₹ 20

www.kewalsach.com

निर्भीकता हमारी पहचान

अगस्त 2022

केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

RNI NO.-BIHHIN/2006/18181, DAVP NO.-129888, POSTAL REG. NO. -PT-35

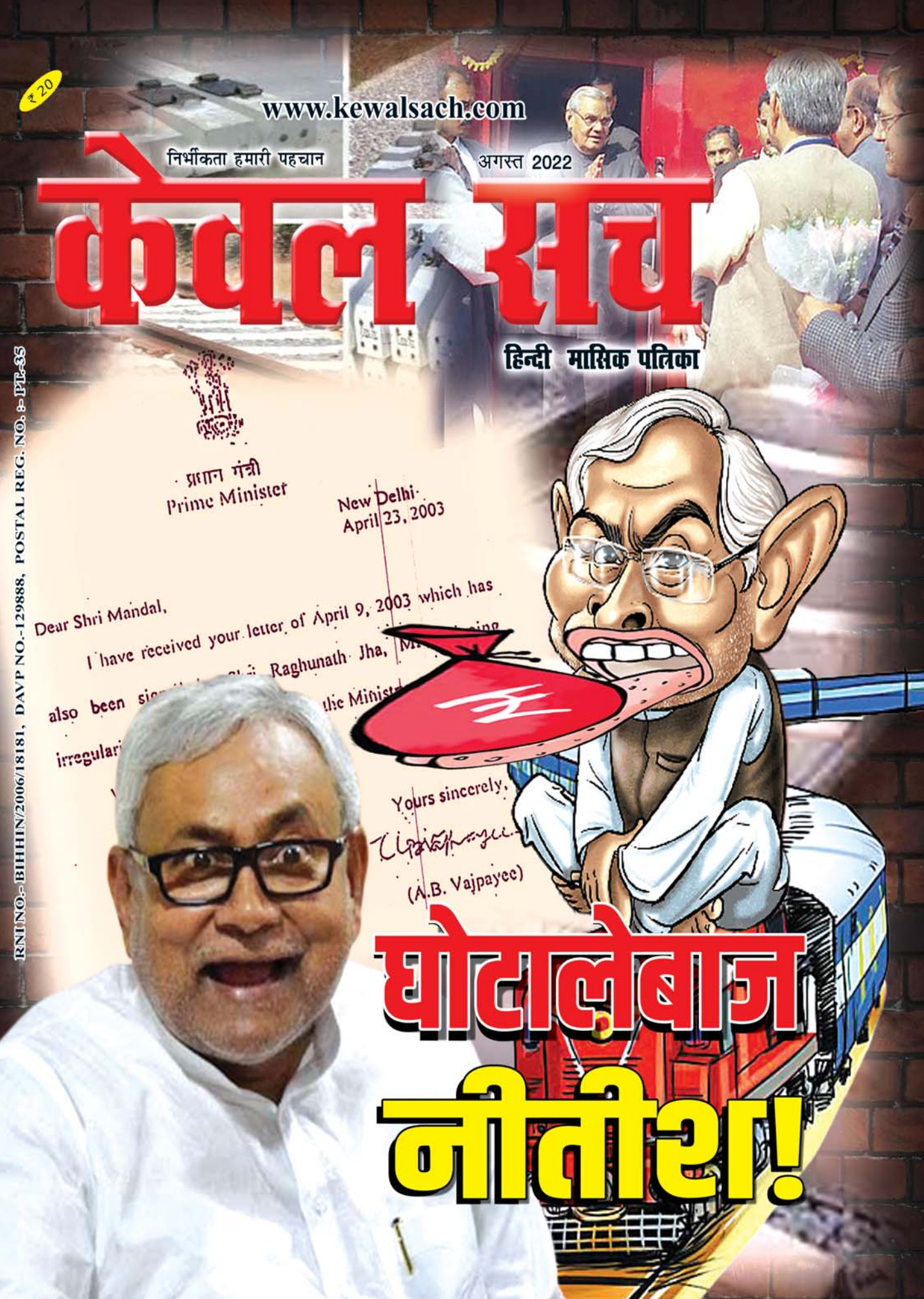

घोटालेबाज नीतीश!

स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षा बंधन की हार्दिक शुभकामनाएँ।

मेथोडिस्ट हॉस्पीटल

प्रताप सागर,

बक्सर-802101 (बिहार)

-: सुविधाएँ :-

सभी सुविधाओं से लैश।

मुफ्त रेलवे पास।

गरीब रोगियों को विशेष छूट।

डॉ0 आर.के. सिंह

जन-जन की आवाज है केवल सच

केवल सच

Kewalachlive.in
वेब पोर्टल न्यूज
24 घंटे आपके साथ

Kewalsach news
जो केवल सच हो

केवल सच TIMES

आत्म-निर्भर बनने वाले युवाओं को सपोर्ट करें

आपका छोटा सहयोग, हमें मजबूती प्रदान करेगा

BHIM UPI
G Pay Paytm

www.kewalsach.com www.kewalsachlive.in

-: सम्पर्क करें :-

पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, मकान संख्या-28/14,
कंकड़बाग, पटना (बिहार)-800020, मो०:-9431073769, 9308815605

Hotel Maurya Patna

Hotel Maurya – Patna is a pioneer project of **Bihar Hotels Limited (BHL).** It is the only **Five Star** category hotel in the State of Bihar with friendly face of affordable luxury. BHL has been successfully operating its Five Star Hotel in Patna since **1978.** Situated in the heart of the city, Patna, the hotel reflects the **historic grandeur** of this city.

Corporate Facilities & Services: Centrally located in the Commercial heart of Patna the Hotel provides Intricately & elegantly designed rooms, Central Air- Conditioning, Direct dialing from rooms with call detail print-out facility, Satellite LED television, Choice of **Seven Convention Halls** of varied capacities, **Heritage rooms** for private dining , **Business Centre, Shopping Arcade, Bank facility, Travel counter, Swimming pool, Safe deposit lockers, Fitness centre & Wi-fi,** all within the hotel premises.

Dining:

- *Vaishali Café* - Walk-in for Breakfast and Business Buffet Lunches. The a-la-carte table offers a multi cuisine and buffet spreads to tinkle those taste buds.
- *Spice Court* – Restaurant serving Indian, Continental, Thai & Chinese cuisine.
- *The Pastry Shop* – Provides all kinds of Baker's confectionery viz; Mouthwatering cakes, Crossiants, Breads, Muffins etc. It also provides free home delivery of cakes of 6 pound onwards.
- *Bollywood Treats*- A matchless meeting point for Munchies, Music, TV shows, Pool Table, Games for kids. Thus, providing Masti not only for adults but also for kids.

Rooms:

- Step into an universe of old world nobility & colonial charm at the spacious VVIP suite of rooms, where your every demand for luxury is met in a manner that's perfected to please. What's more, it's accommodating enough to entertain an entourage of guests. Elegantly designed premium rooms with beautiful interiors and excellent facilities

Total Rooms: 77 – Double: 73, Suites: 04
Credit Cards: Visa, Master, Amex, Bob Cards
Access (in kms): Apt: (07), Rly. Stn.:(01)

बिहार में नये सरकार के नये कैबिनेट के सभी मंत्रियों को हार्दिक शुभकामनाएँ।

क्रमांक	मंत्री का नाम	विभाग
1	श्री नीतीश कुमार, मुख्य मंत्री	1. सामान्य प्रशासन 2. गृह 3. मंत्रिमंडल सचिवालय 4. निगरानी 5. निर्वाचन ऐसे सभी विभाग जो किसी को आवंटित नही है।
2	श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्य मंत्री	1. स्वास्थ्य 2. पथ निर्माण 3. नगर विकास एवं आवास 4. ग्रामीण कार्य
3	श्री विजय कुमार चौधरी	1. वित्त 2. वाणिज्य कर 3. संसदीय कार्य
4	श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव	1. ऊर्जा 2. योजना एवं विकास
5	श्री आलोक कुमार मेहता	राजस्व एवं भूमि सुधार
6	श्री तेज प्रताप यादव	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
7	मो० आफाक आलम	पशु एवं मत्स्य संसाधान
8	श्री अशोक चौधरी	भवन निर्माण
9	श्री श्रवण कुमार	ग्रामीण विकास
10	श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव	सहकारिता
11	डॉ० रामानन्द यादव	खान एवं भूतत्व
12	श्रीमती लेशी सिंह	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण
13	श्री मदन सहनी	समाज कल्याण
14	श्री कुमार सर्वजीत	पर्यटन
15	श्री ललित कुमार यादव	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण
16	श्री संतोष कुमार सुमन	अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण
17	श्री संजय कुमार झा	1. जल संसाधन 2. सूचना एवं जन–संपर्क
18	श्रीमती शीला कुमारी	परिवहन
19	श्री समीर कुमार महासेठ	उद्योग
20	श्री चन्द्र शेखर	शिक्षा
21	श्री सुमित कुमार सिंह	विज्ञान एवं प्रावैधिकी
22	श्री सुनील कुमार	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन
23	श्रीमती अनिता देवी	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण
24	श्री जितेन्द्र कुमार राय	कला, संस्कृति एवं युवा
25	श्री जयन्त राज	लघु जल संसाधन
26	श्री सुधाकर सिंह	कृषि
27	श्री मो० जमा खान	अल्पसंख्यक कल्याण
28	श्री मुरारी प्रसाद गौतम	पंचायती राज
29	श्री कार्तिक कुमार	विधि
30	श्री शमीम अहमद	गन्ना उद्योग
31	श्री शाहनवाज	आपदा प्रबंधन
32	श्री सुरेन्द्र राम	श्रम संसाधन
33	श्री मोहम्मद इसराईल मंसूरी	सूचना प्रावैद्यिकी

निर्भीकता हमारी पहचान

www.kewalsach.com

केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

Regd. Office :-
East Ashok, Nagar, House No.-28/14, Road No.-14, kankarbagh, Patna- 8000 20 (Bihar) Mob.-09431073769,
E-mail :- kewalsach@gmail.com

Corporate Office:-
Riya Plaza, Flat No.-303, Kokar Chowk, Ranchi-834001 (Jharkhand)
Mob.- 09955077308,
E-mail:-
editor.kstimes@rediffmail.com

Delhi Office :-
Sanjay Kumar Sinha
A-68, 1st Floor, Nageshwar talla, Shastri Nagar, New Delhi-110052
Mob.- 09868700991, 09955077308
kewalsach_times@rediffmail.com

Kolkata Office :-
Ajeet Kumar Dube,
131 Chitranjan Avenue, Near- md. Ali Park, Kolkata- 700073 (West Bengal)
Mob.- 09433567880, 09339740757

ADVERTISEMENT RATES PER ISSUE

COLOUR

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE	Qr. PAGE
Cover Page	5,00,000/-	N/A	N/A
Back Page	1,60,000/-	N/A	N/A
Back Inside	1, 00000/-	60,000/-	35000
Back Inner	90,000/-	50,000/-	30000
Middle	1,50,000/-	N/A	N/A
Front Inside	1, 00000/-	60,000/-	40000
Front Inner	90,000/-	50,000/-	30000

B & W

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
Inner Page	60,000/-	35,000/-

1. एक साल के नियमित विज्ञापन पर पत्रिका के वेवसाइट **www.kewalsach.com** के फ्रंट पर भी विज्ञापन निःशुल्क तथा आपका वेवसाइट से सीधा लिंक हो सकता है।
2. एक साल के नियमित विज्ञापन पर 10 प्रतिशत की रियायत।
3. आपके प्रोडक्ट या संगठन के प्रचार-प्रसार हेतु आलेख को उचित स्थान।
4. पत्रिका द्वारा सामाजिक कार्य में आपके संगठन/प्रोडक्ट का बैनर/फ्लैक्स को उचित स्थान देकर आपके संगठन का व्यापक प्रचार-प्रसार।
5. विज्ञापन का भुगतान चेक या आर.टी.जी.एस. से ही मान्य होगा।

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

सरकार

बदलें विचार नहीं

अपनी प्रतिक्रिया हमारे ई-मेल पर दें:- editor.kstimes@rediffmail.com

प्रधानमंत्री बनने के लालच के कारण ही 2010 के बाद से ही नीतीश कुमार चाटुकार नेताओं के बहकावे में आकर या यूं कहें कि अति महत्वाकांक्षी सोच की वजह से 16 जून 2013 को 17 साल पुरानी भाजपा की दोस्ती को तोड़ दिया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में 2 सीट पर सिमट जाने की बदले की आग में नीतीश कुमार ऐसे झुलस गए कि 2013 से 2017 तक उसी दल से दोस्ती करके सरकार चलायी जिसको क्या कुछ नहीं कहते थे लेकिन 2017 में फिर नीतीश कुमार को अपनी गलती का एहसास हुआ और महागठबंधन से रिश्ता तोड़कर बड़े भाई लालू यादव से धोखाधड़ी करके मिट्टी में मिलने के लिए बड़का झूठा पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए। लालू यादव, तेजस्वी-तेज प्रताप यादव ने बेशर्म मुख्यमंत्री तक कहा था और वहीं से इनका नाम सुशासन बाबू से पलटू राम भी हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने भी नीतीश कुमार की कृत्य पर जमकर हमला बोला था। 2017 से 2022 तक नीतीश कुमार भाजपा के साथ मिले सुर मेरा तुम्हारा के तर्ज पर नरेंद्र मोदी के खासम-खास हो गए लेकिन राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रति और प्रधानमंत्री बनने का सपने देखते रहे। उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह ने नीतीश कुमार से आरसीपी सिंह को अलग करके महागठबंधन के साथ सरकार चलाने के लिए रणनीति तैयार की और केंद्र में मंत्री नहीं बनाने का बदला गठबंधन तोड़कर ले लिया। प्रत्येक 5 साल पर चुनाव होता है उसी तर्ज पर नीतीश कुमार ने एक गठबंधन से रिश्ता तोड़ने का और दूसरे से जोड़ने का खेल पहले 2013 में, दूसरी बार 2017 में और अब 2022 में उसी फॉर्मूला को अपनाते हुए 8वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण कर लिया।

मध्यप्रदेश के बाद महाराष्ट्र और बिहार में जिस प्रकार सत्ता का हस्तांतरण हुआ, इससे देश की जनता भी हैरत में है कि जिस प्रकार राजनीति देश के भीतर संचालित हो रही है उससे जनता असमंजस में है की वह किस दल या गठबंधन को वोट करे जो उसके वोट के साथ धोखाधड़ी न करे। बिहार में नीतीश कुमार ने विकास के कई कार्य तो किये लेकिन खुद को सुपरस्टार बनाये रखने के कारण अपनी विलक्षण प्रतिभा पर कलंक भी लगा लिया है। प्रधानमंत्री बनने के लालच के कारण ही 2010 के बाद से ही नीतीश कुमार चाटुकार नेताओं के बहकावे में आकर या यूं कहें कि अतिमहत्वाकांक्षी सोच की वजह से 16 जून 2013 को 17 साल पुरानी भाजपा की दोस्ती को तोड़ दिया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में 2 सीट पर सिमट जाने की बदले की आग में ऐसे झुलस गए कि 2013 से 2017 तक उसी दल से दोस्ती करके सरकार चलायी जिसको क्या कुछ नहीं कहते थे लेकिन 2017 में फिर नीतीश कुमार को अपनी गलती का एहसास हुआ और महागठबंधन से रिश्ता तोड़कर बड़े भाई से धोखाधड़ी करके मिट्टी में मिलने के लिए बड़का झूठा पार्टी में शामिल हो गए। 2017 से 2022 तक नीतीश कुमार भाजपा के साथ मिले सुर मेरा तुम्हारा के तर्ज पर नरेंद्र मोदी के खासम-खास हो गए लेकिन प्रधानमंत्री बनने का सपने देखते रहे। उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह ने नीतीश कुमार से आरसीपी सिंह को अलग करके महागठबंधन के साथ सरकार चलाने के लिए रणनीति तैयार की और केंद्र में मंत्री नहीं बनाने का बदला गठबंधन तोड़कर ले लिया। प्रत्येक 5 साल पर चुनाव होता है उसी तर्ज पर नीतीश कुमार ने एक गठबंधन से रिश्ता तोड़ने का और दूसरे से जोड़ने का खेल पहले 2013 में, दूसरी बार 2017 में और अब 2022 में उसी फार्मूला को अपनाते हुए 8वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण कर ली। लालू यादव चारा घोटाला में जेल भेजने वालों में नीतीश कुमार भी काफी सक्रिय थे क्योंकि विपक्षी नेता की भूमिका में थे लेकिन कभी तेजस्वी यादव ने रेल स्लीपर घोटाला, सृजन घोटाला, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, में मुख्य विपक्षी नेता की भूमिका निभाने में इसलिए विफल रहे या कोशिश नहीं कि की चाचा भी जेल जाए और हम सत्ता से वंचित रह जाएं। नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव को मालूम है कि राजनीति में भाजपा का मुकाबला राजद नहीं कर सकता और पिता के वृद्ध और बीमार होने के साथ पार्टी के भीतर के कलह को भी जानते हैं, वहीं नीतीश कुमार को भी मालूम है कि नरेन्द्र मोदी का मुकाबला अकेले उनके वश का नहीं है और राजद के आड़ में हीं वह भड़ास निकाल सकते हैं। भाजपा भी नीतीश कुमार को राजनीतिक शिकस्त देने के लिए अपनी सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करने से बाज नहीं आएगी और कहीं सुशील कुमार मोदी और मंगल पांडे का बलि देने का मन बनाने में कामयाब हुई तो नीतीश कुमार का न सिर्फ राजनीतिक अंत होगा बल्कि भारत के कलंकित मुख्यमंत्री के रूप में बुढापा जेल में काटने को मजबूर होंगे। फिल्मों में जितनी अभिनेत्रियां कपड़े नहीं बदलती उससे कहीं ज्यादा नीतीश कुमार ने सत्ता/गठबंधन बदला है। उपरोक्त अगर सारे आरोप सच है तो आखिर आम जनता किस नेता व दल पर भरोसा करे। बिहार में पक्ष और विपक्ष बिहार के विकास की बात करती है, विशेष राज्य का दर्जा व जातीय जनगणना की मांग कर एकतरफ बिहार की जनता को गुमराह करती है और दूसरी ओर बिहार को लूट कर अपने अपने परिजनों के लिए अकूत संपत्ति अर्जित करने में लगी है। पक्ष व विपक्ष सिर्फ गांधी ,लोहिया, अंबेडकर व जयप्रकाश के अनुयाई होने का ढोंग कर जनता को गुमराह कर वोट बटोरती है। नीति एवम सिद्धांत की दुहाई देने वाले राजनेता भी कुर्सी के चक्कर में विधायक को करोड़ों रुपये में खरीदते हैं। देश प्रदेश का विकास से अधिक प्राथमिकता सरकार बनाने और सरकारी खजाने की रखवाली के बजाय उसको लूटने की हर संभव कोशिश करते हैं। देश का अधिकांशत: राज्य कर्ज में डूबा हुआ है दूसरी ओर भारतीय रिजर्व बैंक इस गंभीर समस्या से निजात पाने के लिए केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा रहा है कि चुनाव के वक्त जनता से वोट लेने के लिए सरकारी खजाने को रेवड़ी की तरह बांटा जा रहा है जिससे देश की हालत कुछ वर्षों में श्रीलंका-पाकिस्तान जैसी हो जाएगी। आजादी के 75 साल में हीं देश कर्ज में डूब गया है क्योंकि कुर्सी पाने के लिए कोई लैपटॉप, कोई स्कूटी, कोई बिजली तो कोई कोरोना में अनाज ही बांट रहा है परंतु आमजनता व्यक्तिगत हित में वोट करती है जिसकी वजह से राजनेता अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं। आमजनता किसी भी दल को चुने और दूसरे दल को सत्ता से बाहर रखना चाहे लेकिन जनता के साथ धोखाधड़ी करके उसी दल के साथ गठजोड़ करके सरकार बना ले तो जनता के वोट का क्या महत्व बचता है। जनता के वोट का मजाक बनने लगा है जबकि जनता ही मालिक है कि दुहाई दी जाती है परंतु सच तो यही है चुनाव में वोट देने वाला वोटर की स्थिति चुनाव सम्पन्न हो जाने के बाद दूध में गिरी मक्खी के समान हो गया है।

जुलाई 2022

आपको केवल सच पत्रिका कैसी लगी तथा इसमें कौन-कौन सी खामियाँ हैं, अपने सुझाव के साथ हमारा मार्गदर्शन करें। आपका पत्र ही हमारा बल है। हम आपके सलाह को संजीवनी बूटी समझेंगे।

केवल सच

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

हमारा पता है :-

द्वारा:- ब्रजेश मिश्र

पूर्वी अशोक नगर, रोड़ नं.- 14, मकान संख्या- 14/28

कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)

फोन:- 9431073769/ 8340360961/ 9955077308

हमारा ई-मेल

kewalsach@gmail.com, editor.kstimes@rediffmail.com

kewalsach_times@rediffmail.com

उड़ता पंजाब

संपादक जी,

जुलाई 2022 अंक में केवल सच पत्रिका में प्रकाशित धर्मेंद्र सिंह की खबर बिहार का किशनगंज बनता जा रहा उड़ता पंजाब में नशीला पदार्थ की तस्करी और उसके इस्तेमाल करने वालों की संख्या दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है। बिहार सरकार और पुलिस इस पर नकेल कसने के लिए काफी मशक्कत कर रही है परंतु माफियाओं के बढ़ते वर्चस्व के कारण अपराध में भी वृद्धि हो रही है। भ्रष्ट पदाधिकारियों की वजह से भी माफिया युवा पीढ़ी के बीच स्मैक को आसानी से उपलब्ध कराने में कामयाब हो रहे हैं।

✦ **अकरम अली, बस स्टैण्ड, किशनगंज**

जदयू में रंग

ब्रजेश जी,

केवल सच पत्रिका बेबाकी के लिए खास स्थान रखता है। जुलाई 2022 के अंक में बिहार की जदयू पर काफी दमदार खबर "**जदयू में वर्चस्व की जंग**" में ललन सिंह बनाम रामचन्द्र सिंह के बीच की राजनीतिक कलह अब सार्वजनिक होने लगा है। आर सी पी सिंह दावा करते हैं कि मैं खुद राम हूँ, किसी का हनुमान नहीं जबकि ललन सिंह के पीछे अब नीतीश कुमार भी राजनीति कर रहे हैं। जदयू दो खेमो में बंटा हुआ है और यह समय आने पर साफ हो जायेगा तथा खुद एक दूसरे के दामन पर दाग लगाएंगे।

✦ **मनोज सिंह, करमली चक, पटना सिटी**

मिशन 2047

मिश्रा जी,

केवल सच पत्रिका का मैं नियमित पाठक हूँ और इसके सभी खबरों को पढ़ता हूँ और चैनल पर भी देखता हूँ। जुलाई 2022 अंक में भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने को लेकर पटना के फुलवारी शरीफ में पीएफआई का मिशन 2024 का भंडाफोड़ हुआ है। एक बड़ी साजिश का उद्भेदन हुआ है कि पूरी खबर पढ़कर बहुत आक्रोश हुआ तथा यह सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि किस प्रकार भारत के भीतर राष्ट्रद्रोही कार्य हो रहा है। काफी विस्तृत खबर पढ़ने को मिला तथा इसपर हो रही राजनीति को भी समझने का मौका मिला कि नेता कुछ हद तक गिर चुके हैं।

✦ **मनीष सिन्हा, सेक्टर-6, बोकारो, झारखंड**

जल गया भारत

मिश्रा जी,

आपका संपादकीय पढ़ने के बाद मन को तसल्ली मिलती है और जानकारी भी। सरलतापूर्वक अपनी बात को जनमानस के भीतर डालने की अदभुत कला है आपके लेखनी में। जुलाई 2022 अंक के संपादकीय 'नौकरी के नाम पर जल गया भारत ' में आपने मोदी सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर जिस प्रकार आपने खबर को पाठक के बीच रखा है वह काफी मार्मिक एवं राष्ट्रवाद को जीवंत करता है। जिस प्रकार बेरोजगार एवं सरकार परीक्षाफल को लेकर सड़क पर आमने - सामने हैं उससे देश के भीतर कई प्रकार के प्रश्न जन्म ले रहे हैं।

✦ **नारायण चत्रुवेदी, करोलबाग, नई दिल्ली**

कार्यक्रम सम्पन्न

संपादक जी,

जुलाई अंक 2022 में केवल सच, पत्रिका के 17वे स्थापना वर्ष के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की खबर को पढा तथा उसमें प्रकाशित फोटो को भी देखा। कई प्रबुद्ध लोगों के विचार को पढ़ने के साथ पिता की सामाजिक भूमिका को पढकर काफी ऊर्जा का संचार हुआ कि आज के दौर में भी पिता दिवस पर महर्षि सुश्रुत को याद किया जा रहा है। महर्षि सुश्रुत के ऊपर कार्यक्रम में लोगो को सम्मानित होने की खबर से दिल मे केवल सच के प्रति और सम्मान बढ़ा है। शशि रंजन सिंह की कई खबर भ्रष्टाचार को उजागर कर रही है, ऐसी खबरों को प्रकाशित करें।

✦ **मुकेया सहाय, राजा बाजार, जहानाबाद**

अग्निपथ

संपादक जी,

जून 2022 में भारत जिस प्रकार सेना में नौकरी के नाम पर जल गया यह सोचने पर मजबूर कर देता है। केवल सच के जुलाई 2022 अंक में रक्षा मामले के जानकर ललन सिंह की खबर अग्निपथ योजना में सेना के लिए महत्वपूर्ण एवम सामाजिक दृष्टि से आज की जरूरत पर काफी सकरात्मक विषयों को पाठको के बीच रखा है, जो काफी सराहनीय है। झारखंड की पुलिस की खबरों के साथ - साथ राजनीतिक एवं विभाग में फैले भ्रष्टाचार पर भी केंद्रित करना चाहिए। केवल सच की खबरों में सच्चाई रहती है इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है

✦ **पंकज श्रीवास्तव, चूड़ी बाजार, लखनउ**

अन्दर के पन्नों में

RNI No.- BIHHIN/2006/18181, DAVP No.- 129888

समृद्ध भारत

खुशहाल भारत

निर्भीकता हमारी पहचान

केवल सच

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

वर्ष:- 17,	अंक:- 195,	माह:- अगस्त 2022,	मूल्य:- 20/- रू

फाउंडर

स्व० गोपाल मिश्र

संपादक

ब्रजेश मिश्र

9431073769 8340360961

editor.kstimes@rediffmail.com

kewalsach@gmail.com

प्रप्रधान संपादक

सच्चिदानन्द मिश्र 9934899917

सुरजीत तिवारी 9431222619

ललन कुमार प्रसाद 9334107607

संपादकीय सलाहकार

अमिताभ रंजन मिश्र 9430888060, 8873004350

अमोद कुमार 9431075402

महाप्रबंधक

त्रिलोकी नाथ प्रसाद 9308815605, 9122003000

triloki.kewalsach@gmail.com

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

पूनम जयसवाल 9430000482, 9798874154

रीता सिंह 7004100454, 9308729879

मनीष कुमार कमलिया 9934964551, 8809888819

उपसंपादक

अरबिन्द मिश्रा 9934227532, 9576438501

प्रसुन्न पुष्कर 9430826922, 7004808186

ब्रजेश सहाय 7488696914

ललन कुमार 9430243587, 9334813587

अजित कुमार त्रिपाठी 9430826676, 9294942868

आलोक कुमार सिंह 8409746883

संयुक्त संपादक

अमित कुमार 'गुड्डू' 9905244479, 7979075212

amit.kewalsach@gmail.com

राजीव कुमार शुक्ला 9430049782, 7488290565

कृष्ण कुमार सिंह 6209194719, 7909077239

काशीनाथ गिरी 9905048751, 9431644829

प्रदीप कुमार सिन्हा 9472589853, 6204674225

.

सहायक संपादक

शशि रंजन सिंह 8210772610, 9431253179

मिथिलेश कुमार 9934021022, 9431410833

नवेन्दु कुमार मिश्र 9570029800, 9199732994

संजीव रंजन तिवारी 9430915909

संदीप स्नेह 9971679857, 9667977987

रामपाल प्रसाद वर्मा 9939086809, 7079501106

समाचार प्रबंधक

सुधीर कुमार मिश्र 9608010907

ब्यूरो-इन-चीफ

संकेत कुमार झा 9386901616, 7762089203

बिनय भूषण झा 9473035808, 8229070426.

.

विधि सलाहकार

शिवानन्द गिरि 9308454485

रवि कुमार पाण्डेय 9507712014

चीफ क्राइम ब्यूरो

आनन्द प्रकाश 9508451204, 8409462970

कुमार सौरभ 7004381748, 9102366629

गगन कुमार मिश्र 8210810032, 9835585560

साज-सज्जा प्रबंधक

अमित कुमार 9905244479

कार्यालय संवाददाता

सोनू यादव 8002647553, 9060359115

प्रसार प्रतिनिधि

कुणाल कुमार 9905203164

बिहार प्रदेश जिला ब्यूरो

पटना (श०):- श्रीधर पाण्डेय 09470709185

(म०):-

(ग्रा०) :-

बाढ़ :-

भोजपुर :- गुड्डू कुमार सिंह 8789291547

बक्सर :- बिन्ध्याचल सिंह 8935909034

कैमूर :-

रोहतास :- अशोक कुमार सिंह 7739706506

:-

गया (श०) :- सुमित कुमार मिश्र 7667482916

(ग्रा०) :-

औरंगाबाद :-

जहानाबाद :- नवीन कुमार रौशन 9934039939

अरवल :- संतोष कुमार मिश्रा 9934248543

नालन्दा :-

:-

नवादा :- अमित कुमार 9934706928

:-

मुंगेर :-

लखीसराय :-

शेखपुरा :-

बेगूसराय :- निलेश कुमार 9113384406

:-

खगड़िया :-

समस्तीपुर :-

जमुई :- अजय कुमार 09430030594

वैशाली :-

:-

छपरा :-

सिवान :-

:-

गोपालगंज :-

:-

मुजफ्फरपुर :- .

:-

सीतामढ़ी :-

शिवहर :-

बेतिया :- रवि रंजन मिश्रा 9801447649

बगहा :-

मोतिहारी :-

दरभंगा :-

:-

मधुबनी :- सुरेश प्रसाद गुप्ता 9939817141

:-

सहरसा :-

मधेपुरा :-

सुपौल :-

किशनगंज :-

:-

अररिया :- अब्दुल कय्यूम 9934276870

पूर्णिया :-

कटिहार :-

भागलपुर, :-

(ग्रा०):- रवि पाण्डेय 7033040570

नवगछिया :-

दिल्ली कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- संजय कुमार सिन्हा
A-68, 1st Floor,
नागेश्वर तल्ला, शास्त्रीनगर, न्यू
दिल्ली-110052
संजय कुमार सिन्हा, स्टेट हेड
मो०- 9868700991, 9431073769

उत्तरप्रदेश कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
....., स्टेट हेड

सम्पर्क करें

9308815605

पश्चिम बंगाल कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- अजीत कुमार दुबे
131 चितरंजन एवेन्यू,
कोलकात्ता, पश्चिम बंगाल- 700073
अजीत कुमार दुबे, स्टेट हेड
मो०- 9433567880, 9308815605

मध्य प्रदेश कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
हाउस नं.-28, हरसद्धि कैम्पस
खुशीपुर, चांबड़
भोपाल, मध्य प्रदेश- 462010
अभिषेक कुमार पाठक, स्टेट हेड
मो०- 8109932505,

झारखंड कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
नियर- न्यू छोटानागपुर स्कूल
बरियातु रोड, राँची- 834001
....., स्टेट हेड
मो०- 6206889040, 9431073769

छत्तीसगढ़ कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,

....., स्टेट हेड

सम्पर्क करें

8340360961

संपादकीय व प्रधान कार्यालय:-

☞ पूर्वी अशोक नगर, रोड नं:-14, मकान संख्या:- 28/14, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार) मो०- 9431073769, 9955077308

☞ e-mail:- kewalsach@gmail.com, ditor.kstimes@rediffmail.com kewalsach_times@rediffmail.com

☞ स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक ब्रजेश मिश्र द्वारा सांध्य प्रवक्ता खबर वर्क्स, ए- 17, वाटिका विहार (आनन्द विहार), अम्बेडकर पथ, पटना 8000 14(बिहार) एवं पूर्वी अशोक नगर, रोड नं. 14, कंकड़बाग पटना-800020 से प्रकाशित, संपादक- ब्रजेश मिश्र। RNI NO.-BIHHIN/2006/18181

☞ पत्रिका में प्रकाशित समाचारों से संपादक की सहमति आवश्यक नहीं है।

☞ सभी प्रकार के वाद-विवादों का निपटारा पटना न्यायालय के अधीन होगा।

☞ आलेख पर कोई आपत्ति हो तो एक महीने के भीतर खंडन करें।

☞ किसी भी लेख के लिए रचनाकार/लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

☞ सभी पद अवैतनिक हैं।

☞ फोटो-समाचार साभार भी (माध्यम- इंटरनेट एवं अन्य स्त्रोत)

☞ कोई भी शिकायत हमारे पते पर लिखकर भेजें।

☞ **विज्ञापन का भुगतान चेक या ड्राफ्ट एवं RTGS से ही मान्य होगा।**

☞ भुगतान Kewal Sach को ही करें। प्रतिनिधियों को नगद न दें।

☞ A/C No. :- 0600050004768
BANK :- Punjab National Bank
IFSC Code :- PUNB0060020
PAN No. :- AAJFK0065A

झारखण्ड स्टेट ब्यूरो

ब्रजेश कुमार मिश्र 9431950636, 9631490205

उप संपादक

अजय कुमार 6203723995

.....

झारखण्ड सहायक संपादक

ब्रजेश मिश्रा 7654122344, 7979769647

अभिजीत दीप 7004274675, 9430192929

संयुक्त संपादक

.....

.....

.....

.....

.....

झारखण्ड प्रदेश जिला ब्यूरो

राँची	:-	अभिषेक मिश्र	09431732481
साहेबगंज	:-	अनंत मोहन यादव	09546624444
खूँटी	:-		
जमशेदपुर	:-		
हजारीबाग	:-		
जामताड़ा	:-		
दुमका	:-		
देवघर	:-		
धनबाद	:-		
बोकारो	:-		
रामगढ़	:-		
चाईबासा	:-		
कोडरमा	:-		
गिरीडीह	:-		
चतरा	:-		
लातेहार	:-	रविकांत पासवान	09801637947
गोड्डा	:-		
गुमला	:-		
पलामू	:-		
गढ़वा	:-		
पाकुड़	:-		
सरायकेला	:-		
सिमडेगा	:-		
लोहरदगा	:-		

श्री चन्द्र प्रकाश सिंह

प्रधान संरक्षक सह प्रबंध संपादक
'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**
राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक)
पूर्व निदेशक सदस्य, ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
09431016951, 09334110654

श्री सज्जन कुमार सुरेका

मुख्य संरक्षक
'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**
डी- 402 राजेन्द्र विहार, फॉरेस्ट पार्क
भुवनेश्वर- 751009 मो-09437029875

सुधीर कुमार

मुख्य संरक्षक सह निदेशक ''**मगध इंटरनेशनल स्कूल**'' टेकारी
'' **केवल सच** '' पत्रिका **एवं** '' **केवल सच टाइम्स** ''
9060148110
sudhir4s14@gmail.com

श्री आर के झा

मुख्य संरक्षक
'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**
EX. CGM, (Engg.) N.B.C.C
08877663300

देवब्रत्त कुमार गणेश

मुख्य संरक्षक सह भावी प्रत्याशी, 53 ठाकुरगंज विधानसभा
'' **केवल सच** '' पत्रिका **एवं** '' **केवल सच टाइम्स** ''
8986196502/9304877184
devbartkumar15@gmail.com

बिहार राज्य प्रमंडल ब्यूरो

पटना		
मगध		
सारण		
तिरहुत		
पूर्णिया	**धर्मेन्द्र सिंह**	9430230000 7004119966
भागलपुर		
मुंगेर		
दरभंगा		
कोशी		

विशेष प्रतिनिधि

आशुतोष कुमार	9430202335, 9304441800
सागर कुमार	9155378519, 8863014673
सुमित राज यादव	9472110940, 8987123161
बेंकटेश कुमार	8521308428, 9572796847
रामउदय यादव	8862858305, 9709409232
राजीव नयन	9973120511, 9430255401
लक्ष्मी नारायण सिंह	9204090774
मणिभूषण तिवारी	9693498852
राजीव रंजन	9431657626
दीपनारायण सिंह	9934292882
आनन्द प्रकाश पाण्डेय	9931202352, 7808496247
अनु कुमारी	9471715038, 7542026482
रामजीवन साहू	9430279411, 7250065417
रंजीत कुमार सिन्हा	9931783240, 7033394824
विनित कुमार	8210591866, 8969722700
कुणाल कुमार सिंह	9988447877, 9472213899

छायाकार

त्रिलोकी नाथ प्रसाद	9122003000, 9431096964
मुकेश कुमार	9835054762, 9304377779
जय प्रसाद	9386899670,
कृष्णा प्रसाद	9608084774, 9835829947

MIS Executive/DEO/MIS बहाली प्रक्रिया में घोर अनियमितताएं

● सागर कुमार

जिस जीविका परियोजना का गुणगान बिहार के मुख्यमंत्री श्री नितीश कुमार हर सभा में करते है और जो जीविका उनका सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिन जीविका दिदियों के वोट बैंक के दम पर वह चुनाव जीते थे , उसी जीविका की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले स्तंभ यानि MIS थीम में जीविका अधिकारियों द्वारा किया गया पूरा करतूत, उनका काला चिठ्ठा आपको विस्तार पूर्वक बता रहे है। बिहार में जीविका की शुरुआत 2007 में 6 जिलों के 18 प्रखंडों से हुई। और उसके कुछ दिनों बाद 2010 में MIS Executive@DEO (Data Entry Operator) की बहाली के लिए श्रीमणि नाम की एक एजेंसी को हायर किया गया। उस समय 7 से 8 जिलों में ही MIS Eñecutive@DEO (Data Entry Operator) की बहाली ''श्री मणि'' एजेंसी के द्वारा लिखित परीक्षा, शॉर्ट लिस्ट और इंटरव्यू की प्रक्रिया को अपनाकर किया गया। यहां तक तो सब ठीक था परंतु जीविका के अधिकारियों ने एजेंसी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को ठीक ढंग से पेमेंट नहीं दिया। यूं कहें कि श्री मणि एजेंसी ने कई महीनों तक पेमेंट लटका कर रखा और अंततोगत्वा पेमेंट नहीं दिया और कई लोगों को निकाल भी दिया। एक्शन लेते हुए 2012 में श्रीमणि एजेंसी को जीविका से हटा दिया गया और 2012 से 2015 तक जीविका अपने एचआर मैनुअल (HR & Manual) के हिसाब से उनके जरूरत के हिसाब से जिला लेवल पर डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर (DPM) के अंदर MIS Eñecutive@DEO (Data Entry Operator) की भर्ती लिखित परीक्षा, शॉर्टलिस्ट और इंटरव्यू के आधार पर की। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एग्जाम इतना चर्चित हुआ कि इस पूरे एग्जाम की प्रक्रिया का वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें गलती क्या है, यहां तक तो सब ठीक है। जी हां साहब यहां तक तो सब ठीक था लेकिन जब हमने इसकी पड़ताल की तो पाया कि जीविका के एचआर मैनुअल कैटिगरी 3तक में MIS Eñecutive@DEO (Data Entry Operator) जिक्र है परंतु जीविका ने उसके अनुसार आज तक इस पद के लिए कोई भी बहाली नहीं निकाली बल्कि जीविका के अधिकारी अपने एचआर मैनुअल को ताक पर रखकर MIS Executive पद की बहाली केवल और केवल ऑफिस ऑर्डर निकालकर की। कहते हैं ना कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं तो इसका जीता जागता उदाहरण है एसपीएम एमआईएस प्रेम प्रकाश। हुआ यह की 2020 में जीविका के अधिकारियों ने बहुत ही सावधानी से चुपके से अपने एचआर मैनुअल के कैटेगरी - 3 में बदलाव करके वहां से क्म्० पोस्ट को ही हटा दिया।

दिनांक 06 /08/2015 को एक ऑफिस ऑर्डर BRLPS/Project/197/10/1286 निकाला गया जिस पर तात्कालिक OSD

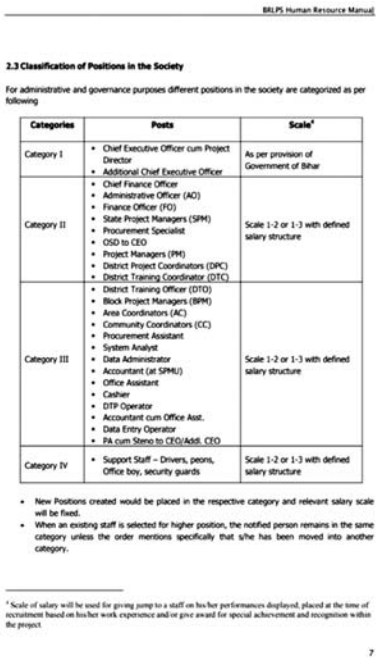

BRLPS Human Resource Manual

2.3 Classification of Positions in the Society

For administrative and governance purposes different positions in the society are categorized as per following

Categories	Posts	Scale*
Category I	• Chief Executive Officer cum Project Director • Additional Chief Executive Officer	As per provision of Government of Bihar
Category II	• Chief Finance Officer • Administrative Officer (AO) • Finance Officer (FO) • State Project Managers (SPM) • Procurement Specialist • OSD to CEO • Project Managers (PM) • District Project Coordinators (DPC) • District Training Coordinator (DTC)	Scale 1-2 or 1-3 with defined salary structure
Category III	• District Training Officer (DTO) • Block Project Managers (BPM) • Area Coordinators (AC) • Community Coordinators (CC) • Procurement Assistant • System Analyst • Data Administrator • Accountant (at SPMU) • Office Assistant • Cashier • DTP Operator • Accountant cum Office Asst. • Data Entry Operator • PA cum Steno to CEO/Addl. CEO	Scale 1-2 or 1-3 with defined salary structure
Category IV	• Support Staff – Drivers, peons, Office boy, security guards	Scale 1-2 or 1-3 with defined salary structure

- New Positions created would be placed in the respective category and relevant salary scale will be fixed.
- When an existing staff is selected for higher position, the notified person remains in the same category unless the order mentions specifically that s/he has been moved into another category.

* Scale of salary will be used for giving jump to a staff on his/her performances displayed, placed at the time of recruitment based on his/her work experience and/or give award for special achievement and recognition within the project.

7

2.3 Classification of Positions in the Society

For administrative and governance purposes different positions in the society are categorized as per following

Categories	Posts	Scale*
Category I	• Chief Executive Officer cum State Mission Director • Additional Chief Executive Officer	As per provision of Government of Bihar
Category II	• Director • Program Coordinator • OSD to CEO • Chief Finance Officer • Administrative Officer (AO) • Finance Officer (FO) • State Finance Manager • Assistant Finance Manager • State Project Managers (SPM) • Procurement Specialist • Procurement Officer • Project Managers (PM) • District Project Manager (DPM) • Manager - IBCB	Scale 1-2 or 1-3with defined salary structure
Category III	• Thematic Managers/FM • Young Professionals • Project Associate • Training Officer (TO) • Block Project Managers (BPM) • Area Coordinators (AC) • Community Coordinators (CC) • Livelihoods Specialist • Procurement Associate • System Analyst • Data Administrator • DTP Operator cum Designer • IT Associate • Logistic Assistant • Office Assistant(at SPMU, DPCU/BPIU) • Accountant (at SPMU, DPCU/BPIU) • Cashier • Store Keeper • PA cum Steno to CEO/Addl. CEO	Scale 1-2 or 1-3with defined salary structure

- New positions created would be placed in the respective category and relevant salary scale will be fixed.

* Scale of salary will be used for giving jump to a staff on his/her performances displayed, placed at the time of recruitment based on his/her work experience and/or give award for special achievement and recognition within the project.

एचआर मेनुअल 2020 से पहले एवं 2020 के बाद

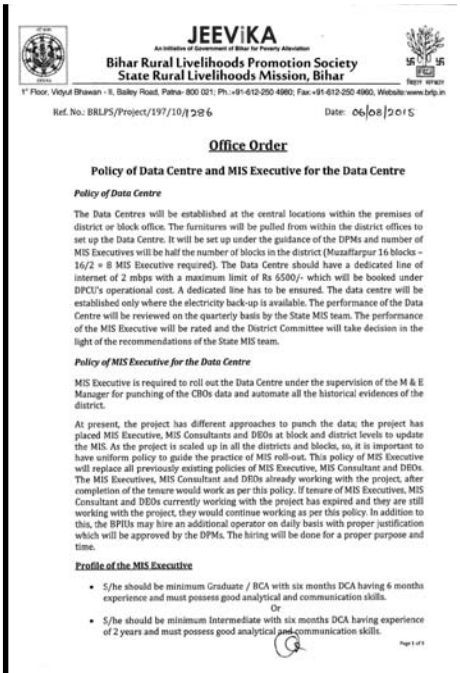

JEEViKA
An Initiative of Government of Bihar for Poverty Alleviation
Bihar Rural Livelihoods Promotion Society
State Rural Livelihoods Mission, Bihar

1st Floor, Vidyut Bhawan - II, Bailey Road, Patna- 800 021; Ph.:+91-612-250 4980; Fax:+91-612-250 4960, Website:www.brlp.in

Ref. No.: BRLPS/Project/197/10/1286 Date: 06/08/2015

Office Order

Policy of Data Centre and MIS Executive for the Data Centre

Policy of Data Centre

The Data Centres will be established at the central locations within the premises of district or block office. The furnitures will be pulled from within the district offices to set up the Data Centre. It will be set up under the guidance of the DPMs and number of MIS Executives will be half the number of blocks in the district (Muzaffarpur 16 blocks – 16/2 = 8 MIS Executive required). The Data Centre should have a dedicated line of internet of 2 mbps with a maximum limit of Rs 6500/- which will be booked under DPCU's operational cost. A dedicated line has to be ensured. The data centre will be established only where the electricity back-up is available. The performance of the Data Centre will be reviewed on the quarterly basis by the State MIS team. The performance of the MIS Executive will be rated and the District Committee will take decision in the light of the recommendations of the State MIS team.

Policy of MIS Executive for the Data Centre

MIS Executive is required to roll out the Data Centre under the supervision of the M & E Manager for punching of the CBOs data and automate all the historical evidences of the district.

At present, the project has different approaches to punch the data; the project has placed MIS Executive, MIS Consultants and DEOs at block and district levels to update the MIS. As the project is scaled up in all the districts and blocks, so, it is important to have uniform policy to guide the practice of MIS roll-out. This policy of MIS Executive will replace all previously existing policies of MIS Executive, MIS Consultant and DEOs. The MIS Executives, MIS Consultant and DEOs already working with the project, after completion of the tenure would work as per this policy. If tenure of MIS Executives, MIS Consultant and DEOs currently working with the project has expired and they are still working with the project, they would continue working as per this policy. In addition to this, the BPIUs may hire an additional operator on daily basis with proper justification which will be approved by the DPMs. The hiring will be done for a proper purpose and time.

Profile of the MIS Executive

- S/he should be minimum Graduate / BCA with six months DCA having 6 months experience and must possess good analytical and communication skills.

  Or
- S/he should be minimum Intermediate with six months DCA having experience of 2 years and must possess good analytical and communication skills.

Page 1 of 3

ऑफिस ऑर्डर

ब्रजकिशोर पाठक का साइन था। इस ऑफिस ऑर्डर के अनुसार MIS Executive/DEO (Data Entry Operator)/Consultant पद अस्तित्व में आया। और इस की बहाली प्रत्येक जिलों के प्रखंडों के संख्या के आधे पदों पर MIS Executive, जरूरत पड़ने पर DEO/Consultant की बहाली करना तय किया गया। उसके बाद 29–नवम्बर वर्ष–2017 में एक कार्यालय आदेश (BRLPS/proj/497/14/vol–3/3454) आया। जिसमें स्पष्ट किया गया था की सभी जिले के सभी प्रखंडो में अब MIS Executive/DEO का बहाली करना है, इसी पत्र के अनुसार सभी प्रखंडो में MIS executive/DEO का बहाली भी कर लिया गया, और परियोजना का कार्य भी बेहतर तरीके से चल रहा था इसी बिच फिर न जाने ऐसा क्या हुआ की दिनांक 11/6/ 2020 को पुनः तात्कालिक ओएसडी ब्रजकिशोर पाठक के साइन से ऑफिस ऑर्डर BRLPS/Proj&MIS/1527/19/600 निकाला गया। जिसमें MIS Eñecutive/DEO (Data Entry Operator) पद, सभी जिलों के सभी प्रखंडों में एक साथ खत्म कर दिया गया और उनकी अंतिम तिथि 30/6 /2020 दे दी गई। ये फरमान एकदम समझ के परे था। साथ में इस फरमान में यह बताया गया था कि अब नई बहाली को पुनः एजेंसी के द्वारा किया जाएगा। अब आप यह सोचिए कि यदि आप कहीं जॉब कर रहे हैं आप का परिवार बाल बच्चा सब उसी नौकरी पर निर्भर है और बिना कोई शिकायत के , बिना कोई कारण के ,अचानक से एक लेटर निकलता है और कहा जाता है कि कुछ दिनों बाद आपको इस जॉब से निकाल दिया जाएगा और फिर इसी पोस्ट पर नई बहाली एजेंसी के द्वारा कराई जाएगी तो आप सोच कर देखिए कि जिस नौकरी को पाने के लिए आपने कई तरह के एग्जाम पास किए और उसके बाद तन मन लगाकर पूरी निष्ठा के साथ काम किया और जीविका को बिहार में पहचान दिलाई और अब उनके अधिकारी इन लोगों को जीविका से लात मारकर बाहर निकाल रहे हैं तो इन्हें कैसा लग रहा होगा।

JEEViKA
Rural Development Department, Government of Bihar
Bihar Rural Livelihoods Promotion Society
State Rural Livelihoods Mission, Bihar

Vidyut Bhawan - II, Bailey Road, Patna- 800 021; Ph.:+91-612-250 4980; Fax:+91-612-250 4960, Website:www.brlps.in

Ref:BRLPS/Proj-MIS/1527/19/ 600 Date: 11-06-2020

To,

All DPMs,

Bihar Rural Livelihoods Promotion Society

Subject: Regarding deployment of Data Entry Operators by agency

Working tenure of presently serving MIS Executives/ Data Entry Operators would expire on 30.06.2020 for the blocks mentioned in the enclosure. Such MIS Executives/ DEOs would be required to serve notice period as provided in office order BRLPS/Project/197/10/1286 dated 06.08.2015.

It is worth mentioning that now onwards, DEOs have to be hired from the agency which would shortly provide the list of selected DEOs for the blocks mentioned in the enclosure, which would be shared with you. DEOs provided by the agency would be deployed in the districts and period of commencement of their deployment would be 01.07.2020.

By the order of CEO

11/6/2020

(B.K. Pathak)
Officer on Special Duty

Encl.: List of blocks

Copy to:

1. Director, OSD, All PCs, CFO, AO
2. All SPMs, PS, SFMs, PMs, AFMs
3. All DPMs, M&E Managers
4. IT Section

क्या यह नियमपूर्वक या न्याय संगत लग रहा है और क्या इसमें बड़े भ्रष्टाचार की बू नहीं आ रही है। जीविका अपने MIS executive को जो वेतन देता था उससे लगभग दुगने वेतन एजेंसी के क्म० को जीविका ने दिया, न जाने ऐसी क्या बिपत्ति थी की जो कार्य 8000 – 9000 में होता था उसी कार्य के लिए 13000–14000की अतिरिक्त राशी खर्च किया जाए। प्रत्येक प्रखंड के लिए 4000–5000 रुपया अधिक खर्च हो रहा था। अब पुरे 387 प्रखंड में एजेंसी से DEO का चयन हुआ अब आप खुद ही देख लीजिये कितने रूपए का

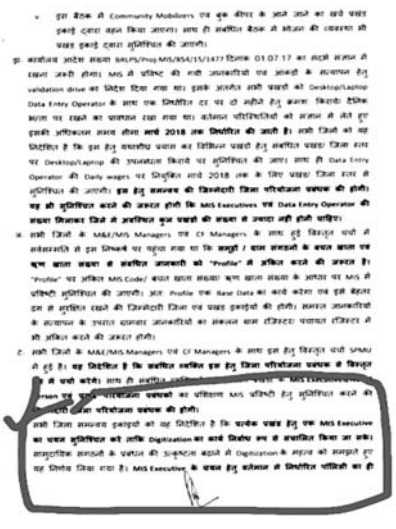

Gmail

Regarding Interview for Data Entry Operator in the District of Bhojpur,Baxar,Rothas,Samastipur,West Champaran,Saharsha,Supaul,and Madhepura,

G.A. Digital Web Word Pvt. LTD.

Check List for Recruitment/Taken over on our roll.

Dear Candidate,

You have to submit the following papers for Recruitment or taken over on our Roll.

1. Resume with Signature
2. Cancel chequeof Bank where salary has to be credited
3. Pan Card Copy(In Duplicate)
4. Adhar card copy(In Duplicate) With full Date of Birth
5. 5 small Photo
6. Qualification (Intermediate and DCA 6 Months)
7. Experience(01 Year Experience as Data Entry Operator)
8. Stamp Paper of Rs. 100/- in your Name and undertaking typed and signed by them.
9. Police verification Report

G.A. Digital Web Word Pvt. LTD.
4th Floor ,Keshav park ,Piller NO-80
Near Durga Ashram ,Bailley Road ,
Patna-800014

जी.ए. डिजीटल का मेल

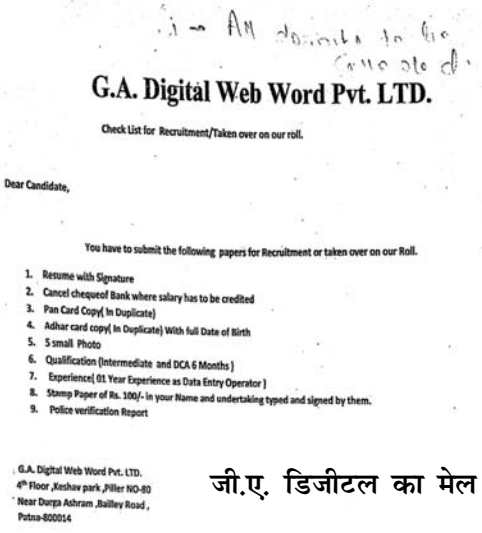

वित्तीय हानि हुआ। जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो बीच में एक एजेंसी के द्वारा बहाली करवाना क्यों जरूरी है , इसका जवाब जीविका को और खास कर इस सेक्शन के जीविका के सबसे बड़े अधिकारी SPM-MIS (राज्य परियोजना प्रबन्धक–मैनेजमेंट इनफार्मेशन सिस्टम) प्रेम प्रकाश को ही देना चाहिए।

आज तक हम सवाल पूछते रहे लेकिन जीविका के एक अधिकारी जवाब देने का नाम नहीं लेता है इससे स्पष्ट रूप से जग जाहिर हो जाता है कि जीविका के अधिकारियों के पॉकेट एजेंसियों के द्वारा दिए गए पैसों से गर्म है। आगे बढ़ते हैं और आगे की प्रक्रिया आपको समझाते हैं। अब इन लोगों का खेल समझिए। सर्वप्रथम दिनांक 01 फरवरी 2020 दिन शनिवार को रात के 9:33 बजे 5 जिलों के MIS/Executive/DEO (Data Entry Operator) को राकेश कुमार (HR GA Digital Web World. LTD.) के नाम से एक मेल आया। मेल में क्या लिखा था हम बाद में बताएंगे लेकिन अभी देखिए इन लोगों का खेल की जिन लोगों को मेल किया गया उनको उस दिन के पहले तक है। GA Digital के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और शनिवार के रात में उनको मेल किया जाता है और उस के दूसरे दिन अर्थात 2 फरवरी 2020 के दिन रविवार सुबह के 9:34 पर जीविका के SPM - MIS प्रेम प्रकाश जी का मेल सभी DPM को भेजा जाता है ASPM-MIS के मेल में साफ साफ जिक्र था की एजेंसी BTDP - NRETP प्रखंडो के लिए है फिर भी एजेंसी NRLM प्रखंड के लड़के को पटना मेल करके बुलाया इस सम्बन्ध में SPM-MIS प्रेम प्रकाश की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। दोनों मेल में यह जानकारी दी गई थी कि जीविका में मैन पावर देने हेतु एक प्राइवेट एजेंसी को हायर किया गया है जिसका नाम है GA Digital Web World PVT. LTD. और इस मेल के माध्यम से ही यह कहा गया कि आप सभी लोगों का इंटरव्यू 03 फरवरी 2020, 04 फरवरी 2020 अर्थात सोमवार और मंगलवार को होगा। अब इनकी मनसा और इनका कारनामा देखिए।

उपरोक्त जो मेल अभ्यर्थियों को भेजे गए उनमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पुलिस वेरीफिकेशन रिपोर्ट मांगा गया जिसको बनाने में लगभग 10 से 15 दिन लगते हैं और इसकी जानकारी उन लोगों को केवल1 दिन पहले वह भी शनिवार को रात में दी गई। लेकिन फिर भी जॉब जाने के डर से सभी अभ्यर्थी टाइम से पटना के बेली रोड स्थित है। डिजिटल के ऑफिस में पहुंचे। पहले तो वो कार्यालय किसी दुसरे के नाम से रजिस्टर्ड था, जिसका नाम था सौम्या एजुकेशनल हब, अब सौम्या एजुकेशनल हब और है। GA Digital का आपस में क्या सम्बन्ध है ये जीविका अधिकारी ही बेहतर समझाएंगे।

एजेंसी सेलेक्ट करने के लिए जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाया गया था उसमें प्रेम प्रकाश जी ने साफ–साफ लिखा था कि जिस भी कंपनी को जीविका में Man-power सप्लाई का काम दिया जाए उसका खुद का ऑफिस बिहार में होना चाहिए लेकिन जिस समय है। GA Digital को जीविका में यह काम मिला जिस समय GA Digital का बिहार में अपना खुद का कोई ऑफिस नहीं था बल्कि सौम्या एजुकेशनल हब के ऑफिस में है। GA Digital अपना ऑफिस चला रही थी और वहीं पर सभी अभ्यर्थियों का टाइपिंग टेस्ट ली थी। लेकिन जब यह मुद्दा थोड़ा हाइलाइटेड हो गया और विवाद में पड़ गया तब बिहार में उसी जगह पर GA Digital का ऑफिस खुल पाया। सवाल यह उठता है कि जब उस समय GA Digital का अपना बिहार में ऑफिस नहीं था तो प्रेम प्रकाश जी ने किस बेसिस पर GA Digital को ही

Section VII – Activity Schedule 62

Section VII - Activity Schedule

Terms of Reference

Hiring of Agency to provide Services for Data Entry Work

(i) Background

Bihar Rural Livelihoods Project (BRLPS) is designed by Government of Bihar to address rural poverty in Bihar. Besides state government and central government, the World Bank is also extending financial assistance to this project. The project aims at enhancing social and economic empowerment of the rural poor by creating self-managed community institutions and enhancing income through sustainable livelihoods generation. Currently, JEEVIKA is implementing three projects named as BTDP, NRLP and NRLM covering 534 blocks with support from staff and cadres spread across the state.

The data capturing in MIS requires establishment and streamlining of Decision Support System (DSS) in BRLPS (JEEVIKA) across state. The kind of effort put in has resulted in successfully capturing of the voluminous legacy data in the system as well as the current data on some indicators. In this activity, most important stakeholders are the MIS Executives/Data Entry Operators (DEOs) who perform data entry. Data entry includes data entry of CBO profiles and financial transactional data of VOs and CLFs. As on date, profiles of more than 8 lakh SHGs, more than 50 thousand VOs and more than 800 CLFs have been digitized. The data entry or digitization of CBOs' profiles and their financial transactions at the block/district level is a continuous process. This will allow to maintain current data in the MIS system and will help the management in proper decision making as well as in carrying out reviews at all levels. In addition, the real time digitization of the CLF/VO transaction data would require reinforcement of the existing IT Infrastructure and man power at block and district level offices.

The digitization work in BRLPS is increasing significantly as several mobile apps and portal based data entry from different themes has increased and is also being rolled out across state i.e. all 534 blocks. The data entry in all the applications will be a continuous process and will help in sharing of information in timely manner with accuracy. In order to facilitate effective planning, monitoring & implementation at grass root levels, it is necessary to take the MIS down to the sub-district/block level and even at panchayat level by using mobile apps. This will reduce the manual work, streamline the operation, and hence increase efficiency in proper monitoring vis-a-vis the productivity even at district/block level offices. In this regard, BRLPS proposes to hire services for effectively running setting up Block Data centers in all the blocks of 32 districts of Bihar.

pg. 1

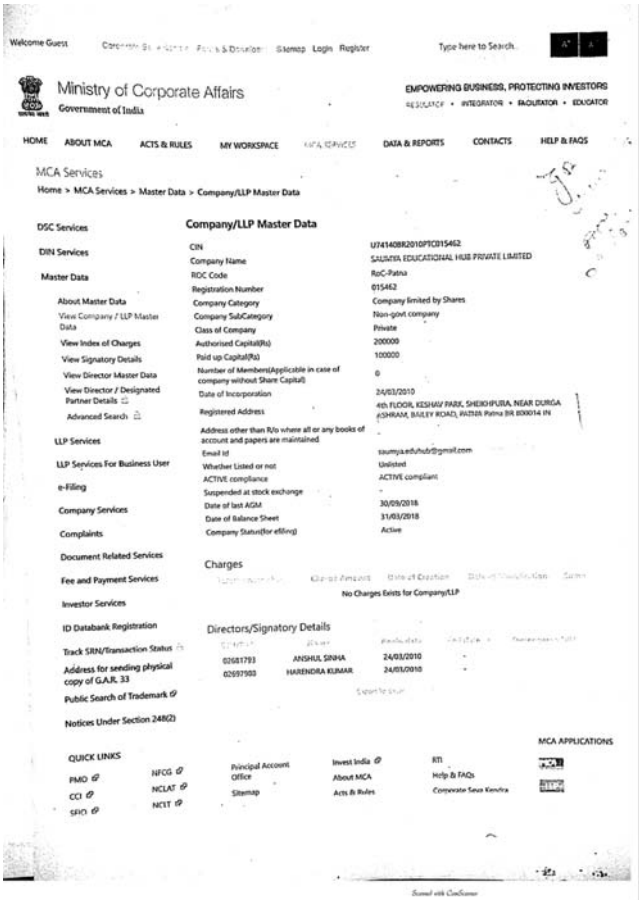

Welcome Guest · Corporate Seva Kendra · Forms & Downloads · Sitemap · Login · Register · Type here to Search

Ministry of Corporate Affairs
Government of India

EMPOWERING BUSINESS, PROTECTING INVESTORS
REGULATOR • INTEGRATOR • FACILITATOR • EDUCATOR

HOME · ABOUT MCA · ACTS & RULES · MY WORKSPACE · MCA SERVICES · DATA & REPORTS · CONTACTS · HELP & FAQS

MCA Services
Home > MCA Services > Master Data > Company/LLP Master Data

DSC Services · DIN Services · Master Data (About Master Data, View Company / LLP Master Data, View Index of Charges, View Signatory Details, View Director Master Data, View Director / Designated Partner Details, Advanced Search) · LLP Services · LLP Services For Business User · e-Filing · Company Services · Complaints · Document Related Services · Fee and Payment Services · Investor Services · ID Databank Registration · Track SRN/Transaction Status · Address for sending physical copy of G.A.R. 33 · Public Search of Trademark · Notices Under Section 248(2)

Company/LLP Master Data

CIN	U74140BR2010PTC015462
Company Name	SAUMYA EDUCATIONAL HUB PRIVATE LIMITED
ROC Code	RoC-Patna
Registration Number	015462
Company Category	Company limited by Shares
Company SubCategory	Non-govt company
Class of Company	Private
Authorised Capital(Rs)	200000
Paid up Capital(Rs)	100000
Number of Members(Applicable in case of company without Share Capital)	0
Date of Incorporation	24/03/2010
Registered Address	4th FLOOR, KESHAV PARK, SHEIKHPURA, NEAR DURGA ASHRAM, BAILEY ROAD, PATNA Patna BR 800014 IN
Address other than R/o where all or any books of account and papers are maintained	-
Email Id	saumya.eduhub@gmail.com
Whether Listed or not	Unlisted
ACTIVE compliance	ACTIVE compliant
Suspended at stock exchange	-
Date of last AGM	30/09/2018
Date of Balance Sheet	31/03/2018
Company Status(for efiling)	Active

Charges

No Charges Exists for Company/LLP

Directors/Signatory Details

DIN/PAN	Name	Begin date	End date	Surrendered DIN
02681793	ANSHUL SINHA	24/03/2010	-	
02697903	HARENDRA KUMAR	24/03/2010	-	

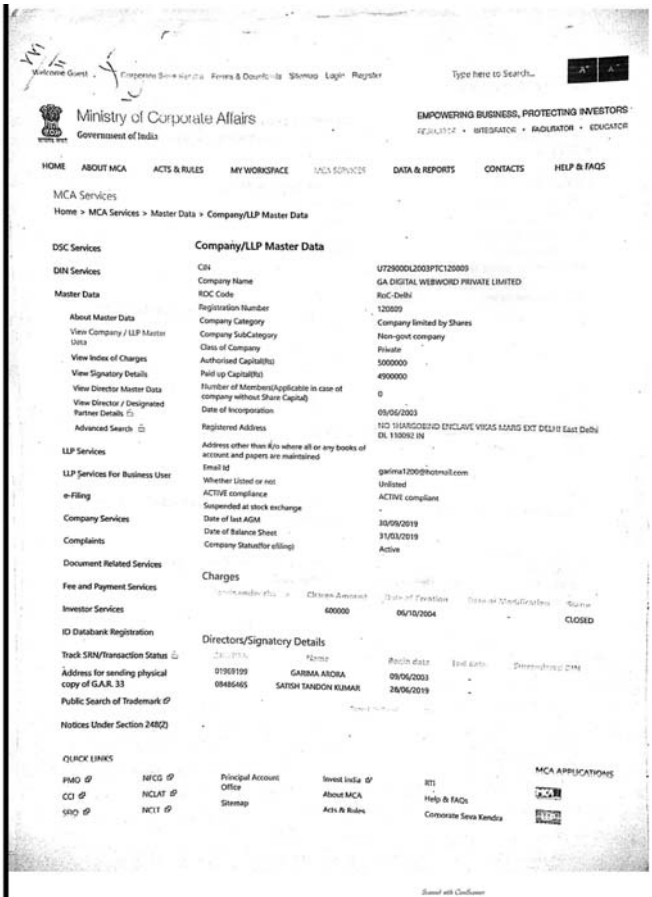

QUICK LINKS: PMO · CCI · SFIO · NFCG · NCLAT · NCLT · Principal Account Office · Sitemap · Invest India · About MCA · Acts & Rules · RTI · Help & FAQs · Corporate Seva Kendra · MCA APPLICATIONS

Welcome Guest · Corporate Seva Kendra · Forms & Downloads · Sitemap · Login · Register · Type here to Search

Ministry of Corporate Affairs
Government of India

EMPOWERING BUSINESS, PROTECTING INVESTORS
REGULATOR • INTEGRATOR • FACILITATOR • EDUCATOR

HOME · ABOUT MCA · ACTS & RULES · MY WORKSPACE · MCA SERVICES · DATA & REPORTS · CONTACTS · HELP & FAQS

MCA Services
Home > MCA Services > Master Data > Company/LLP Master Data

Company/LLP Master Data

CIN	U72900DL2003PTC120009
Company Name	GA DIGITAL WEBWORD PRIVATE LIMITED
ROC Code	RoC-Delhi
Registration Number	120009
Company Category	Company limited by Shares
Company SubCategory	Non-govt company
Class of Company	Private
Authorised Capital(Rs)	5000000
Paid up Capital(Rs)	4900000
Number of Members(Applicable in case of company without Share Capital)	0
Date of Incorporation	09/06/2003
Registered Address	NO 1HARGOBIND ENCLAVE VIKAS MARG EXT DELHI East Delhi DL 110092 IN
Address other than R/o where all or any books of account and papers are maintained	
Email Id	garima1200@hotmail.com
Whether Listed or not	Unlisted
ACTIVE compliance	ACTIVE compliant
Suspended at stock exchange	-
Date of last AGM	30/09/2019
Date of Balance Sheet	31/03/2019
Company Status(for efiling)	Active

Charges

Assets under charge	Charge Amount	Date of Creation	Date of Modification	Status
	600000	06/10/2004	-	CLOSED

Directors/Signatory Details

DIN/PAN	Name	Begin date	End date	Surrendered DIN
01969199	GARIMA ARORA	09/06/2003	-	
08486465	SATISH TANDON KUMAR	26/06/2019	-	

QUICK LINKS: PMO · CCI · SFIO · NFCG · NCLAT · NCLT · Principal Account Office · Sitemap · Invest India · About MCA · Acts & Rules · RTI · Help & FAQs · Corporate Seva Kendra · MCA APPLICATIONS

सौम्या एजुकेशनल हब प्राइवेट लि० एवं जी.ए. डिजीटल वेब वर्ल्ड प्रा०लि० का रजिस्ट्रेशन

मैनपावर सप्लाई का कार्य दिया। कार्य दिया भी तो उसका नोटिफिकेशन या उसका एडवर्टाइजमेंट किस जगह पर प्रकाशित किया यह जवाब प्रेम प्रकाश जी को और जीविका को देना चाहिए। वहां पर GA Digital Web World PVT LTD ने काफी अनमने ढंग से उनकी टाइपिंग टेस्ट कराई और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया और सबको Orally केवल मुंह से ही बोल कर भगा दिया कि आप लोगों को टाइपिंग नहीं आता है आप लोग घर जाइए। दिनांक-03-02-2020 एवं 04-02-2020 को जो जीविका वाले MIS Executive/DEO एजेंसी में interview के लिए गए थे उनसब को एजेंसी बोला की आप फेल कर गए जिसका कोई लिखित प्रमाण भी नहीं मिला। अभ्यर्थियों ने एजेंसी से टाइपिंग रिपोर्ट या टाइपिंग लेटर की मांग की फिर भी एजेंसी वाले उन लोगों की एक न सुनी और उन्हें वहां से निकाल दिया। उसी समय 4 फरवरी 2020 को उन सभी अभ्यर्थियों ने जीविका के तात्कालिक CEO- IAS बाला मुरुगन डी से मुलाकात की और उक्त एजेंसी की लिखित शिकायत की। लेकिन तत्कालीन CEO बाला मुरुगन कोई करवाई नहीं की।

अब यहां पर एक खबर सामने कर आती है कि सूत्रों के अनुसार एजें Digital Web World PVT L1 जीविका से काम लेने के लिए जीविका के अधिकारियों को मोटी रकम दी है और उस रकम की भरपाई और ज्यादा मुनाफा के लिए एजेंसी ने जीविका में मैनपावर बहाली में बिहार के आम अभ्यर्थियों से लाखों रुपए लिए हैं खैर इस के स्पष्ट प्रमाण तो हमारे पास नहीं हैं परंतु जिला द्वारा जहाँ पर भी एजेंसी द्वारा भेजे गए लडको की जब जांच परीक्षा आयोजित किया गया उसमें निकल कर आया की लगभग सभी का बहाली संदेह के घेरे में है।

बहरहाल, इसी प्रकार से पूरे बिहार के सभी जिलों में कार्य कर रहे MIS Executive/DEO को अयोग्य घोषित कर दिया गया और हल्ला हंगामा

दिनांक 18/02/2021 को आयोजित Data Entry Operators (GA Digital Pvt. Ltd.) के समीक्षा बैठक की कार्यवाही।

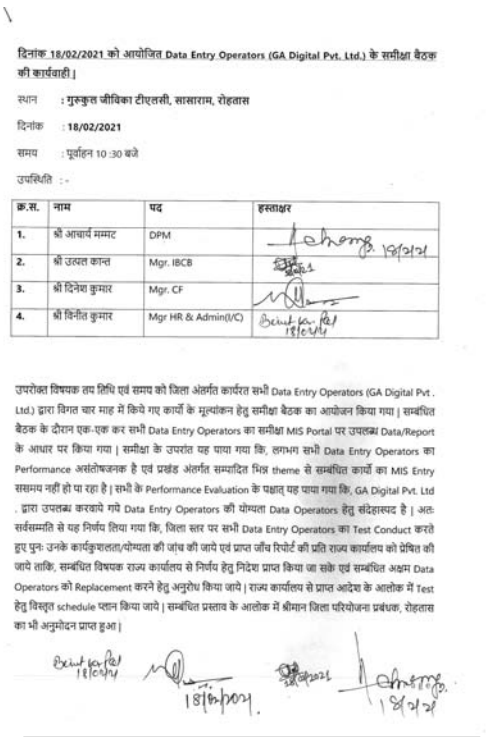

स्थान : गुरूकुल जीविका टीएलसी, सासाराम, रोहतास

दिनांक : 18/02/2021

समय : पूर्वाहन 10 :30 बजे

उपस्थिति : -

क्र.स.	नाम	पद	हस्ताक्षर
1.	श्री आचार्य मम्मट	DPM	18/2/21
2.	श्री उत्पल कान्त	Mgr. IBCB	
3.	श्री दिनेश कुमार	Mgr. CF	
4.	श्री विनीत कुमार	Mgr HR & Admin(I/C)	18/02/21

उपरोक्त विषयक तय तिथि एवं समय को जिला अंतर्गत कार्यरत सभी Data Entry Operators (GA Digital Pvt . Ltd.) द्वारा विगत चार माह में किये गए कार्यों के मूल्यांकन हेतु समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। सम्बंधित बैठक के दौरान एक-एक कर सभी Data Entry Operators का समीक्षा MIS Portal पर उपलब्ध Data/Report के आधार पर किया गया। समीक्षा के उपरांत यह पाया गया कि, लगभग सभी Data Entry Operators का Performance असंतोषजनक है एवं प्रखंड अंतर्गत सम्पादित भिन्न theme से सम्बंधित कार्यों का MIS Entry ससमय नहीं हो पा रहा है। सभी के Performance Evaluation के पश्चात् यह पाया गया कि, GA Digital Pvt. Ltd . द्वारा उपलब्ध करवाये गये Data Entry Operators की योग्यता Data Operators हेतु संदेहास्पद है। अतः सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि, जिला स्तर पर सभी Data Entry Operators का Test Conduct करते हुए पुनः उनके कार्यकुशलता/योग्यता की जांच की जाये एवं प्राप्त जाँच रिपोर्ट की प्रति राज्य कार्यालय को प्रेषित की जाये ताकि, सम्बंधित विषयक राज्य कार्यालय से निर्णय हेतु निदेश प्राप्त किया जा सके एवं सम्बंधित अक्षम Data Operators को Replacement करने हेतु अनुरोध किया जाये। राज्य कार्यालय से प्राप्त आदेश के आलोक में Test हेतु विस्तृत schedule प्लान किया जाये। सम्बंधित प्रस्ताव के आलोक में श्रीमान जिला परियोजना प्रबंधक, रोहतास का भी अनुमोदन प्राप्त हुआ।

18/02/21 · 18/02/2021 · 18/2/2021 · 18/2/21

केवल सच का SPM-MIS प्रेम प्रकाश से सवाल

☞ जीविका में MIS एग्जीक्यूटिव की बहाली सबसे पहले कब की गई?

☞ पूर्व से कार्यरत MIS Executive/ DEO के जगह एजेन्सी से DEO की बहाली करने की जरुरत अचानक क्यों पड़ी?

☞ जीविका के जिस कार्य को चयनित MIS Executive/DEO 8500 Rs के मानदेय पर ज्वाइन कर के अब 7 साल के बाद भी सिर्फ 9000–10000 के मामूली रुपये पर कार्य रहे थे तो एजेंसी को 16000 रू० देकर DEO रखने की जरुरत क्यों पड़ी?

☞ एजेंसी को Man Power सप्लाई के लिए चयन करने का आधार क्या बनाया गया था? जबकि उस समय तक GA Digital Web World PVT LTD का पटना और बिहार में कोई खुद का ऑफिस नहीं था।

☞ एजेंसी के द्वारा बहाली प्रक्रिया के लिए विज्ञापन कब और किस पोर्टल पर प्रकाशित किया गया?

☞ पुनः 2 साल तक एजेंसी से कार्य लेने के बाद अचानक उसे भी दरकिनार करने की क्या वजह है ?

☞ अब जीविका द्वारा CLF से MIS Executive की बहाली करने का प्रावधान क्या है और इसकी जरुरत क्यों पड़ी?

☞ संकुल स्तरीय संघ क्या है और यह कैसे कार्य करता तो? इसमें कार्यरत कर्मी किसके कर्मी कहलाते तो?

☞ संकुल स्तरीय संघ अगर स्वतंत्र संस्था है तो इसमें जीविका के कर्मी की सहभागिता की जरुरत क्यों पड़ती है?

☞ अगर संकुल स्तरीय संघ स्वतंत्र संस्था नहीं है तो MIS Executive की बहाली उस वक्त क्यों करायी जा रही जब इसके विरुद्ध पुराने लोग माननीय पटना उच्च न्यायालय में केस दर्ज किए है।

☞ संकुल स्तरीय संघ में काम करने के लिए बहाली संकुल स्तरीय संघ के द्वारा ही किया जाता है तो सिर्फ MIS Executive/DEO पद के लिए प्रखंड कार्यालय से लेकर राज्य कार्यालय तक के कर्मी क्यों हस्तक्षेप करते दिख रहे हैं ऐसा क्यों?

☞ संकुल स्तरीय संघ का क्षेत्र सिमित होते हुए भी एक ही MIS से सभी CLF और प्रखंड के कार्यो को करने के लिए निर्देशित करने का क्या प्रावधान है?

☞ क्या संकुल स्तरीय संघ की दिदिया MIS एंट्री जैसे टेक्निकल कार्य के लिए MIS Executive का चयन करने में सक्षम हैं?

☞ HR मैन्युअल में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद रहते हुए भी आपने क्यों MIS Executive का अलग से बहाली करवाया और कार्यालय आदेश संख्या 1286 के अनुसार जो MIS Executive/DEO जीविका मे कार्य कर रहे हैं वो आउटसोर्स कैसे हुए? जबकि कार्यालय आदेश संख्या 1286 मे आउटसोर्स तौर पर बहाली का कोई जिक्र नहीं ?

☞ जीविका द्वारा सभी कर्मी एवं कैडर का वेतन/मानदेय का वृद्धि हुआ लेकिन सिर्फ MIS Executive इससे वंचित रहे ऐसा क्यों ?

☞ अचानक से आपने Terms of Reference को क्यों बदल दिया ?

☞ MIS Executive/ DEO का PF और ESIC क्यों नहीं कटता है और क्यों नहीं इस पद पर नियुक्त महिलाओं को मातृत्व अवकाश (ML leave) एवं बिशेष अवकाश(Special Leave) मिल पाता है। जबकि बाकी जीविका कर्मियों को यह सब सुविधाएं मिलती हैं।

करने पर एक दो लोगों का चयन भी कर लिया गया। जब जीविका अधिकारियो के मनमानी से MIS Executive तंग आ गए तब जाकर उन्होंने पटना उच्च न्यायलय में इन्साफ की गुहार लगाई पटना उच्च न्यायलय के अंतिम फैसला अभी आना शेष है किन्तु तब तक यथा स्थिति बनाए रखने की पटना उच्च न्यायलय ने आदेश जारी किया। इसी बिच एक और फरमान जारी किया गया की अब MIS Executive की बहाली CLF संकुल स्तरीय संघ के द्वारा की जाएगी,जो संकुल स्तरीय संघ खुद एक स्वतंत्र संस्था होती है और व्यवहारिक रूप से औसतन देखा जाए तो उसके अध्यक्ष, सचिव कम पढ़े लिखे होते हैं और कुछ लोग तो अनपढ़ भी है। उनको जिम्मेदारी दिया गया की कंप्यूटर चलाने वाले टेक्नीकल रूप से सशक्त लड़के लड़कियों का वो लोग चयन करे। अब इसके पीछे भी बड़ा

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
Civil Writ Jurisdiction Case No.9928 of 2020

Miritunjay Kumar

... ... Petitioner/s

Versus

The State of Bihar

... ... Respondent/s

Appearance :
For the Petitioner/s : Mr.Shashi Shekhar Tiwary
For the Respondent/s : Mr.Lalit Kishore (Ag)

CORAM: HONOURABLE MR. JUSTICE MOHIT KUMAR SHAH
ORAL ORDER

3 26-03-2021 The respondents are directed to file counter affidavit within four weeks from today.

List this case after four weeks.

In the meantime, *status quo* shall be maintained *qua* the service conditions of the petitioners herein.

(Mohit Kumar Shah, J)

rinkee/-

U

I/21374/2022

File No.BRLPS/Proj-M&E/827/15 244

JEEViKA
Bihar Rural Livelihoods Promotion Society
State Rural Livelihoods Mission, Bihar

Office Order

Hiring of MIS Executives through CLF Policy in Districts

Vide office order BRLPS/Proj-MIS/1527/20/3696 dated 02.03.2021, BRLPS/Proj-MIS/854/15/776 dated 03.06.2019 and BRLPS/Proj-MIS/1527/19/5229 dated 19.03.2020, the hiring process of MIS Executives of all NRLM, NRETP and BTDP blocks through CLF policy has already been communicated. In continuation to office order BRLPS/Proj-MIS/827/15/I/14152/2021 dated 09.12.2021, the compliance has to be done as given below:

Sl. No.	Activities	Timeline
1	Identification of CLF for hiring of MIS Executives	11th April, 2022
2	Selection process to be initiated (Advertisement, etc.)	18th April, 2022
3	Selection process to be completed (Shortlisting, interview, typing test, result declaration, etc.)	15th June, 2022
4	Document verification before joining	25th June, 2022
5	Work to be started by newly selected MIS Executives	1st July, 2022

In reference to the above activities, the following directions are given:

a) Extension is given to MIS Executives in all blocks of 32 districts till 30th June, 2022.
b) Extension is given to GA Digital till 30th June, 2022 to provide DEOs as per the contract.
c) 32 BTDP districts will hire the MIS Executives through CLF policy for all the blocks.
d) The payment of honorarium to MIS Executives is to be done through concerned CLF/ nodal VO.
e) All the documents are to be properly maintained at respective BPIUs and CLF level for future reference.
f) It is important to maintain transparency in the entire process by DPM and will ensure that the hiring process is completed within the above mentioned timeline.

बालामुरूगन डी

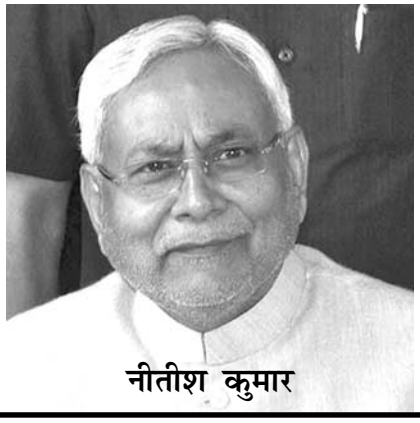
नीतीश कुमार

राहुल कुमार

खेल है। इसमें सिर्फ नाम सीधी साधी अध्यक्ष या सचिव का है असल में तो सारा मलाई जीविका अधिकारी खा रहे है क्योंकि संकुल स्तरीय संघ CLF के द्वारा ली गई परीक्षा में भी अनियमितता बहुत हुई है। और इस बहाली प्रक्रिया में संकुल स्तरीय संघ का केवल नाम होता है बल्कि पर्दे के पीछे से जीविका के बड़े अधिकारी ही इसमें निर्णयकर्ता होते हैं। उनके आज्ञा पर संकुल स्तरीय संघ में कोई भी बहाली हो पाती है। आज भी MIS Executive@DEO 9000-10000 Rs पर पुरे माह अपना पसीना बहा कर जीविका को डिजिटल की दुनिया में शिखर पर पंहुचा रहे हैं परन्तु MIS Executive/DEO द्वारा किये उनके कार्यो को प्रोत्साहित करने के बजाय SPM-MIS अपना जेब गर्म करने में लगे है। इन सभी प्रकरण में मुख्य रूप से चउ-उपे प्रेम प्रकाश शक के दायरे में आते हैं क्योंकि अगर आपने परियोजना के हित में कुछ अच्छा किया है तो आप खुलकर मीडिया को बताते। हम किसी भी सवाल को लेकर आपके पास जाते हैं तो आप मिलने से मना कर देते हैं । किसी बात का जवाब नहीं देते हैं। आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिस वजह से आप मीडिया के सवालों से बच रहे हैं या फिर जिन लोगों को आप जॉब से हटा रहे हैं उनको भी स्पष्ट जानकारी नहीं दे रहे हैं उनको भी आप बरगला रहे हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं यह जवाब आपको देना चाहिए।

मुख्यमंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव, जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को अनगिनत मेल/पत्र लिखने के बाद भी SPM-MIS लगातार बच रहे है, फिर भी माननीय मुख्य मंत्री कहते नहीं थकते की जीविका में कोई भ्रष्टाचार नहीं होता। सर जी ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है । अब तो सरकार भी बदल गई है और आपके मन

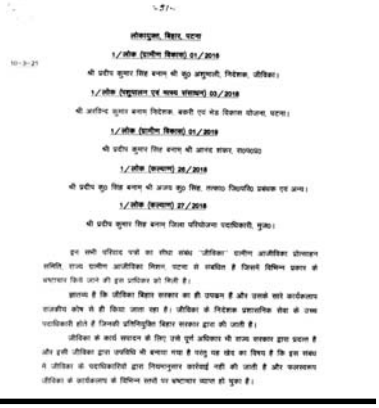

मुताबिक सरकार बन गई है। आपसे गुजारिश करेंगे की थोडा समय निकाल कर अपने महत्वकांक्षी परियोजना का असलियत भी तो देख लीजिये। क्योंकि बिहार लोकायुक्त ने भी यह माना है कि जीविका के कार्यकलापों के विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार व्याप्त हो चुका है और हमने भी अभी तक के अध्ययनों के आधार पर यह माना है कि जीविका एक सुनियोजित लूट है क्योंकि अगर आप जीविका के SHG, VO और CLF के बुक्स ऑफ रिकॉर्ड का ठीक ढंग से अध्ययन करेंगे तो आपको इस हकीकत का पता चल पाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी, ग्रामीण विकास विभाग के माननीय मंत्री जी प्रधान सचिव जी और जीविका के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री राहुल कुमार जी अगर आपको इतना ही भरोसा है अपने अधिकारियों पर और लगता है कि जीविका में भ्रष्टाचार नहीं है और मीडिया झूठ का ही आप पर सवाल उठा रही है तो हम आपसे बहुत ही विनम्रता पूर्वक एक आग्रह करेंगे कि आप एक बार जीविका के सभी SHG, VO और CLF के Books of Record का Audit CAG (Comptroller and Auditor General of India) से करा लें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसके बाद फिर कभी भी केवल सच जीविका के बारे में कुछ भी नहीं लिखेगा। लेकिन ऐसा होने की संभावना बहुत ही कम है क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो जीविका के अधिकतर अधिकारी जेल में होंगे।

खैर, हम हर बार जीविका में फैले भ्रष्टाचार और बिहार सरकार के अन्य विभागों में फैले हुए तमाम भ्रष्टाचार को लगातार उठाते रहेंगे और अगर आप भी हमारे इस मुहिम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं आपकी पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी, देश हित में, बिहार हित में अगर आपका जमीर जिंदा है तो जुड़े हमारे साथ और इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ युद्ध का आगाज करें। ●

Data Entry Operator के जाँच परिणाम की सूची

DEO का नाम	प्रखण्ड	Basic Computer Test	Typing Test			Performance
			Percentage %	Hindi	English	
शैल कुमारी	अकोढ़ीगोला	46	46%	3	10	Fail
विनोद कुमार	चेनारी	74	74%	26	28	Pass
सोनिया खातून	दावथ	86	86%	25	32	Pass
मनोहर कुमार	डेहरी	58	58%	15	20	Fail
कुमारी रश्मि तिवारी	डी.पी.सी. यू.	88	88%	23	25	Pass
महेश कुमार शर्मा	करगहर	28	28%	9	26	Fail
अमन कुमार	कोचस	50	50%	1	22	Fail
सुमन कुमारी	नासरीगंज	34	34%	27	38	Fail
मिथिलेश कुमार	राजपुर	92	92%	26	27	Pass
सुजीत कुमार	रोहतास	68	68%	24	32	Pass
ज्योति कुमारी	संझौली	42	42%	13	16	Fail
सतवंत कुमार	सासाराम	42	42%	12	15	Fail
रंगीता कुमारी	शिवसागर	48	48%	14	18	Fail
रेशमा परवीन	सुरजपुरा	88	88%	22	32	Pass
छोटन कुमार	तिलौथू	86	86%	30	39	Pass
दुर्गा कुमार	बिक्रमगंज	40	40%	0	5	Fail

8वीं बार नीतीश कुमार

● **अमित कुमार**

'8वीं बार, नीतीश कुमार'।

सर्वविदित है कि वर्ष 2000 फिर 2005 से लेकर 2022 तक मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार का साथ छोड़ने का नाम नहीं ले रही और आज एक बार फिर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल या यूं कहे महागठबंधन (राजद, कांग्रेस, हम, माले, सीपीआई, सीपीएम) के साथ पुनः सरकार बनाते हुए राजभवन में महामहिम राज्यपाल फगु चौहान के समक्ष पद एवं गोपनियता का शपथ लेते हुए 8वीं बार मुख्यमंत्री बनाये गये। सनद् रहे कि 9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार के इस्तीफा देने और महागठबंधन के समर्थन से नई सरकार बनाने का दावा पेश करने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल हो गई। ज्ञात हो कि नीतीश कुमार ने पहली बार 2000 में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, जब उन्होंने केवल एक सप्ताह तक चलने वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार का नेतृत्व किया था। राजग गठबंधन के 2005 में विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल करने के बाद उन्होंने एक बार फिर मुख्यमंत्री पद

संभाला। इसके बाद 2010 में राजग ने पांच साल बाद विधानसभा चुनाव में उनके नेतृत्व में शानदार जीत हासिल की और नीतीश कुमार तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। किन्तु 2014 में लोकसभा चुनाव में जदयू की हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया था, लेकिन एक साल से भी कम समय में उन्होंने पुनः वापसी की और उन्होंने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 2015 में नीतीश कुमार राजद और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाकर विधानसभा चुनाव में आरामदायक बहुमत हासिल कर मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने जुलाई 2017 में राजद के साथ असंगत मतभेदों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था। हालांकि, 24 घंटे से भी कम समय में फिर से मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण कर उन्होंने भाजपा के साथ एक नई सरकार बनाई। कुमार ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नवंबर में सातवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और आज फिर से राजद एवं महागठबंधन के साथ मिलकर राज्यपाल के समक्ष बहुमत साबित करते हुए सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा और 10 अगस्त 2022 को 8वीं बार पद एवं गोपनियता

की शपथ खाते हुए मुख्यमंत्री बने।

गौरतलब है कि बीजेपी से नाता तोड़ना हो या जोड़ना या फिर आरजेडी के साथ आना और उससे अलग होना, नीतीश के लिए ये कोई नई बात नहीं है। पिछले करीब तीन दशक के दौरान बीजेपी और आरजेडी के साथ नीतीश के रिश्ते कई बार बने और बिगड़े हैं। यूं कहें कि पिछले करीब तीन दशकों में कम से कम 4 बार नीतीश का हृदय परिवर्तन हो चुका है। बीजेपी और आरजेडी से गठबंधन तोड़ने के लिए नीतीश का दो चर्चित फॉर्मूला रहा है-कम्युनलिज्म या सांप्रदायिकता, जिसे नीतीश बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। वहीं दूसरा है करप्शन, जिसका इस्तेमाल वे आरजेडी से गठबंधन तोड़ने के लिए कर चुके हैं। नीतीश कुमार के करीब चार दशक लंबे राजनीतिक करियर में उन्होंने पांच बार पाला बदला है। इस दौरान उनके ऊपर लालू प्रसाद यादव के अलावा जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव जैसे नेताओं को किनारे लगाने का आरोप लगा। नीतीश की इन हरकतों के कारण ही राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने उन्हें 'पलटूराम' की संज्ञा दी थी।

ज्ञात हो कि 1 मार्च 1951 को बिहार के बख्तियारपुर में जन्मे नीतीश कुमार ने 1972 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी। एक इंटरव्यू में नीतीश ने कहा था कि उन्होंने अधूरे मन से स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की नौकरी ज्वाइन की, लेकिन पहला ही दिन उनका आखिरी दिन साबित हुआ, क्योंकि शुरू से ही उनका मन राजनीति में लगता था। अपनी राजनीति के शुरुआती दिनों में उन्होंने राममनोहर लोहिया, एस.एन. सिन्हा, कर्पूरी ठाकुर और वी.पी. सिंह जैसे दिग्गज नेताओं के साथ काम किया। 1985 में वह सत्येंद्र नारायण सिन्हा की अध्यक्षता वाले जनता दल से जुड़े और इसी साल पार्टी के टिकट पर हरनौत से विधायक चुने गए। जनता दल में अपने शुरुआती वर्षों में नीतीश कुमार ने 1989 में बिहार विधानसभा में लालू प्रसाद यादव को विपक्ष का नेता के तौरपर समर्थन किया था। नीतीश और लालू एक-दूसरे को कॉलेज के दिनों से ही जानते थे। बाद में दोनों ही जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जुड़े थे। मार्च 1990 में लालू प्रसाद यादव जब बिहार के पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तो उसमें नीतीश कुमार ने अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन लालू से उनकी ये दोस्ती ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। 1994 में नीतीश ने लालू के खिलाफ बगावत कर दी। इसकी वजह ये थी कि उन दिनों जनता दल पर लालू का नियंत्रण था। लालू का साथ छोड़ नीतीश ने जॉर्ज फर्नांडीस के साथ मिलकर समता पार्टी का गठन किया था। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही बिहार की राजनीति में सबसे चर्चित किस्सों में रही है। इसके बाद नीतीश ने 1996 में पहली बार बीजेपी से हाथ मिलाया और अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। उसी साल जनता दल

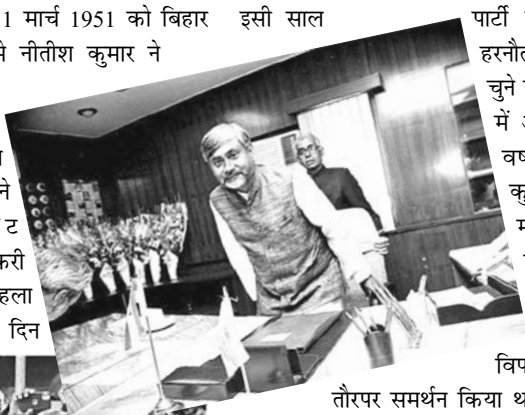

अध्यक्ष शरद यादव और लालू प्रसाद यादव के बीच मनमुटाव हो गया, जिसके बाद लालू ने राष्ट्रीय जनता दल के नाम से नई पार्टी बना ली। दिगर बात है कि 1998 में जब एनडीए की केंद्र में सरकार बनी तो नीतीश और जॉर्ज फर्नांडिस अटल कैबिनेट का हिस्सा थे। नीतीश कुमार ने तब वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी को अपना पसंदीदा नेता करार दिया था। दूसरी तरफ नीतीश 3 मार्च 2000 को बीजेपी की अगुआई वाले एनडीए के समर्थन से पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन बहुमत साबित नहीं कर पाने की वजह से 7 दिन बाद ही 10 मार्च को उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तब एनडीए ने 151 सीटें और लालू की आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन ने 159 सीटें जीती थीं, लेकिन दोनों ही बहुमत के लिए जरूरी 163 सीटों से दूर रह गए थे। दरअसल, उस समय तक बिहार विधानसभा में 324 सीटें थीं। नवंबर 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बनने के बाद अब बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। नीतीश कुमार की समता पार्टी ने 2003 में शरद यादव की जनता दल के साथ अपना विलय कर लिया। हालांकि नीतीश ने बीजेपी के साथ अपना गठबंध न जारी रखा। इस विलय से जनता दल यूनाइटेड का गठन हुआ, जिसके मुखिया बने नीतीश कुमार। आगे बताते चले कि नीतीश ने 2005 के विध ानसभा चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और पूर्ण बहुमत हासिल करते हुए 24 नवंबर 2005 को दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। नीतीश ने बीजेपी गठबंधन के साथ मिलकर 5 साल तक सरकार चलाई। नीतीश और बीजेपी का गठबंधन 2010 के विधानसभा चुनावों में भी जारी रहा और इन चुनावों में बहुमत हासिल करते हुए 26 नवंबर 2010 को नीतीश तीसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि नीतीश और बीजेपी का मजबूत गठबंधन करीब 17 साल बाद जून 2013 में पहली बार तब टूटा, जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। नीतीश ने उस समय बीजेपी से अलग होने के लिए कम्युनलिज्म यानी सांप्रदायिकता का हवाला दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश ने तब कहा था कि उन्होंने बीजेपी गठबंधन से नाता इसलिए तोड़ा था क्योंकि उनका मानना था कि एनडीए के पास एक साफ-सुथरी और सेकुलर इमेज वाला नेता होना चाहिए था। उस समय उन्होंने संघ-मुक्त भारत का भी आह्वान किया था। नीतीश ने तब ये भी कहा था, 'मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी के साथ वापस नहीं जाएंगे।' नीतीश और मोदी के रिश्ते हमेशा से उतार-चढ़ाव भरे रहे हैं। बीजेपी से अलग होने के बाद 2013 में नीतीश ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया, लेकिन कुछ ही महीनों बाद मई 2014 में इस्तीफा दे दिया। तब करीब 6 महीनों के लिए जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने। वही फरवरी 2015 में विधानसभा चुनावों से कुछ समय पहले मांझी की जगह नीतीश चौथी बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद नीतीश ने 2015 का विधानसभा चुनाव आरजेडी और कांग्रेस से हाथ मिलाकर महागठबंधन बनाकर लड़ा। महागठबंधन ने 243 में से 178 विधानसभा सीटें जीतीं और 20 नवंबर 2015 को पांचवीं बार बिहार के सीएम बन गए और लालू के बेटे तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने। वही दो साल के अंदर ही नीतीश के जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी से मिलकर बना महागठबंधन 2017 में टूट गया तथा इसकी वजह लालू के बेटे और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम आईआरसीटीसी घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग में सामने आया था। इसके बाद आरजेडी पर करप्शन का आरोप लगाते हुए नीतीश ने महागठबंधन से नाता तोड़ लिया और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वह 24 घंटे के अंदर ही बीजेपी के समर्थन से फिर से मुख्यमंत्री बन गए। नीतीश और बीजेपी का गठबंधन 2019 के

लोकसभा चुनाव तक ठीक चला और एनडीए ने अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए बिहार की 40 में से 39 लोकसभा सीटें जीत लीं। नीतीश की वापसी के पीछे भाजपा के नेता सुशील मोदी की अहम भूमिका मानी जाती है। सुशील मोदी को नीतीश कुमार ने इस नई सरकार में डिप्टी सीएम बनाया। दूसरी तरफ राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार की इस कदम को धोखाधड़ी करार दिया और निजी लाभों के लिए महागठबंधन में टूट का कारण बताया। लालू ने तब नीतीश को मौकापरस्त और पलटूराम नेता तक कह दिया था।

बहरहाल, 2017 में भाजपा के साथ लौटने के बाद 2020 का विधानसभा चुनाव जदयू ने एनडीए गठबंधन में रहते हुए ही लड़ा। 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू और बीजेपी के संबंध बिगड़ने लगे थे। जेडीयू ने बीजेपी पर यह कहकर निशाना साधना शुरू कर दिया कि बीजेपी के पास राज्य में कोई नेता नहीं और नीतीश ही एनडीए के सीएम हो सकते हैं।

आखिरकार बीजेपी ने नीतीश कुमार को सीएम प्रत्याशी घोषित करते हुए बराबर-बराबर सीटों पर चुनाव लड़ा। हालांकि, नतीजों के एलान के साथ ही यह साफ हो गया कि एनडीए गठबंधन में अब जदयू बड़े भाई की भूमिका खो चुकी है। बल्कि 74 सीट जीतकर भाजपा सीधे- सीधे राजद से टक्कर में आ गई। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री के लिए नीतीश कुमार के नाम के एलान को लेकर भी पसोपेश की स्थिति रही। एक बार जब भाजपा ने नीतीश कुमार को सीएम बनाने का एलान कर दिया, तब भी दोनों पार्टियों के बीच जारी विवाद कम नहीं हुए। चाहे जनसंख्या नियंत्रण विधेयक की बात हो, जातिगत जनगणना या बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग। भाजपा और जदयू में विवाद बना रहा। इसी बीच चिराग ने एनडीए से अलग होकर सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। इन चुनावों में जेडीयू को तगड़ा नुकसान हुआ, जबकि बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ। इसके बाद भाजपा नेताओं के बयान और आरसीपी सिंह के केंद्र सरकार से

करीबी बढ़ाने के मामलों ने दोनों पार्टियों के बीच दरार को खाई में बदलने का काम किया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने इसे नीतीश के खिलाफ साजिश का चिराग मॉडल करार दिया। और नीतीश कुमार ने आखिरकार भाजपा से गठबंधन तोड़ दिया। अब एनडीए से नाता तोड़ने के बाद नीतीश और तेजस्वी ने फिर से साथ मिलकर सरकार बना ली है। करीब 21 महीनों बाद एक बार फिर से नीतीश कुमार का हृदय परिवर्तन हो गया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह द्वारा कहा गया कि बीजेपी, पार्टी को कमजोर करने की साजिश कर रही है और 9 अगस्त को नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़ने का ऐलान करते हुए इस्तीफा दे दिया और कुछ ही देर में लालू की आरजेडी के साथ गठबंधन का ऐलान भी कर दिया। 10 अगस्त को वह आरजेडी के समर्थन से आठवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए।

गौरतलब हो कि नीतीश कुमार फिर से पाला बदलने जा रहे हैं, इसकी चर्चा पहले से ही चल रही थी और इसकी तस्दीक तो उसी दिन हो गई थी कि जब जनता दल यूनाइटेड के अंदर आरसीपी सिंह के कथित भ्रष्टाचार की खबर आने के बाद आरसीपी सिंह ने जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार पर हमला किया। आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए दो ऐसी बातें कहीं जो खुल्लम खुल्ला नीतीश के विरोधी भी नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि 'नीतीश कुमार कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, सात जन्म तक नहीं बन सकते'। इसके अलावा आरसीपी सिंह ने कहा कि 'जनता दल यूनाइटेड डूबता जहाज है'। ये दो बातें हैं जिसको लेकर नीतीश कुमार हमेशा से कहीं ज्यादा सतर्कता बरतते रहे हैं। यह भी सच है कि राजनीतिक तौर पर उनकी महत्वाकांक्षा देश के शीर्ष पद पर रही है। यही वजह है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी से गठबंधन से अलग होने से पहले प्रेस कांफ्रेंस में कहा था कि नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने के तमाम गुण हैं। वही नीतीश कुमार की राजनीति को नजदीक से जानने वाले कई नेताओं का मानना है कि प्रधानमंत्री पद की चर्चा होने पर नीतीश कुमार प्रफुल्लित होते रहे हैं। आरसीपी सिंह भी नीतीश कुमार के बरसों तक सबसे करीब रहे हैं, जाहिर होता है कि उनके मनोभावों को समझते हुए ही आरसीपी सिंह ने ये निशाना साधा था। दूसरी तरफ ललन सिंह के प्रेस कांफ्रेंस में भी दो ऐसी बातें हुई, जिससे यह तय हुआ कि बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड की राह जुदा होने वाली है। ललन सिंह ने पहली बात यह कही कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान को हमारे नुकसान के लिए खड़ा किया गया था और अब हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई है। इसकी चर्चा जनता दल यूनाइटेड के पटना में हुई विधायकों और सांसदों की बैठक में भी हुई। नीतीश कुमार ने खुद अपने नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा लगातार अपमान किया गया, हमारी पार्टी को लगातार कमजोर करने की कोशिश की गई। जनता दल यूनाइटेड से जुड़े सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के एक नेता का आरसीपी सिंह के साथ एक ऑडियो बातचीत ने इस अलगाव को बढ़ावा दिया। इस बातचीत में कथित तौर पर आरसीपी सिंह को जनता दल यूनाइटेड में कुछ करने को कहा जा रहा है। हालांकि इस तमाम घटनाक्रम को लेकर बीजेपी के किसी बड़े नेता का कोई बयान सामने नहीं आया है। वही नई दिल्ली एयरपोर्ट से पटना लौटते हुए, उड़े हुए चेहरे के साथ शाहनवाज हुसैन ने कहा कि 'हमारी पार्टी किसी को नहीं तोड़ती है, हमलोग केवल अपनी पार्टी को मजबूत करते हैं'।

दिगर बात है कि बीते दिनों पटना आये बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के एक बयान को अहम माना रहा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आने वाले दिनों में सभी क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना को दो गुटों

में विभक्त किया था, उसको लेकर भी जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार सशंकित हो गए थे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये सब अचानक से हुआ है, आरसीपी सिंह पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार इस गठबंधन से बाहर निकलने की पोजिशनिंग लंबे समय से कर रहे थे। दरअसल 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही नीतीश कुमार के लिए लगातार असहज स्थिति बनी हुई थी। पार्टी के अंदर भी और उस सरकार के अंदर भी, जिसके वे मुखिया थे। सरकार का मुखिया होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष और नेताओं का उन पर लगातार दबाव दिखा। यूनिफॉर्म सिविल कोड और तीन तलाक जैसे मुद्दों की चर्चा नीतीश कुमार की राजनीति को असहज करने जैसी ही स्थिति थी। यही वजह है कि गठबंधन से अलग होने से पहले अपने नेताओं के सामने नीतीश कुमार ने कहा भी कि बीजेपी ने अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा था। इसकी शुरुआत इस सरकार के बनने के तुरंत बाद शुरू हो गई थी, जब बीजेपी ने नीतीश कुमार के बेहद करीबी सुशील कुमार मोदी को बिहार की सरकार से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। दरअसल, नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी की आपसी अंडरस्टैंडिंग ऐसी थी कि वे एक दूसरे की जरूरत को अच्छी तरह समझते थे। बिहार बीजेपी के कई नेताओं ने 2020 के चुनाव के दौरान भी माना था कि सरकार आएगी, लेकिन ये जोड़ी आगे नहीं रहेगी। सुशील कुमार मोदी को बाद में बीजेपी ने राज्यसभा भेज तो दिया, लेकिन उनकी कमी बिहार बीजेपी को 9 अगस्त को

खली होगी। 9 अगस्त को बीजेपी नीतीश कुमार से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी और वे फोन लाइन पर नहीं आ रहे थे, अगर सुशील कुमार मोदी बिहार की राजनीति में सक्रिय होते तो संपर्क करना आसान होता। सरकार बनने के बाद विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के साथ नीतीश कुमार की नोंकझोंक को दुनिया भर में लाइव देखा गया था। जातीय जनगणना को लेकर भी नीतीश कुमार ने अलग रास्ता लिया, लेकिन तब बिहार की बीजेपी ने राष्ट्रीय नेतृत्व से अलग रास्ता लेकर गठबंधन को बनाए रखने की कोशिश की। इसके बाद ही नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी में तेजस्वी यादव के घर पहुंचे और वहां कुछ दूर पैदल चलकर उन्होंने बीजेपी को एक संकेत दे दिया था। इसके बाद लालू प्रसाद यादव के बीमार होने पर नीतीश कुमार ना केवल उन्हें देखने गए बल्कि मीडिया में घोषणा की थी राज्य सरकार लालू जी के इलाज का सारा खर्च उठाएगी। वही नीतीश कुमार के बीजेपी से अलग होने की इस कहानी में एम्स अस्पताल की भी अहम भूमिका रहा है, जहां लालू प्रसाद यादव अपना इलाज करा रहे थे और वहीं जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह भी इलाज कराने पहुंचे थे। इन दो समाजवादी नेताओं की आपसी मुलाकातों ने महागठबंधन को एकजुट करने में अहम भूमिका निभायी। वशिष्ठ नारायण सिंह उन वरिष्ठ नेताओं में हैं, जो राजनीतिक मुद्दों पर नीतीश कुमार से सलाह मशविरा करते रहे हैं।

बहरहाल, भाजपा के एक और पुराने साथी ने उसका साथ छोड़ दिया है। जनता दल (यू), भाजपा के उस दौर के साथियों में से एक है, जब भाजपा को राजनीतिक रूप से 'अछूत' समझा जाता था और कोई भी राजनीतिक दल भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करना चाहता था, उसे लगता था कि इससे उसकी सेकुलर छवि को

झटका लगेगा। उस दौर में भाजपा के साथ शिव सेना, अकाली दल, समता पार्टी और बाद में विलय के बाद जनता दल (यू) ने गठबंधन किया था। लेकिन पहले शिव सेना फिर अकाली दल और एक बार फिर जनता दल (यू) की दूरी से भाजपा के सबसे पुराने साथियों का नाता टूट गया है। भाजपा के पुराने साथियों में नाता तोड़ने वालों में पहला नाम शिव सेना का है। जिसने 2019 में 30 साल पुराने गठबंधन को तोड़ दिया था। 2019 के महाराष्ट्र विधान सभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के लिए दोनों दलों का गठबंधन टूट गया था और भाजपा के हाथ से सत्ता निकल गई थी। उसके बाद शिव सेना ने कांग्रेस-एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। लेकिन यह सरकार भी गिर गई और अब शिव सेना प्रमुख उद्धव ठाकरे अपने राजनीतिक करियर के सबसे गहरे संकट का सामना कर रहे हैं, उनकी पार्टी टूट चुकी है और उनके पुराने साथी एकनाथ शिंदे भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना चुके हैं। इसी तरह किसान आंदोलन को लेकर 2021 में शिरोमणि अकाली दल ने भाजपा से 27 साल पुराना नाता तोड़ लिया था। भाजपा से रिश्ता टूटने के बाद 2022 के पंजाब विधान सभा चुनाव में शिरोमणि अकाली दल की बुरी तरह से हार हुई और वह फिर एक बार पंजाब के सत्ता से दूर हो गई है। पंजाब में भाजपा और शिरोमणि अकाली दल ने 10 साल लगातार सरकार चलाई थी और 2017 से उसे कांग्रेस से हार का सामना करना पड़ा था। अब अंत में नाम आता है जदयू का।

जद (यू) और भाजपा का रिश्ता दूसरी बार टूटा है। इसके पहले नीतीश कुमार ने 2013 में भाजपा से 17 साल पुराना रिश्ता तोड़ दिया

था। लेकिन फिर 4 साल बाद वह फिर से भाजपा के साथ हो गए थे और अब फिर 5 साल बाद भाजपा से नाता तोड़ लिया है। इन साथियों के निकलने का सीधा मतलब है कि अटल-आडवाणी और जार्ज फर्नांडीस की अगुआई में बना एनडीए अब कमजोर पड़ रहा है और अब विपक्ष की राजनीति में नीतीश कुमार नए चेहरे और धुरी बन सकते हैं। नीतीश कुमार ने करियर के ऐसे समय में भाजपा का साथ छोड़ा है, जब वह अपनी राजनीति के आखिरी चरण में है। ऐसे में नीतीश नई भूमिका में दिख सकते हैं और 2024 के लोक सभा चुनाव में विपक्ष को लामबंद करने से लेकर भाजपा के खिलाफ रणनीति बनाने में सक्रिय दिख सकते है। दूसरी तरफ नीतीश के साथ बिहार में सरकार बनाने जा रहे राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव अब नए तेवर में दिख रहे हैं। उन्होंने पार्टी बैठक में कहा है कि बिहार के बाद दिल्ली में सत्ता परिवर्तन करना है।

जाहिर है तेजस्वी यह बात नीतीश के भरोसे ही कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में नीतीश कुमार विपक्ष की राजनीति का चेहरा बन सकते हैं। इस महाठबंधन में कांग्रेस की भूमिका भी बेहद अहम मानी जा रही है। बीजेपी से अलग होने से पहले नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी से कम से कम तीन बार लंबी बातचीत की है। राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा है कि आने वाले दिनों में यूपीए में नीतीश कुमार की अहम भूमिका होने वाली है। महागठबंधन के पिछले समय में भी यह चर्चा चली थी कि यूपीए का पुनर्गठन किया जाए। हालांकि तब उन्होंने अपने लिए कोई भूमिका नहीं मांगी थी, लेकिन इस बार संभव है कि उन्हें कनवेनर जैसा पद दिया जाए। राजनीतिक चर्चाओं के मुताबिक यूपीए कनवेनर के तौर पर नीतीश कुमार 2024 में विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद का चेहरा भी हो सकते हैं और इसके लिए वे बिहार की कमान तेजस्वी यादव को थमा सकते हैं।

फिलवक्त, एनडीए टूट गई है और महागठबंधन सरकार बनाने जा रही है। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली है। बस इंतजार है सरकार के भीतर कैबिनेट विस्तार की। हालांकि सूत्रों के मुताबिक 16 मंत्री राजद कोटे से और 13 मंत्री जेडीयू कोटे के हो सकते हैं। इनमें सहयोगी कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां एक तरफ राजद के साथ हैं तो दूसरी ओर जेडीयू के साथ हम पार्टी है। ऐसे में महागठबंधन के ये दो सूरमा किन-किन को मंत्री बनाते हैं, ये देखना होगा। नीतीश कुमार की इस नई सरकार में क्या-क्या बदलाव होंगे और कौन सा महत्वपूर्ण विभाग किन्हे मिलेंगे, इन तमाम जानकारियों को केवल सच अगले अंक में प्रकाशित करेगा, तब तक मंथन करे '8वीं बार, नीतीश कुमार'! ●

जदयू

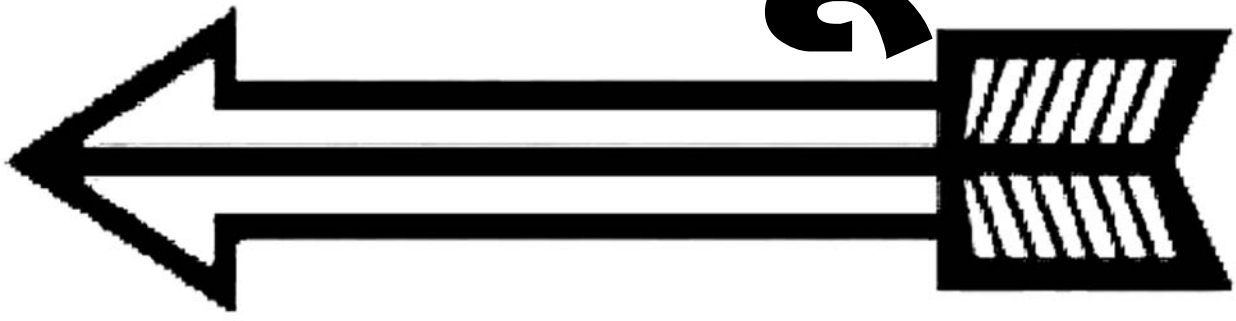

डूबता या दौड़ता जहाज!

बिहार की राजनीति में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। यूं कहे तो हर दल में दो गुट की गुटबाजी का खेल खेला जा रहा है और इसका असर पार्टी एवं उनके कार्यकर्ताओं पर पड़ना स्वभाविक है। जिस प्रकार बिहार में जदयू के भीतर खेला चल रहा है, वह लोकप्रिय भोजपुरी कहावत 'खेलम न खेले देब, खेलवे बिगाड़ देब' जैसी नजर आ रही है। बीते कई महीनों से सुर्खियों में आरसीपी सिंह और ललन सिंह के बीच के द्वंद को देखते और सुनते आ रहे हैं। केवल सच पत्रिका ने भी अपने पिछले जुलाई अंक में जदयू के भीतर के कलह को दिखाते हुए 'जदयू में वर्चस्व की जंग' खबर को प्रकाशित किया था। हालांकि बीते माह तक जदयू बनाम आरसीपी की जंग में राज्यसभा सदस्य उम्मीदवार को लेकर गहमागहमी के बीच खीरू महतो को राज्यसभा भेज दिया गया था और आरसीपी सिंह को साइलेंट कर दिया गया था। खैर, गुस्सा तो इस बात का जरूर पूर्व केन्द्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के मन में था, किन्तु फिर भी पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ता बनकर कार्य करने का बयान देते हुए स्थिर ही दिख रहे थे। इसी बीच जहानाबाद के दौरे में उनका स्वागत करते हुए वहां कार्यकर्ताओं ने 'बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, आरसीपी सिंह जैसा हो' के नारे लगाने शुरू कर दिये। इस खबर के पहले से ही आरसीपी से खीज खाये मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक्शन लेते हुए प्रदेश अध्यक्ष के हवाले से आरसीपी पर पार्टी में रहते हुए अकूत संपत्ति बनाने को लेकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और नोटिस भेज दिया। उन नोटिस में छः बिन्दुओं पर सवाल करते हुए जवाब मांगा गया। नतीजा यह हुआ कि आरसीपी सिंह ने जदयू की प्राथमिक सदस्यता से इस्तिफा देते हुए पत्रकार वार्ता में हरेक बिन्दुओं पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित उनके ईर्द-गिर्द रहने वालों की धज्जियां उड़ा दी। जदयू द्वारा भ्रष्टाचार का आरोप लगाये जाने के बाद पूर्व केन्द्रीय मंत्री आरसीपी सिंह बौखलाये हुए हैं और उन्होंने यहां तक कह डाला कि अगर लड़ाई हमसे लड़नी है तो हमारी बेटी-पत्नी को बीच में क्यों घसीट रहे हो। बौखलाये आरसीपी ने जदयू को डूबती हुई नैया होने की बात कहते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पीएम बनने को लेकर कहा कि नीतीश कुमार सात जन्मों तक पीएम नहीं बन पायेंगे। ऐसी तमाम सवालों के जवाब रोष के साथ भावनाओं में छलक कर आरसीपी सिंह के द्वारा सामने आने को बेताब है। ऐसे में सूत्रों के हवाले आरसीपी द्वारा नई पार्टी बनाये जाने की बात कभी आ रही है तो कभी मुख्यमंत्री को खुली चुनौती देते हुए उनके गृह जिला नालंदा से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने की बात भी सामने आ रही है। इन तमाम राजनीतिक उलझनों पर प्रकाश डालती प्रस्तुत है संयुक्त संपादक **अमित कुमार** के साथ सहायक संपादक **रामपाल प्रसाद वर्मा** की राजनीतिक रिपोर्टः-

पूर्व केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह यानी आरसीपी सिंह मुश्किल में फंस गए हैं। उन्हें अपनी ही पार्टी जेडीयू ने नोटिस थमा दिया है। आरोप है कि राज्यसभा सांसद और फिर केंद्रीय मंत्री रहते हुए आरसीपी सिंह ने अकूत अचल संपत्ति बनाई है। वह भी गलत तरीके से। राज्यसभा की सदस्यता खत्म होने पर पिछले महीने ही आरसीपी सिंह ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह में पिछले कुछ समय से काफी खटास बढ़ गई थी। यही कारण है कि मंत्री पद जाते ही खुद की पार्टी से इतने बड़े आरोप लगने पर कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। कहा जाने लगा है कि जेडीयू में कुछ लोग हैं, जो आरसीपी सिंह की राजनीति खत्म करना चाहते हैं। हालांकि यह भी सच है कि वह नीतीश कुमार ही थे जो आरसीपी सिंह को राजनीति में लाये थे। आरसीपी

सिंह पहली बार 1996 में नीतीश कुमार के संपर्क में तब आए जब वो तत्कालीन केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के निजी सचिव थे। नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच दोस्ती इसलिए भी गहरी हुई, क्योंकि दोनों ही बिहार के नालंदा से हैं और एक ही जाति से आते हैं। नीतीश कुमार जब केंद्र सरकार में मंत्री बने तो आरसीपी सिंह को अपने साथ ले आए। नीतीश कुमार रेलमंत्री बने थे तो आरसीपी सिंह को विशेष सचिव बनाया। नवंबर 2005 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने तो आरसीपी सिंह को साथ लेकर बिहार भी आए और प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद आरसीपी की जेडीयू में पकड़ मजबूत होने लगी। 2010 में आरसीपी सिंह ने वीआरएस लिया, फिर जेडीयू ने उन्हें राज्यसभा के लिए नामित कर दिया। 2016 में पार्टी ने उन्हें फिर से राज्यसभा भेजा। 2020 में उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया गया। 2021 में जब केंद्र में मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ तो आरसीपी सिंह जेडीयू कोटे से केंद्र सरकार में मंत्री बना दिए गए। उन्हें इस्पात विभाग का मंत्री बनाया गया था।

बहरहाल, यही से आरसीपी सिंह से नीतीश कुमार की दूरियां बढ़नी शुरू हुई। 2021 में जब आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री बने तो कुछ दिन तक सबकुछ ठीक चला। बताया जाता है कि इसके बाद आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार में अनबन की बातें आने लगीं। हालांकि, खुले मंच से दोनों ने कभी एक-दूसरे पर निशाना नहीं साधा। कहा जाता है कि केंद्र सरकार में मंत्री बनने के बाद आरसीपी सिंह भाजपा के काफी

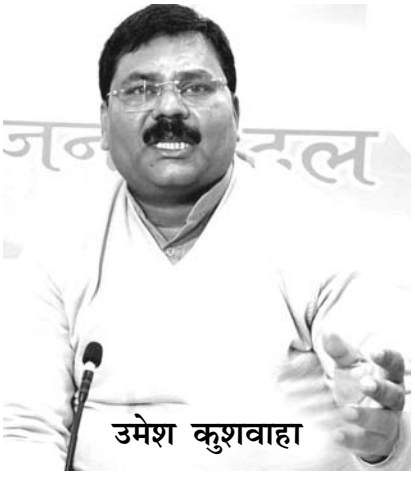

करीब आ गए थे। इसके चलते उनकी दूरियां नीतीश कुमार से बढ़ने लगीं थीं। यही कारण है कि आरसीपी सिंह को पार्टी ने दोबारा राज्यसभा नहीं भेजा। और तो और पार्टी ने आरसीपी सिंह पर अकूत संपत्ति पार्टी में रहकर बनाने का आरोप तक लगाया।

बताते चले कि सत्ताधारी दल जदयू ने अपने ही कद्दावर नेता और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाया। आरसीपी सिंह पर साल 2013-2022 तक अकूत संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। अब आरसीपी सिंह को प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कारण बताओ नोटिस भेजा है। आरसीपी सिंह के खिलाफ कार्रवाई को लेकर एक बार फिर बिहार में माहौल गर्म हो गया है। जदयू नेताओं ने आरसीपी सिंह पर 9 साल में 58 प्लॉट खरीदने का गंभीर आरोप लगाया है, जिसमें नालंदा जिले के दो प्रखंडों में खरीदी गई 40 बीघा जमीन भी शामिल है। वहीं आरसीपी सिंह पर जमीन को दान में लेने का आरोप लगा है। इन संपत्तियों का चुनावी हलफनामे में जिक्र नहीं किया गया था। सबसे खास बात ये है कि आरसीपी सिंह की संपत्ति का ब्योरा जदयू के ही नेताओं ने जुटाया है। इसतरह से कहा जा रहा है कि 'जदयू की सेना, अपने रामचंद्र की संपत्ति खोजो अभियान' पर निकल गई है। जदयू ने यहां तक आरोप लगाया है कि आरसीपी सिंह ने अपनी पत्नी के नाम में हेरफेर कर जमीन खरीदी है। सबूत के साथ यह बात सामने आई है कि आरसीपी सिंह और उनके परिवार ने 2013 से अब तक अकूत संपत्ति बनाई है। कुछ पत्नी के नाम तो कुछ दोनों बेटियों के नाम से हैं। जदयू ने जो दस्तावेज जुटाए हैं, उसके मुताबिक 2013 से अब तक नालंदा जिले के सिर्फ दो प्रखंड अस्थावां और इस्लामपुर में करीब 40 बीघा जमीन खरीदी गई है। इसके

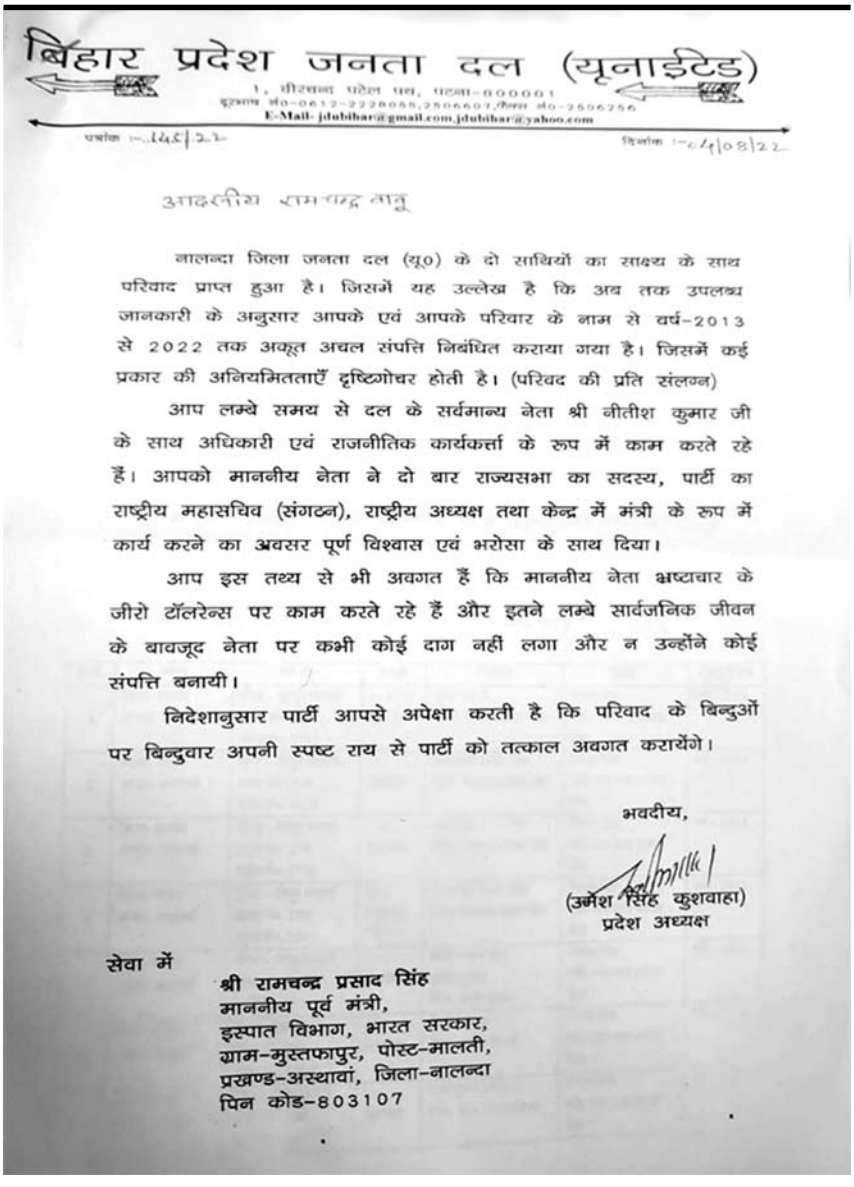

बिहार प्रदेश जनता दल (यूनाईटेड)

1, वीरचन्द पटेल पथ, पटना-800001
दूरभाष नं0-0612-2228055,2506607,फैक्स नं0-2506256
E-Mail- jdubihar@gmail.com,jdubihar@yahoo.com

पत्रांक :- 145/22 दिनांक :- 04/08/22

आदरणीय रामचन्द्र बाबू

नालन्दा जिला जनता दल (यू०) के दो साथियों का सादर्य के साथ परिवाद प्राप्त हुआ है। जिसमें यह उल्लेख है कि अब तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार आपके एवं आपके परिवार के नाम से वर्ष-2013 से 2022 तक अकूत अचल संपत्ति निबंधित कराया गया है। जिसमें कई प्रकार की अनियमितताएँ दृष्टिगोचर होती है। (परिवद की प्रति संलग्न)

आप लम्बे समय से दल के सर्वमान्य नेता श्री नीतीश कुमार जी के साथ अधिकारी एवं राजनीतिक कार्यकर्त्ता के रूप में काम करते रहे हैं। आपको माननीय नेता ने दो बार राज्यसभा का सदस्य, पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव (संगठन), राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा केन्द्र में मंत्री के रूप में कार्य करने का अवसर पूर्ण विश्वास एवं भरोसा के साथ दिया।

आप इस तथ्य से भी अवगत हैं कि माननीय नेता भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेन्स पर काम करते रहे हैं और इतने लम्बे सार्वजनिक जीवन के बावजूद नेता पर कभी कोई दाग नहीं लगा और न उन्होंने कोई संपत्ति बनायी।

निदेशानुसार पार्टी आपसे अपेक्षा करती है कि परिवाद के बिन्दुओं पर बिन्दुवार अपनी स्पष्ट राय से पार्टी को तत्काल अवगत करायेंगे।

भवदीय,

(उमेश सिंह कुशवाहा)
प्रदेश अध्यक्ष

सेवा में

श्री रामचन्द्र प्रसाद सिंह
माननीय पूर्व मंत्री,
इस्पात विभाग, भारत सरकार,
ग्राम-मुस्तफापुर, पोस्ट-मालती,
प्रखण्ड-अस्थावां, जिला-नालन्दा
पिन कोड-803107

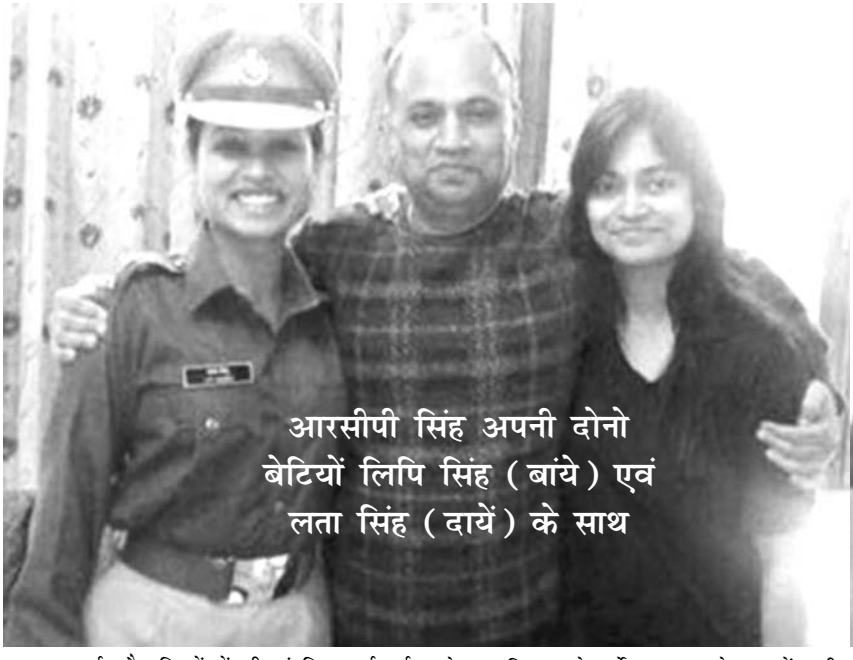

आरसीपी सिंह अपनी दोनो बेटियों लिपि सिंह (बांये) एवं लता सिंह (दायें) के साथ

आरसीपी सिंह की पत्नी गिरिजा सिंह

अलावा कई और जिलों में भी संपत्ति बनाई गई है। आरसीपी सिंह की पत्नी गिरजा सिंह और दोनों बेटियों यानी लिपि सिंह एवं लता सिंह के नाम पर ज्यादातर जमीन है। जदयू की रिपोर्ट के मुताबिक नालंदा जिले के इस्लामपुर (हिलसा) अंचल के सैफाबाद मौजा में 12 और केवाली अंचल में 12 प्लॉट खरीदे गए हैं। 2013 से 2016 के बीच में इसकी खरीदारी की गई है। ये प्लॉट आरसीपी सिंह की बेटी लिपि सिंह और लता सिंह के नाम पर है। वहीं 28 अप्रैल 2014 को गया के नीमचक बथानी स्थित चरकावां के नरेश प्रसाद सिंह ने नालंदा जिले के छबीलापुर के बेलधर बिगहा के धर्मेंद्र कुमार को दान में जमीन दी। बाद में धर्मेंद्र कुमार ने यही जमीन लिपि सिंह और लता सिंह के नाम बेच दी। जदयू के दस्तावेजों के अनुसार 4 सितंबर 2014 और 15 सितंबर 2014 को सिलाव के बिशेश्वर साव ने दो प्लॉट खरीदे। इसे 18 सितंबर को लिपि सिंह और लता सिंह के नाम बेच दिया गया। ऐसे 2 और मामले हैं, जिसमें 6 दिन और 8 महीने में दूसरे से खरीदी गई। जमीन को खरीदने वाले ने लता सिंह और लिपि सिंह को जमीन बेच दी गई। जदयू के 35 पन्नों में जमीन की खरीद और इससे जुड़े दूसरे विवरण भी है। वहीं, नालंदा जिले के इस्लामपुर (हिलसा) के अलावे अस्थावां (नालंदा) के शेरपुर मालती मौजा में भी आरसीपी सिंह ने 33 प्लॉट खरीदे हैं। इसमें चार प्लॉट 2011–2013 में लता सिंह और लिपि सिंह के नाम पर लिया है। पिता के रूप में आरसीपी सिंह का नाम है। बाकी 12 प्लॉट गिरजा सिंह और 18 प्लॉट लता सिंह के नाम पर खरीदे गए हैं। वहीं महमदपुर में 2015 में एक प्लॉट गिरजा सिंह के नाम पर खरीदा गया। 2011 में 2, 2013 में 2, 2014 में 5, 2015 में 6, 2017 में 1, 2018 में 3, 2019 में 4, 2020 में 3, 2021 में 6 तथा 2022 में 2 प्लॉट खरीदे गए हैं। यह भी बात सामने आई है कि आरसीपी

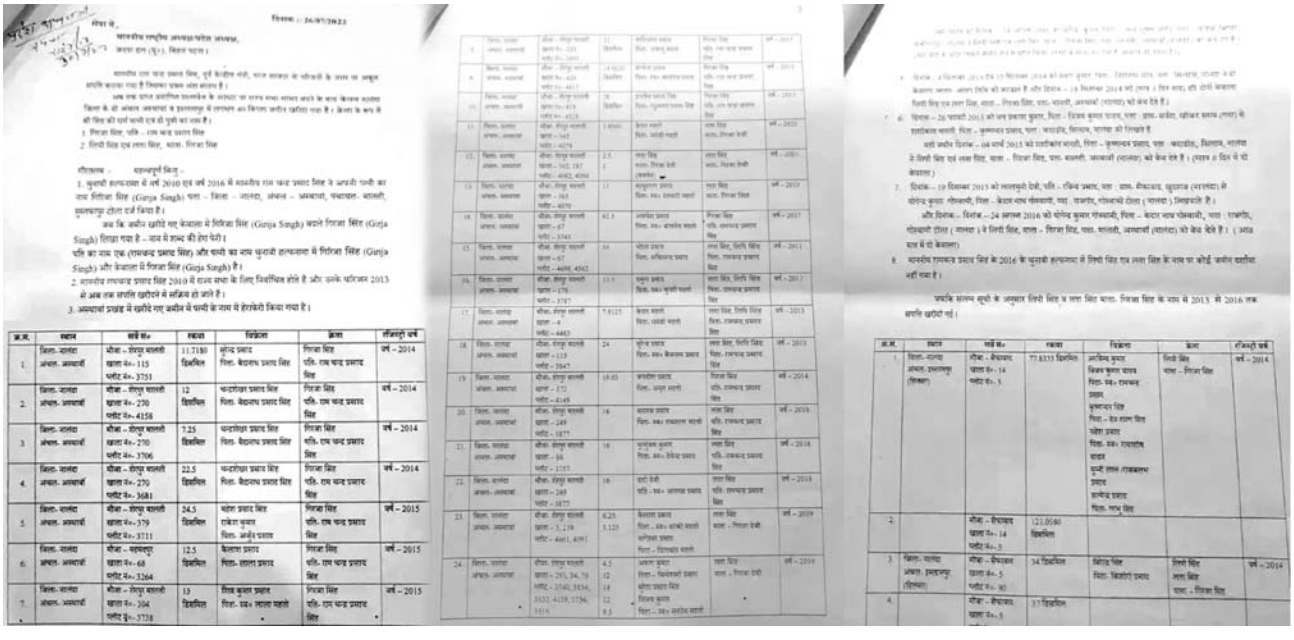

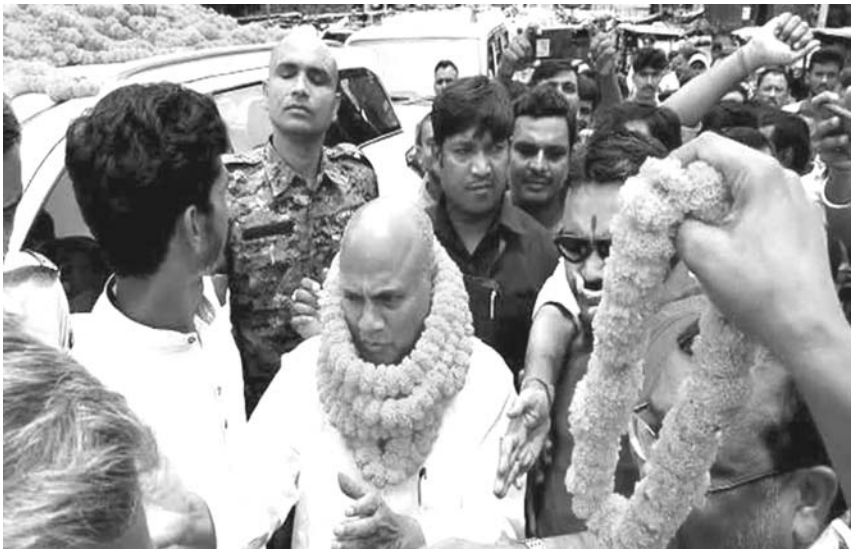

सिंह ने पत्नी के नाम के साथ भी हेरफर किया है। चुनावी हलफनामा 2010 एवं 2016 में आरसीपी सिंह ने अपनी पत्नी का नाम गिरिजा सिंह दर्ज किया है। वहीं जमीन खरीदी गए केवाला में गिरजा सिंह लिखा गया है।

जनता दल यूनाइटेड सुप्रीमो और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक समय में रामचंद्र प्रसाद सिंह के करीबी रहे और अब उनकी कोपभाजन के शिकार पूर्व केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहते हैं। इसलिए नीतीश कुमार और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के इशारे पर पार्टी की बिहार इकाई ने रामचंद्र प्रसाद सिंह से उनके द्वारा पिछले कुछ वर्षों में खरीदे गए 58 प्लॉट्स को लेकर सवाल किए हैं। पार्टी की बिहार इकाई ने इन प्लॉट का ब्योरा देते हुए पूछा है कि इसमें कई भूखंड की जानकारी उनके चुनावी हलफनामे में भी नहीं हैं और ये अकूत संपति अर्जित की हैं जो अनियमित लगती है। बता दें कि जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने आरसीपी सिंह को कारण बताओ नोटिस भेजकर अकूत संपत्तियों और अनियमितताओं पर जवाब मांगा था। उमेश कुशवाहा के द्वारा भेजे गए पत्र सह नोटिस में पूछा गया कि नालंदा जिला के दो साथियों का साक्ष्य के साथ परिवाद प्राप्त हुआ है। जिसमें यह उल्लेख है कि अब तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार आपके एवं आपके परिवार के नाम से वर्ष 2013 से 2022 तक अकूत अचल संपत्ति निबंधित की गई। इसमें कई तरह की अनियमितताएं नजर आ रही हैं। क्या ये आपकी नियमित आमदनी से खरीदी गई है। खरीदी गई ज्यादातर जमीनें आरसीपी सिंह की पत्नी गिरजा सिंह और दोनों बेटियों (लिपि सिंह, लता सिंह) के नाम पर है। एक आरोप यह भी है कि आरसीपी ने खासकर 2016 के अपने चुनावी हलफनामे में इसका जिक्र नहीं किया है। वो छह सवाल, जो आरसीपी सिंह से पूछे गये थे :-

1. क्या नालंदा के सिर्फ दो प्रखंड अस्थावां और इस्लामपुर में 2013 से अब तक करीब 40 बीघा जमीन आपने खरीदी है?
2. क्या आपने वाजिब आमदनी के बूते यह संपत्ति बनाई है? चूंकि पार्टी ने आपकी इस खरीद को अनियमितता बताया है?
3. ज्यादातर जमीनें आपकी पत्नी और दोनों बेटियों के नाम पर हैं। आपने 2016 के चुनावी हलफनामे में इसका जिक्र नहीं किया। क्यों?
4. कुछ ऐसी जमीनें भी खरीदने की बात है, जो किसी ने किसी को दान दी थी और दान लेने वाले ने आपको बेच दी?
5. किसी एक ने दूसरे से जमीन खरीदी और फिर कुछ दिनों में आपकी दोनों बेटियों को क्यों बेच दी?
6. कई संपत्तियों की खरीद के वक्त आपकी बेटी लिपि सिंह की शादी नहीं हुई थी। दस्तावेज में आपकी सिर्फ आपकी पत्नी का नाम है। क्यों?

हालांकि, इस नोटिस में माना गया है कि अधिकांश भूखंड उन्होंने अपनी पत्नी या बेटी के नाम से खरीदा है, लेकिन पार्टी ने पूछा है कि उन्होंने इस संपत्ति को चुनावी हलफनामे में क्यों नहीं दिखाया? फिर दान वाली जमीन आपने कैसे खरीदी? आप इस बात से अवगत हैं कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस पर काम करते हैं और इतने लंबे सार्वजनिक जीवन के बावजूद नेता पर कभी कोई दाग नहीं लगा और ना उन्होंने कोई संपत्ति बनाई। इस पत्र से साफ है कि आय से अधिक संपति को आधार बनाकर पार्टी के दो शीर्ष नेता नीतीश कुमार और ललन सिंह, आरसीपी के खिलाफ कार्रवाई करना चाह रहे थे। नीतीश कुमार ने पिछले दो महीने के दौरान आरसीपी सिंह को ना केवल राज्यसभा की सदस्यता से वंचित किया था बल्कि पटना में वो जिस घर में रहते थे उस घर को भी मुख्य सचिव को आवंटित

कर खाली करने पर मजबूर कर दिया और अब जमीन का मामला सार्वजनिक कर पार्टी से उनकी विदाई की एक तरह से औपचारिकता पूरी की जा रही थी। माना जा रहा है कि आरसीपी भले जो भी जवाब दें, लेकिन पार्टी उसे असंतोषजनक करार कर उन्हें पार्टी से निलंबन की कार्रवाई शुरू करेगी। किन्तु नोटिस मिलने के बाद आरसीपी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तिफा दे दिया। वहीं, आरसीपी सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अधिकांश भूखंड उनकी बेटियों या पत्नी के नाम पर हैं, जो आयकर जमा करती हैं। विभाग में उन्होंने खरीद-बिक्री की जानकारी दे रखी थी। इसके अलावा उनके खाते या उनके नाम से कोई भूखंड की खरीद-बिक्री नहीं हुई।। ऐसे में ये आरोप लगाना कहां से उचित हैं कि लालू स्टाइल में उन्होंने जमीन अर्जित की। उन्होंने पार्टी के नेताओं से पूछा कि वो बताएं कि आखिर किसी भूखंड के बदले उन्होंने किसी को उपकृत किया हो। ये सब आरोप बेबुनियाद हैं और जिसने भी जांच की उसे उनसे भी पूछताछ कर लेनी चाहिए थी। दिगर बात है कि जदयू ने अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रहे आरसीपी सिंह के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई को कमोबेश मुकाम तक पहुंचा दिया है। कार्रवाई का आधार उनकी और उनके घर वालों की हाल की संपत्ति दर्शायी जा रही है। पार्टी ने इसे भ्रष्टाचार के मोर्चे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 'जीरो टॉलरेंस' की नीति के खिलाफ माना है। वही जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह भ्रष्टाचार का मामला लग रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि आरसीपी सिंह का पक्ष आने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नोटिस के जरिए जानने की कोशिश की गई है कि जो ब्योरा पार्टी को प्राप्त हुई है, आरसीपी का क्या

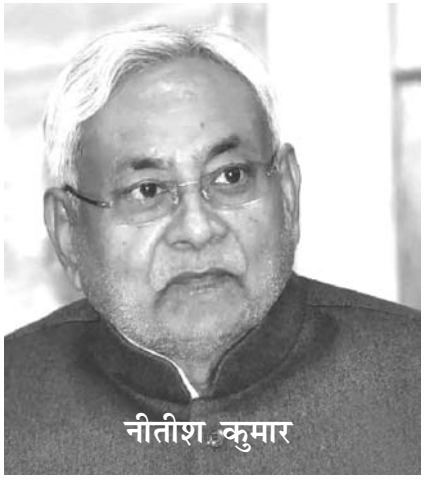
नीतीश कुमार

कहना है? उन्होंने जो भी जमीन खरीदी है उसका एफिडेविट में जिक्र नहीं है तो यह चुनाव आयोग का मामला बनता है। यह मामला चुनाव आयोग को देखना चाहिए। यह सबको मालूम होना चाहिए कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और हमारी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है। इस संबंध में सरकार से संबंधित किसी व्यक्ति पर अगर इस तरह का आरोप लगता है तो स्वभाविक रूप से यह गंभीर है। जल्द से जल्द उन्हें पूरे मसले पर अपनी बात रखनी चाहिए। वहीं, आरसीपी सिंह को उनकी संपत्ति के मुद्दे और पार्टी के नोटिस के मद्देनजर जद (यू) से निष्कासित किये जाने के सवाल पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि क्या ऐसा लगता है कि वह अपनी गतिविधियों के चलते अभी भी पार्टी में हैं? उन्होंने खुद एक रास्ता अपनाया है, जहां उन्होंने मान लिया है कि वह अब पार्टी में नहीं हैं। कुशवाहा ने आगे कहा कि अभी जो भी उनपर आरोप है कि कहां से संपत्ति आई, कैसे आई यह सब जांच का विषय है। लेकिन इतना सबको मालूम है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसी चीजों को कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं। स्वभाविक रूप से अगर किसी ने साथ रहकर भी ऐसा किया है तो इसमें दो बातें हो सकती है। या तो नीतीश कुमार की जानकारी के बिना ऐसा किया गया होगा या फिर उनसे दूर हटने के बाद ऐसा किया गया होगा। लेकिन पूरी बात जांच के बाद ही पता चल पाएगी। अगर पार्टी के किसी सदस्य के बारे में कोई सूचना आती है तो पार्टी की जिम्मेदारी बनती है जिनके बारे में सूचना है उन्हें इस बात से अवगत कराया जाए। आरसीपी सिंह के समर्थकों की ओर से 'बिहार का सीएम कैसा हो, आरसीपी सिंह जैसा हो' जैसी नारेबाजी पर कुशवाहा ने कहा कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसपर अपनी बात स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर रहकर अगर कोई ऐसी नारेबाजी करता है तो सरासर गलत है। पार्टी ऐसी चीजों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी।

गौरतलब हो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन की सच्चाई है कि उनके अधिकांश कट्टर आलोचक और विरोधी एक समय में उनके खास करीबी रहे हैं। इस सूची में अब पूर्व केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह का भी नाम धीरे-धीरे जुड़ने लगा था। नीतीश कुमार द्वारा राज्य सभा की सदस्यता से वंचित किए जाने के बाद उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया। कुछ महीनों पूर्व तक नीतीश कुमार के करीबी रामचंद्र प्रसाद सिंह इन दिनों नालंदा जिले में अपने गाँव में प्रवास कर रहे हैं। विधिवत रूप से दिल्ली से बोरिया बिस्तर बांधकर वापस लौटने के बाद आरसीपी सिंह ने अपने मन की बात अब तक नहीं की हैं, जब एक पार्टी कार्यकर्ता की मौत के बाद उनके परिवार वालों से मिलने के समय जो उनके पक्ष में ये नारा लगा कि 'बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, आरसीपी सिंह जैसा हो'। ये

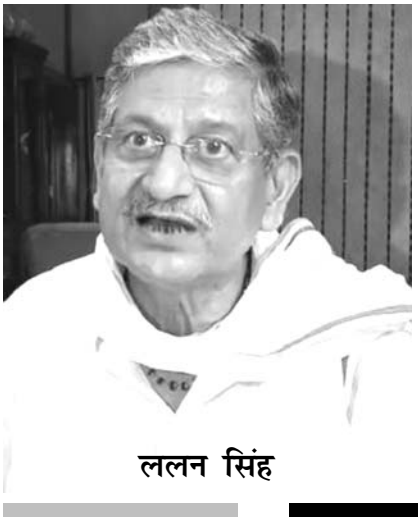
ललन सिंह

उमेश कुशवाहा

उपेन्द्र कुशवाहा

निश्चित रूप से नीतीश कुमार और उनके समर्थकों को नागवार गुजरा होगा और वो उन्हें चिढ़ाने के लिए ही आरसीपी सिंह के समर्थक नारा लगा रहे थे। आरसीपी सिंह ने कुछ खुलकर तो नहीं बोला, लेकिन इतना जरूर कहा कि उन्हें कोई हाशिये पर लाने की नहीं सोच सकता, क्योंकि उन्हें अपने जीवन में वो चाहे नौकरी हो या राजनीतिक जीवन सब कुछ पाया हैं, जो एक सामान्य लोग पाने की आकांक्षा रखते हैं। नीतीश कुमार के बारे में कुछ खास नहीं कहा लेकिन ये कह कर उनकी दुखती रग पर हाथ जरूर रख दिया कि 'नीतीश कुमार का पैतृक गाँव भले नालंदा जिले में हो, लेकिन वो उनका जन्मस्थान बख्तियारपुर हैं' जबकि आरसीपी ने अपने बारे में कहा कि उनका जन्मस्थान भी नालंदा जिला हैं। इस बात का अलग-अलग अर्थ लगाया जा रहा हैं। लेकिन एक बात साफ हैं कि आरसीपी अपने आप को नालंदा का धरतीपुत्र बता रहे हैं। इसके अलावा वर्तमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के बारे में कहा कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के समय उनके नाम के प्रस्तावक वहीं थे। आरसीपी के बयानों से साफ हैं कि वो

बागी हो चुके हैं और उनको अंदाजा हैं कि देर सवेर उनके खिलाफ कारवाई कर पार्टी से निकालने की नीतीश कुमार अपने दिलीइच्छा को पूरा करेंगे। क्योंकि नीतीश जब अपने नजदीकियों को किनारा करते हैं तो राजनीतिक प्रताड़ना का कोई अंत नहीं। लेकिन फिलहाल आरसीपी जितना फूंक-फूंककर कदम रख रहे हैं, वैसे में नीतीश

प्रदेश अध्यक्ष, जनता दल (यू)

मैं, रामचन्द्र प्रसाद सिंह, जनता दल (यू) की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र देता हूँ।

रामचन्द्र प्रसाद सिंह
पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष
जनता दल (यू)
6/8/2022
8.30PM
मुस्तफापुर, नालंदा

को कोई कारवाई करने का समुचित आधार नहीं मिल रहा था और अचानक वह मौका नीतीश कुमार और जदयू नेताओं के हांथों अचूक संपत्ति के हवाले मिल ही गया।

दूसरी ओर जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता मंजीत सिंह ने आरसीपी सिंह पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश की कृपा हटते ही आरसीपी सिंह रोड पर आ गए हैं। जेडीयू प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व विधायक मंजीत सिंह ने पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कृपा से वे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, दो बार राज्यसभा सदस्य रहे और केंद्र में मंत्री बने। मुख्यमंत्री की कृपा हटते ही वे रोड पर आ गए हैं। रोड पर अब घूम रहे हैं। नीतीश कुमार और दल को आरसीपी सिंह ने धोखा दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से हम कहेंगे कि इस पर जल्द संज्ञान लें। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि कुछ भाड़े के लोगों को एकत्र करके कोई बिहार का नेता नहीं बन सकता है। आरसीपी सिंह अपनी हैसियत भूल गए हैं। चार दिन पहले तक मुख्यमंत्री को साहब-साहब कहते वे थकते नहीं थे। आज मुख्यमंत्री बनने चले हैं। प्रदेश प्रवक्ता ने आगे कहा कि नीतीश कुमार इस दल के सर्वमान्य नेता है। पार्टी के अंदर कोई वैकेंसी नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी बनाने में उनका कोई योगदान नहीं है। वर्ष 1994 में समता पार्टी बनी और नीतीश कुमार ने संघर्ष किया। संघर्ष की बदौलत 2005 में तत्कालीन सत्ता को उखाड़ फेंका। उस समय की सियासत में आरसीपी सिंह का कोई अता-पता नहीं था। आज पार्टी में आरसीपी सिंह का कोई वजूद नहीं है। जदयू का एक भी कार्यकर्ता आरसीपी सिंह के साथ नहीं है। वह अकेले खड़े हैं। दिगर बात है कि अपने

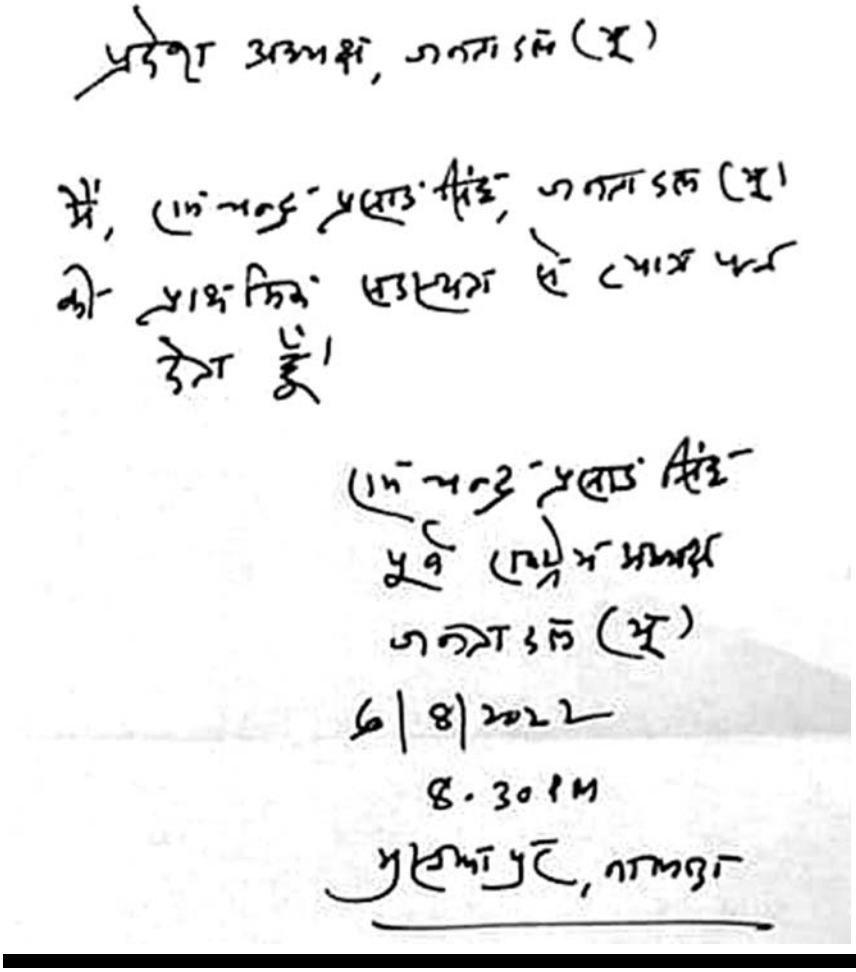

ही पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ जांच करने और उनसे भ्रष्टाचार संबंधी सवाल-जवाब करने वाली जदयू हालिया वर्षों में संभवत: देश की पहली पार्टी है। जेडीयू ने जिस तरह से आरसीपी सिंह को नोटिस दिया, उससे साफ पता लगता है कि नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच कड़वाहट काफी बढ़ चुकी है। किसी भी सार्वजनिक नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप काफी गंभीर होता है। वह भी तब जब अपनी ही पार्टी की तरफ से इस तरह के आरोप लगाए गए हों। मतलब साफ है कि जेडीयू में कुछ लोग हैं, जो आरसीपी सिंह की राजनीति अब पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं।

बहरहाल, कभी नीतीश कुमार के हनुमान कहे जाने वाले आरसीपी सिंह ने जनता दल यूनाइटेड से इस्तीफा दे दिया। कहा जा रहा है कि वह लंबे समय से पार्टी से नाराज चल रहे थे। जेडीयू से इस्तीफा देते हुए आरसीपी सिंह ने कहा कि पार्टी अब एक डूबता हुआ जहाज है। अब मैं इस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। कोई सीमा होती है। आप मुझसे पूछ सकते थे। मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं रह सकता। यह पार्टी तो डूबता जहाज है। जितने लोग चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम किए, वे सम्मानित हो रहे हैं। हमसे चिढ़ है तो हमसे निपटिए, बच्चियों को घसीट रहे हो। आरसीपी सिंह ने आगे कहा कि मेरे नाम जमीन नहीं है। मैंने बच्चियों के नाम जमीन ट्रांसफर नहीं की। जिनके नाम है वे जवाब दे रही हैं। वो तो पार्टी की सदस्य भी नहीं है। जानबूझकर मेरी इमेज खराब करने की कोशिश की गई। ऐसा पहले भी कई बार किया जा चुका है। मैं जमीन का आदमी हूं। मैंने हमेशा गरिमा से काम किया है, किसी की एक पैसे की चाय नहीं पी। आरसीपी ने पार्टी की तरफ से जारी नोटिस पर जवाब देते हुए कहा कि उनकी एक बेटी आईपीएस है तो दूसरी अधिवक्ता है। साल 2010 से ही दोनों बेटियां इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करती आ रही हैं। आरसीपी ने आगे कहा कि उनके पिता भी सरकारी नौकरी में थे। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति हमारी दोनों बेटियों के नाम कर दी थी। आरसीपी ने आगे कहा कि जमीन की खरीद एक बार में नहीं, बल्कि टुकड़े में हुई थी। आगे उन्होंने कहा कि कुछ मामला जमीन के बदले जमीन का भी है। उन्होंने कहा कि उनके बैंक अकाउंट से एक रुपये का भी लेन-देन नहीं हुआ है। हमारे ऊपर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, वो सभी निराधार है। आरसीपी ने चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग शीशे के घर में रहते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। उन्होंने कहा था कि इससे पहले भी उन पर आरोप लगाये गए थे, लेकिन हुआ क्या। आरसीपी ने कहा कि जिसने भी उन्हें नोटिस भेजा उसने मेरे

नाम के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री लिखा हैं। सवालिया लहजे में उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलने या लिखने में उन्हें शर्म लग रही था क्या? उन्होंने आगे कहा कि दम है तो सबूत निकाल लें। मेरी बेटी ने जमीन खरीदी, उसका हिसाब उसके पास है। वह रिटर्न फाइल करती है। हमारी पत्नी यहीं रहती हैं, यहीं खेती कराती हैं। हमारा तो कुछ है ही नहीं। हमारा जो है वह सर्विस से मिला पैसा है और पेंशन है। मेरे नाम पर सिर्फ एक ही प्लॉट है, जो मेरा पुश्तैनी है। कौन सा ऐसा केंद्रीय मंत्री है जो दिल्ली से आकर अपने गांव में रहता है? आरसीपी ने आगे कहा कि जो लोग शीशे के घर में रहते हैं, वे पत्थर न फेंके। आज मैं बहुत दुखी हूं। मैं फिर से चुनौती दे रहा हूं कि मेरे खिलाफ कुछ साबित करके दिखाएं। मैं चुनौती स्वीकार करता हूं। सवा साल से मंत्री था तो ईर्ष्या का कोई इलाज नहीं है। आपको कुछ बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा है मुख्य समस्या यही है। अपने इस्तीफे की घोषणा के साथ ही उन्होंने कहा कि इस पार्टी में कुछ नहीं बचा है। वो डूबता हुआ जहाज है। अब झोला ढोने से कोई फायदा नहीं होना वाला है। आरसीपी ने कहा कि पार्टी नेताओं द्वारा जान-बुझकर मेरी इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी में कुछ जालसाज है। जालसाज लोगों के पास बस यही काम रह गया है। अपने ऊपर लगे जमीन से जुड़े आरोपों से आहत पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह राजनीतिक गलियारों से लेकर मीडिया की गलियारों में सुर्खियों में रहे और इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री थोड़े भावुक भी दिखे। उन्होंने कहा कि जेडीयू पार्टी डूबता हुआ जहाज, जो भी कार्यकर्ता इस डूबते हुए जहाज को छोड़ना चाहते हैं छोड़ दें। मैंने हमेशा पार्टी में सच्चे कार्यकर्ता के रूप में काम किया। जेडीयू ने राजनीति की स्तर को तोड़ दिया। वही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जम कर हमला किया। आरसीपी सिंह ने कहा कि देश में ऐसा कौन मुख्यमंत्री होगा जो शाम में तीन घंटे सिर्फ बातें कर निकाल देता हो? नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने के मुद्दे पर उन्होने कहा कि वो 7 जन्म में भी पीएम नहीं बन सकते, इस जन्म की बात तो छोड़ दें। आरसीपी सिंह ने कहा कि अच्छी चुनौती दी गई है और मैं इसको स्वीकार करता हूं। हमसे चिढ़ है, तो हमसे निपटो,

हमारे पास विकल्प खुले हुए हैं। वर्तमान समय में मुझपर अकूत संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया। ये मेरी छवि को बदनाम करने की कोशिश थी। आरसीपी सिंह ने कहा कि जेडीयू अब झोला ढोने वालों की पार्टी बनकर रह गई है। पिछले एक साल से पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है। पहले जिलाध्यक्ष का चुनाव समय पर नहीं होता था। आज तो जिला, प्रखंड व बूथ स्तर पर अध्यक्ष बनाए गए हैं। जेडीयू में कार्यकर्ताओं की कोई इज्जत नहीं है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि इस डूबते हुए जहाज को छोड़ दें। आरसीपी सिंह ने कहा कि ऐसा नहीं है कि सांसद बनने से पहले वो काम नहीं करते थे, वो आईएएस थे। आज जो लोग पटना में परिक्रमा कर रहे हैं, वो कल तक पार्टी का विरोध करते थे। खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताते थे।

बहरहाल, इस्तीफा देने के बाद आरसीपी सिंह, जद(यू) और नीतीश कुमार पर जमकर बरसे थे। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार सात जन्मों में भी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। आरसीपी सिंह ने इस दौरान कई सवाल उठाए थे, जिसका जबाब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे दिया। ललन सिंह ने कहा कि जद(यू) डूबता नहीं बल्कि दौड़ता जहाज है। कुछ लोग जहाज में छेद कर रहे थे, लेकिन समय रहते जहाज के छेद की मरम्मत कर ली गई। उन्होंने कहा कि जेडीयू को 43 सीट आई ये साजिश की वजह से ऐसा हुआ। उन्होंने कहा कि हम लोग अब सतर्क हैं। 2020 में एक चिराग मॉडल आया था, अब एक और चिराग मॉडल तैयार करके षड्यंत्र किया जा रहा था। ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार की सीट घटाने के लिए साजिश रची जा रही है। जनता ने वोट देना कम नहीं किया, हमारे खिलाफ बड़े-बड़े पड्यंत्र किए गए। उन्होंने कहा कि आरसीपी सिंह जनता दल यूनाइटेड के बारे में जानते क्या हैं। आरसीपी सिंह कह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड डूबता हुआ जहाज है, मगर आने वाले वक्त में उनको पता चल जाएगा कि जनता दल यूनाइटेड भागता हुआ जहाज है। उन्होंने कहा कि आरसीपी सिंह सत्ता से बेदखल हो गए हैं इसीलिए उनको तकलीफ हो रही है। उन्होंने बीजेपी का नाम लिए बिना कहा कि आरसीपी सिंह का तन जनता दल यूनाइटेड में, मन कहीं और था। दिगर बात है कि ललन सिंह ने प्रेस वार्ता में बीजेपी के साथ पर कहा था कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है। उन्होंने कहा था कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में हमलोगों ने अभी भी पूरा साथ दिया है। 2019 में ही नीतीश ने सबसे परामर्श करके ही फैसला ले लिया था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे, लेकिन 2021 में आरसीपी सिंह ने मंत्रिमंडल में शामिल होने का फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते लिया। क्यों लिया? किससे परामर्श से किया? ये वही बता सकते हैं। इसके साथ ही साफ किया है कि अब जेडीयू मोदी कैबिनेट में शामिल नहीं होगा। बीजेपी के साथ जेडीयू के रिश्ते और मोदी कैबिनेट शामिल होने के सवाल पर ललन सिंह ने कहा था कि बीजेपी के साथ सब ठीक है। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को वोट दिया है। वहीं, आगे बीजेपी से गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि 2024 और 2025 में जदयू बीजेपी के साथ रहेगा या नहीं, भविष्य में या 2029 में क्या होगा, इसके बारे में हम अभी कैसे प्रतिबद्ध हो सकते हैं। दिगर बात हो कि प्रेस वार्ता के दो दिन बाद ही जदयू ने बीजेपी से नाता तोड़ते हुए पुनः राजद और उनके सहयोगी महागठबंधन के साथ एक बार फिर से सरकार बना ली है।

गौरतलब है कि जेडीयू से इस्तीफा देने के बाद आरसीपी सिंह क्या करेंगे? यह सवाल बिहार की सियासत में बड़ी तेजी से उठ रहा है। सूत्रों की माने तो आरसीपी सिंह आनेवाले लोकसभा चुनाव में नालंदा से किस्मत आजमा सकते हैं। दरअसल, आरसीपी सिंह ने इस्तीफा देने के बाद आगे की रणनीति पर फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोले हैं। सिर्फ यह संकेत दिया है कि वे कोई नया संगठन बनाकर आगे की राजनीति कर सकते हैं। आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद जदयू के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी पार्टी का साथ छोड़ दिया है। आरसीपी सिंह के बेहद करीबी कन्हैया सिंह ने भी जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। जदयू राज्य परिषद सदस्य मुन्ना सिद्की ने भी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता त्याग दी। इनके अलावा करीब एक दर्जन जदयू नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। आरसीपी सिंह के करीबी कन्हैया सिंह इस्तीफा देने के बाद आरसीपी सिंह को लेकर बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि आरसीपी सिंह नालंदा के बेटे हैं। उनकी जन्मभूमि नालंदा है, सो उनका स्वाभाविक हक बनता है। आरसीपी सिंह के समर्थकों की पूरी इच्छा है कि वे नालंदा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ें और उम्मीद भी है की आरसीपी सिंह नालंदा से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और उन्हें वहां से कोई नहीं हरा सकता है। उन्होंने कहा कि आरसीपी सिंह के साथ जो कुछ हो रहा है और हुआ है वह सबकुछ नालंदा की जनता देख रही है, जो वक्त आने पर जवाब देगी।

विडम्बना है कि एक तरफ आरसीपी सिंह राजनीति में बेघर हो गये हैं तो दूसरी ओर जेडीयू में चल रही गुटबाजी से पार्टी और उनके कार्यकर्ता फर्श पर आते दिख रहे है, चाहे इसमें सेंधमारी भाजपा ही क्यों न कर रही है, जैसा की संकेतों में जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने चिराग मॉडल के बाद आरसीपी मॉडल लाने का आरोप सहयोगी गठबंधन भाजपा पर लगा रही है। ऐसे में अब आरसीपी सिंह का इस्तीफा कितना मायने रखता है और देखना होगा कि जदयू और नीतीश कुमार के बिना क्या वह फिर से बिहार की राजनीति में पहले जैसा मुकाम हासिल कर पाएंगे? नौकरशाह से राजनेता बने आरसीपी सिंह कभी नीतीश कुमार के राइट हैंड माने जाते थे। वो आगे कौन सी राह चुनेंगे, ये अभी बड़ा सवाल है! ●

पूर्व मंत्री मंगल पाण्डेय को दाग क्यों अच्छे लगते हैं?

● शशि रंजन सिंह/राजीव शुक्ला

अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल आई०एस० ठाकुर और आयुर्वेद महाविद्यालय बेगूसराय के प्राचार्य पर यौन शोषण के गंभीर आरोप के बावजूद मंत्री के प्रिय पात्र बने रहें। पूर्व मंत्री मंगल पांडे को दाग क्यों अच्छे लगते हैं!यह विषय बहुत ही गंभीर विषय है। राजनीतिक सूचिता की बात करने वाली भाजपा के बड़े नेता हैं पूर्व मंत्री मंगल पांडे, लेकिन उनके मंत्रित्व काल में दागदार अधिकारी उनके प्रिय पात्र बने हुए थे। कार्यकारी राज्य औषधि नियंत्रक, रविन्द्र सिन्हा, पटना की सिविल सर्जन विभा सिंह, अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल आई०एस० ठाकुर, प्राचार्य आयुर्वेद कॉलेज पटना डा० संपूर्णानन्द तिवारी, प्रार्चाय आयुर्वेद कॉलेज बेगूसराय डॉ० उमाशंकर चतुर्वेदी, मंत्री महोदय की पत्नी के नाम पर कुख्यात संस्था उर्मिला इंटरनेशलन सर्विसेज प्रा०ली० के मालिक अविनाश कुमार, अधीक्षक दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल हरिशंकर मिश्रा ऐसे कई दागदार अधिकारियों के साथ मिलकर पूर्व मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य खराब कर दिया।

पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं

डॉ० आई.एस. ठाकुर

अस्पताल के अधीक्षक इंद्र शेखर ठाकुर, जिन पर फर्जी पी०एच०डी० डिग्री का आरोप लगभग प्रमाणित हो चुका है, जिनको स्वास्थ्य विभाग द्वारा फर्जी पी०एच०डी० डिग्री और बिस्फी में स्वास्थ्य अधिकारी रहते हुए लखनऊ के जाली आवासीय प्रमाण पत्र पर मास्टर ऑफ सर्जरी डिग्री प्राप्त करने के कारण निलंबित करते हुए विभागीय जाँच का आदेश दिया गया था, लेकिन अपने राजनीतिक पहुँच का इस्तेमाल करते हुए विभागीय जाँच को ठंडे बस्ते में रखते हुए पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल जैसे प्रतिष्ठित अस्पताल का अधीक्षक बना दिया गया। पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के अधीक्षक बनते ही इंद्र शेखर ठाकुर द्वारा पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल परिसर को शराब, सेक्स और भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया। सहायक मेट्रान हिरा कुमारी को निरा राडिया बनाकर अधीक्षक पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल ने अपने शारीरिक और आर्थिक जरूरतों को पूरा किया। पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के महिला

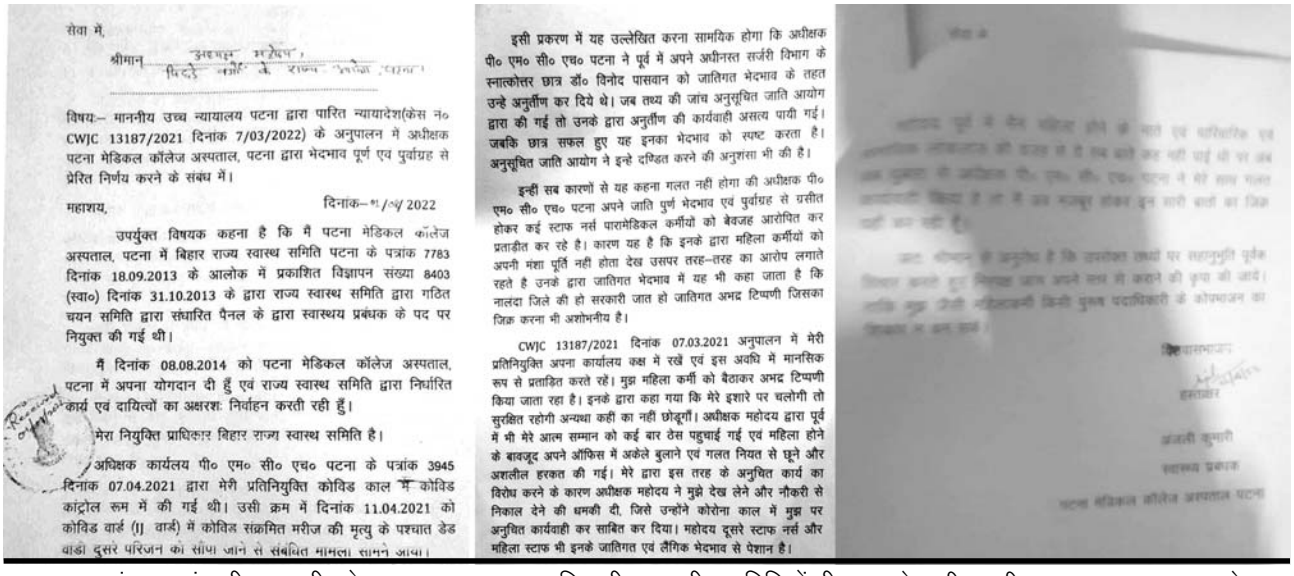

सेवा में,

श्रीमान अध्यक्ष महोदय, पिछड़े वर्गों के राज्य आयोग, पटना।

विषयः– माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित न्यायादेश(केस नं० CWJC 13187/2021 दिनांक 7/03/2022) के अनुपालन में अधीक्षक पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना द्वारा भेदभाव पूर्ण एव पुर्वाग्रह से प्रेरित निर्णय करने के संबंध में।

महाशय, दिनांक– / / 2022

उपर्युक्त विषयक कहना है कि मै पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना में बिहार राज्य स्वास्थ समिति पटना के पत्रांक 7783 दिनांक 18.09.2013 के आलोक में प्रकाशित विज्ञापन संख्या 8403 (स्वा०) दिनांक 31.10.2013 के द्वारा राज्य स्वास्थ समिति द्वारा गठित चयन समिति द्वारा संधारित पैनल के द्वारा स्वास्थय प्रबंधक के पद पर नियुक्त की गई थी।

मैं दिनांक 08.08.2014 को पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना में अपना योगदान दी हुँ एवं राज्य स्वास्थ समिति द्वारा निर्धारित कार्य एवं दायित्वों का अक्षरशः निर्वाहन करती रही हुँ।

मेरा नियुक्ति प्राधिकार बिहार राज्य स्वास्थ समिति है।

अधिक्षक कार्यलय पी० एम० सी० एच० पटना के पत्रांक 3945 दिनांक 07.04.2021 द्वारा मेरी प्रतिनियुक्ति कोविड काल में कोविड कांट्रोल रूम में की गई थी। उसी क्रम में दिनांक 11.04.2021 को कोविड वार्ड (IJ वार्ड) में कोविड संक्रमित मरीज की मृत्यु के पश्चात डेड बाडी दुसरे परिजन को सौंपा जाने से संबंधित मामला सामने आया।

इसी प्रकरण में यह उल्लेखित करना सामयिक होगा कि अधीक्षक पी० एम० सी० एच० पटना ने पूर्व में अपने अधीनस्त सर्जरी विभाग के स्नात्कोत्तर छात्र डॉ० विनोद पासवान को जातिगत भेदभाव के तहत उन्हे अनुर्तीण कर दिये थे। जब तथ्य की जांच अनुसूचित जाति आयोग द्वारा की गई तो उनके द्वारा अनुर्तीण की कार्यवाही असत्य पायी गई। जबकि छात्र सफल हुए यह इनका भेदभाव को स्पष्ट करता है। अनुसूचित जाति आयोग ने इन्हे दण्डित करने की अनुशंसा भी की है।

इन्हीं सब कारणों से यह कहना गलत नही होगा की अधीक्षक पी० एम० सी० एच० पटना अपने जाति पुर्ण भेदभाव एवं पुर्वाग्रह से ग्रसीत होकर कई स्टाफ नर्स पारामेडिकल कर्मीयों को बेवजह आरोपित कर प्रताडीत कर रहे है। कारण यह है कि इनके द्वारा महिला कर्मीयों को अपनी मंशा पूर्ति नही होता देख उसपर तरह–तरह का आरोप लगाते रहते है उनके द्वारा जातिगत भेदभाव में यह भी कहा जाता है कि नालंदा जिले की हो सरकारी जात हो जातिगत अभद्र टिप्पणी जिसका जिक्र करना भी अशोभनीय है।

CWJC 13187/2021 दिनांक 07.03.2021 अनुपालन में मेरी प्रतिनियुक्ति अपना कार्यालय कक्ष मे रखें एवं इस अवधि में मानसिक रूप से प्रताड़ित करते रहें। मुझ महिला कर्मी को बैठाकर अभद्र टिप्पणी किया जाता रहा है। इनके द्वारा कहा गया कि मेरे इशारे पर चलोगी तो सुरक्षित रहोगी अन्यथा कही का नहीं छोड़ूगाँ। अधीक्षक महोदय द्वारा पूर्व में भी मेरे आत्म सम्मान को कई बार ठेस पहुचाई गई एवं महिला होने के बावजूद अपने ऑफिस में अकेले बुलाने एवं गलत नियत से छूने और अशलील हरकत की गई। मेरे द्वारा इस तरह के अनुचित कार्य का विरोध करने के कारण अधीक्षक महोदय ने मुझे देख लेने और नौकरी से निकाल देने की धमकी दी, जिसे उन्होंने कोरोना काल में मुझ पर अनुचित कार्यवाही कर साबित कर दिया। महोदय दूसरे स्टाफ नर्स और महिला स्टाफ भी इनके जातिगत एवं लैंगिक भेदभाव से पेशान है।

हस्ताक्षर

अंजली कुमारी

स्वास्थ्य प्रबंधक

स्वास्थ्य प्रबंधक अंजली कुमारी ने जब अधीक्षक इंद्र शेखर ठाकुर के काम इच्छा को पुरा नहीं किया तो बिना कारण पृच्छा किये राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा नियुक्ति के बावजूद अधीक्षक द्वारा स्वास्थ्य प्रबंधक अंजली को बर्खास्त कर दिया गया।

महिला स्वास्थ्य प्रबंधक द्वारा विभिन्न आवेदनों में कहा गया कि मुझ महिला कर्मी को बैठाकर अधीक्षक द्वारा अभद्र टिप्पणी किया जाता रहा है। अधीक्षक द्वारा कहा गया कि मेरे इशारे पर चलोगी तो सुरक्षित रहोगी अन्यथा कहीं का नहीं छोडूँगा। अधीक्षक महोदय द्वारा पूर्व में भी मेरे आत्म–समान को कई बार ठेस पहुँचाई गई एवं महिला होने के बावजूद अपने ऑफिस में अकेले बुलाने एवं गलत नियत से छूने और अश्लील हरकत की गई। मेरे द्वारा इस तरह के अनुचित कार्य का विरोध करने के कारण अधीक्षक महोदय ने मुझे देख लेने और नौकरी से निकाल देने की धमकी दी, जिसे उन्होंने कोरोना काल में मुझ पर अनुचित कार्यवाही कर साबित कर दिया। अधीक्षक से दूसरे स्टाफ नर्स और महिला स्टाफ भी इनके जातिगत एवं लैंगिक भेदभाव से परेशान है। पूर्व में मैंने महिला होने के नाते एवं पारिवारिक एवं सामाजिक लोकलाज की वहज से ये सब बाते कह नहीं पाई थी पर अब जब दुबारा से अधीक्षक पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना ने मेरे साथ गलत कार्यवाही किया है, तो मैं अब मजबूर होकर इन सारी बातों का जिक्र यहाँ कर रही हूँ। स्वास्थ्य प्रबंधक ने अपने आवेदन में कहा कि अधीक्षक महोदय ने मेरी बर्खास्तगी के पश्चात त्री–सदस्यीय समिति गठित किये। ज्ञापांक– 4155, दिनांक– 11.04. 2021 द्वारा गठित त्री–सदस्यीय समिति में तीन विभागाध्यक्षों द्वारा उक्त प्रकरण की जाँच का फलाफल प्राप्त निष्कर्ष निम्नांकित है। CCTV फूटेज के अवलोकन एवं सभी संबंधित व्यक्तियों से ली गयी लिखित जानकारी के आलोक में प्रथम दृष्टया ट्रॉली मेन श्री नितीश कुमार एवं श्री महेश प्रसाद दोषी प्रतीत होते है, जिन्होंने अनिधिकृत तौर पर आई०जे० वार्ड के बेड नं० 9 के मरीज श्री चुन्नु कुमार का अन्यत्र स्थानांतरित कर दिये तथा इसकी सूचना ऑन ड्यूटी सिस्टर एवं डॉक्टर को नहीं दिया। पुनः बेड नं० 9 के उक्त खाली स्थान पर एक अन्य नये मरीज श्री राज कुमार भगत को एक साधारण बेड पर उक्त ट्रॉली मेन द्वारा रख दिया गया और इसकी सूचना सिस्टर एवं डॉक्टर को नहीं दी गई।

हीरा कुमारी

ऐसा प्रतीत होता है कि चुन्नु कुमार के अपने परिजन (चचेरा भाई) सदानन्द सुधाकर द्वारा शव को पहचानने में भुल हुई, जिसके कारण शव को गलत परिजनों ने प्राप्त किया। अधीक्षक पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल ने पूर्व में अपने अधीनस्त सर्जरी विभाग के स्नात्कोत्तर छात्र डॉ० विनोद पासवान को जातिगत भेदभाव के तहत उन्हें अनुर्तीण कर दिये थे। जब तथ्य की जाँच अनुसूचित जाति आयोग द्वारा की गई तो उनके द्वारा अनुर्तीण की कार्यवाही असत्य पायी गई जबकि छात्र सफल हुए। यह इनका भेदभाव को स्पष्ट करता है। अनुसूचित जाति आयोग ने इन्हें दंडित करने की अनुशंसा भी की है। इन्हीं सब कारणों से यह कहना गलत नहीं होगा कि अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना अपने जाति पूर्ण भेदभाव एवं पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कई स्टाफ नर्स, पारामेडिकल कर्मियों को बेवजह आरोपित कर अपनी मंशा पूर्ति नहीं होता देख उसपर तरह–तरह का आरोप लगाते रहते हैं। उनके द्वारा जातिगत भेदभाव में यह भी कहा जाता है कि नालंदा जिले की हो सरकारी जात हो जातिगत अभद्र टिप्पणी जिसका जिक्र करना भी अशोभनीय है। (यह कहना है महिला स्वास्थ्य प्रबंधक का)।

पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में माफिया राज चल रहा है। पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में एक माफिया

स्वास्थ्य अधिकारी हैं, जिनका पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में पद में मुख्य चिकित्सा अधिकारी (आवश्यक एवं केजुअल्टी) अभिजित सिंह, जो पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में पिछले 9–10 सालों से बने हुए हैं। पिछले कोरोना काल में इनका स्थानांतरण पटना में ही लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल में हुआ था, लेकिन उनके मुख्यमंत्री आवास तक पहुँच के कारण कुछ दिनों में ही पुनः इनका पदस्थापन फिर से पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में कर दिया गया। पूरे पटना में एंम्बुलेंस और नर्सिंग माफिया के साथ इनका संबंधों का खुलासा कई बार हो चुका है। पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के गरीब रोगियों को एंम्बुलेंस माफियाओं के मदद से निजि नर्सिंग होम में भेजना पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल प्रशासन पोषित माफियाओं का मुख्य पेशा है। पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में माफिया राज चल रहा है और इसका हिस्सा पूर्व मंत्री मंगल पांडे को भी जाता था। वहीं दूसरी तरफ राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, पटना के फर्जी प्राचार्य संपूर्णानन्द तिवारी का अन्तर–स्नातक, बी०ए०एम०एस० और पी०एज०डी० की डिग्री फर्जी है। उनको बिहार ही नहीं देश के प्रतिष्ठित आयुर्वेद कॉलेज का प्राचार्य पूर्व मंत्री मंगल

डॉ० संपूर्णानन्द तिवारी

पांडे के द्वारा बनाया गया है। जब इन मामले को लेकर राम किशुन साह ने माननीय पटना उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की तो न्यायालय के आदेश से जाँच शुरू हुआ तो स्वास्थ्य विभाग की लाडली उप सचिव महोदया रेणु कुमारी के द्वारा विभाग के विवादित, दागदार और रेणु कुमारी जो कि न्यायालय संबंधी कार्य का निपटारा करती हैं, के प्रिय अधिकारी डॉ० श्याम सुंदर सिंह जिनपर कई आरोप लगे हुए हैं और उन आरोपों की जाँच अभी लंबित है, उनको जाँच अधिकारी बना दिया गया। बिडंबना देखिए जब डॉ० श्याम सुंदर सिंह को रेणु कुमारी ने जाँच अधिकारी बनाया। उक्त आदेश में कहा गया कि वादी श्री राम किशुन साह द्वारा समर्पित अभ्यावेदन में जो लांछन लगाये गए हैं, उन बिन्दुओं की जाँच एवं सुनवाई का प्रतिवेदन उपलब्ध करवाया जाए। इस आदेश में लांछन शब्द का चयन ही कहीं ना कहीं रेणु कुमारी की मनोदशा को दर्शाता है। रेणु कुमारी के आदेशानुसार डॉ० श्याम सुदंर सिंह द्वारा वादी को परेशान किया जाने लगा। साथ ही वादी को प्रलोभन और धमकी भी दिया जाने लगा। इन तथ्यों से साफ स्पष्ट है कि इस जाँच की दिशा और दशा क्या होगी ?

राजकीय आयोध्या शिवकुमारी आयुर्वेद महाविद्यालय सह चिकित्सालय, बेगूसराय के पूर्व परिचारी रूपम कुमारी द्वारा सभी जनता से अपील के नाम एक पर्चा छपावाकर पूरे बिहार में बाँटा गया, जिसमें प्राचार्य डॉ० उमाशंकर चौधरी पर यौन शोषण सहित कई गंभीर आरोप लगाये गए हैं। केवल सच इन आरोपों की सत्यता को सत्यापित नहीं करता है, लेकिन इस तरह के आरोप से संस्थान एवं राज्य की प्रतिष्ठा धूमिल होती है। इसलिए इन आरोपों की जाँच ईमानदारीपूर्वक बिना कोई दवाब की होनी चाहिए। भाजपा, जो खुद को हिन्दु धर्म का रक्षक कहती है, उसी भाजपा के प्रधानमंत्री, जो पूरी दुनिया में आयुर्वेद का डंका बजवाने का दम भरते है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बिहार में 2005

संoसंo–होoजांच फोल्डर/01/2022– 55/निoहोoकोo
आयुष निदेशालय
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

प्रेषक,
डाo श्याम सुन्दर सिंह,
निदेशक होमियोपैथी

सेवा में,
राम किशुन साह,
पिता–स्वo जानकी साह,
ग्राम–पिन्दौता खुर्द, पोo–तिसिऔटा,
जिला–वैशाली, बिहार

पटना, दिनांक – 13/07/2022

विषय :– दिनांक 20.07.2022 को बैठक में उपस्थित होने के संबंध में।
प्रसग :–स्वारथ्य विभागीय आदेश संख्या– 775(आoचिo) दिनांक 28.06.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध मे कहना है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय मे दायर समादेश याचिका (PIL) संख्या–3422/2022 मे दिनांक 11.03.2022 को आदेश पारित किया गया है। पारित आदेश के आलोक में आपके द्वारा दिनांक 05.04.2022 को विभाग में अभ्यावेदन समर्पित किया गया है जिस पर अग्रत्तर कार्रवाई की जा रही है।

स्वारथ्य विभागीय आदेश संख्या– 775(आoचिo) दिनांक 28.06.2022 द्वारा आपके अभ्यावेदन में लगाये गये लांछन के विन्दुवार जाँच एवं सुनवाई हेतु दोनों निदेशकों की एक संयुक्त समिति गठित की गयी है। संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 13.07.2022 को आपके द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के समीक्षोपरांत आपकी सहयोग की आवश्यकता हुई है।

अतः अनुरोध है कि मामला पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.03.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में आपके सहयोग एवं बिन्दुवार विचार–विमर्श करने हेतु दिनांक 20.07.2022 को 12.30 बजे अपo में निदेशक होमियोपैथी कोषांग में एक बैठक आयोजित की गयी है। उक्त बैठक मे ससमय आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। कृपया आपके द्वारा समर्पित अभ्यावेदन में प्राचार्य, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, पटना (डाo सम्पूर्णानन्द तिवारी) के विरूद्ध लगाये गये आरोप से संबंधित पुख्ता साक्ष्य के साथ उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थिति होने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
13/7/2022
(डाo श्याम सुन्दर सिंह)
निदेशक होमियोपैथी

13-07-2022
निदेशक, आयुर्वेद

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
।। आयुष निदेशालय ।।
आदेश

संoसंo–16/सीo1–32/2022– 775(आoचिo) दिनांक– 28/06/2022

माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर समादेश याचिका (PIL) संख्या–3422/2022 में दिनांक–11.03.2022 को पारित आदेश के आलोक में वादी श्री राम किसुन साह द्वारा समर्पित अभ्यावेदन में लगाये गये लांछन के बिन्दुओं की जाँच एवं सुनवाई कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु दो सदस्यीय सम्मिलित समिति का गठन निम्नरुपेण किया जाता है :

1. डा० श्याम सुन्दर सिंह – निदेशक, होमियोपैथ – सदस्य
2. डा० राजेश्वर सिंह – निदेशक, आयुर्वेद – सदस्य

2. उक्त समिति एक माह के अन्दर स्पष्ट मंतव्य के साथ अपना प्रतिवेदन समर्पित करेगी।

ह०/–
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक :– संoसंo–16/सीo1–32/2022 –775(आoचिo) पटना, दिनांक 28.6.22

प्रतिलिपि :– निदेशक, होमियोपैथ/आयुर्वेद, आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य विभाग/वादी श्री राम किसुन साह, S/O स्व० जानकी साह, ग्राम–पिन्दौता खुर्द, पोस्ट–तिसिऔटा, जिला–वैशाली, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी

में बनी है। लगभग 15 सालों से स्वास्थ्य विभाग भाजपा के पास ही रहा है। इन 15 सालों में लालू यादव को विकास विरोधी बताने वाले भाजपा ने किस तरह आयुर्वेद का बेड़ा गर्क किया है, हम आपको बिन्दुबार बता रहे हैं :–

☞ डॉ० (प्रो०) विजय शंकर दूबे, अधीक्षक, राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल, पटना।

☞ डॉ० धन्नजय शर्मा, उपाधीक्षक, राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल, पटना।

☞ डॉ० शिवादित्य ठाकुर, स्नातक, अनुसंधान पदाधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अनुसंधान ईकाई, पटना।

☞ डॉ० (श्रीमती) किरण शुक्ला, स्नातक, अनुसंधान चिकित्सा पदाधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अनुसंधान ईकाई, पटना।

☞ डॉ० वैद्यनाथ तिवारी, स्नातक, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल, पटना। आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी, पटना।

☞ डॉ० सुनीता कुमारी, स्नातक, आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल, पटना।

☞ डॉ० शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय, स्नातक, आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल, पटना।

☞ डॉ० उदय नारायण पाठक, स्नातक, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल, पटना, आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी, पटना।

☞ इन सभी के वरीयता क्रम को दर–किनार कर पदस्थापित किया गया।

☞ डॉ० (प्रो०) दिनेश्वर प्रसाद, प्राचार्य, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, पटना जो जाति के नोनियार है, उनको हटाकर, डॉ० सम्पूर्णानन्द तिवारी को प्राचार्य, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, पटना बनाया गया है।

☞ डॉ० दिनेश्वर प्रसाद, प्राचार्य राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, पटना से स्थानान्तरण करते हुए राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, दरभंगा में पदस्थापित किया गया है।

☞ डॉ० दिनेश्वर प्रसाद का सेवानिवृत्ति दिनांक 31.01.2023 को है। मात्र डेढ़ साल बच गया है।

☞ राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, दरभंगा 15 वर्षों से बंद है।

☞ डॉ० दिनेश्वर प्रसाद की पत्नी किडनी रोग से ग्रसित है, जिनका ईलाज चल रहा है।

☞ डॉ० सम्पूर्णानन्द तिवारी का जी०ए०एम०एस० डिग्री पी०एच०डी० डिग्री तथा एम०डी० उपाधि अवैध एवं अमान्य है।

☞ डॉ० तिवारी का जन्मतिथि 23.10.1957 है।

अभिषेक सिंह

जी०ए०एम०एस० पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 15 वर्ष निर्धारित है। उन्होंने मात्र 13 वर्ष की आयु में जी०ए०एम०एस० पाठ्यक्रम में नामांकन लेकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर से वर्ष 1976 में जी०ए०एम०एस० डिग्री प्राप्त किये है। उनका जी०ए०एम०एस० डिग्री अवैध है।

☞ डॉ तिवारी सत्र 1970–76 में जी०ए०एम०एस० पाठ्यक्रम में अध्ययनरत थे तथा उन्होंने सत्र 1975–77 में इन्टरमीडिएट में नामांकन लेकर 1977 में इन्टरमीडिएट बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर से पास किये एवं इन्टर्नशिप प्रशिक्षण भी कर रहे थे। एक ही साथ जी०ए०एम०एस०, इन्टरमीडिएट एवं इन्टर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। उनकी सारी डिग्री अवैध है।

☞ डॉ सम्पूर्णानन्द तिवारी कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरंभगा से वर्ष 2005 में पी०एच०डी० उपाधि प्राप्त किये है। भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली के द्वितीय उपसूची में कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा से प्राप्त पी०एच०डी० उपाधि की मान्यता 1974 से 1988 है। डॉ० तिवारी का पी०एच०डी० डिग्री अमान्य है।

☞ डॉ० तिवारी, जिनका राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, पटना में द्रव्यगुण विषय में एम०डी० पाठ्यक्रम चल रहा था, उन्होंने केन्द्रीय कोटा से पंचकर्म विषय में एम०डी० करने हेतु आवेदन दिया तथा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर से द्रव्यगुण विषय में एम०डी० उपाधि प्राप्त किये। इस आधार पर उनका एम०डी० डिग्री अमान्य है।

☞ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तीन वर्ष का है। डॉ० तिवारी ने त्रिवर्षीय एम०डी० डिग्री को दो वर्ष से कम में ही प्राप्त कर लिये।

☞ डॉ० सम्पूर्णानन्द तिवारी जब प्रभारी प्राचार्य राजकीय यतीन्द्र नारायण अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज, नाथनगर, भागलपुर में पदस्थापित थें, तो उन्होंने तीस लाख रूपये की अवैध निकासी किये थे।

☞ तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव श्रीमती बी. भामथी ने पत्रांक –200, दिनांक– 17.09.2005 के द्वारा डॉ. तिवारी द्वारा किये गये वित्तीय अनियमितता एवं अन्य मामले पर जाँच करायी गई सभी आरोप सही पाये गये, परन्तु स्वास्थ्य विभाग द्वारा आजतक कोई कार्रवाई नहीं की गई।

☞ राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज की स्थापना 26 जुलाई 1926 को हुई। इस महाविद्यालय में आठ विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चल रहा है तथा छः विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रस्तावित है।

☞ राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल, पटना राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज का संलग्न अस्पताल है। राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल पटना में सभी परामर्शी चिकित्सक स्नातकोत्तर उपाधि (एम.डी.) धारी है तथा सभी विषयों के स्नातकोत्तर शोध छात्र अपने ड्रग का ट्राईल कर रहे है। राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल, पटना के आवासीय चिकित्सा पदाधिकारी/चिकित्सा पदाधिकारी के लिए स्नातकोत्तर उपाधि अनिवार्य है।

☞ श्री मंगल पांडे, मंत्री स्वास्थ्य ने सभी नियमों को ताक पर रखकर स्नातकोत्तर उपाधि के स्थान पर स्नातक, आवासीय चिकित्सा पदाधिकारी एवं चिकित्सा पदाधिकारी को पदस्थापित कर दिया है।

☞ डॉ. (प्रो.) दिनेश्वर प्रसाद, प्राचार्य, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, पटना इन्होंने सभी बिन्दुओं को उठाते रहे, उन्हें 15 वर्ष से बंद राजकीय भारतीय चिकित्सा संस्थान, मोहनपुर, दरभंगा में पदस्थापित कर दंडित किया गया है।

☞ डॉ. दिनेश्वर प्रसाद दिनांक 07.09.2016 से राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, पटना के प्राचार्य थे। उन्होंने पटना आयुर्वेदिक कॉलेज, पटना को जमीन से उठाकर आसमान में पहुँचा दिया।

☞ डॉ. प्रसाद के समय में स्नातक पाठ्यक्रम में 38 छात्र के स्थान पर 100 छात्रों का नामांकन फिर 125 छात्रों का नामांकन होने लगा तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में 8 विषयों में 48 स्नातकोत्तर शोध छात्रों का नामांकन शुरू हो गया। महाविद्यालय से छः माह पर कॉलेज पत्रिका का प्रकाशित होना और अनेकों महत्वपूर्ण कार्य किये है।

☞ डॉ. धन्नजय शर्मा, उपाधीक्षक, राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल, पटना वरीयता सूची में सब से कनीय है। पैसा एवं पैरवी के दम पर उपाधीक्षक के पद को सुशोभित कर रहें हैं। वरीय चिकित्सक मुँह देख रहे है। उपाधीक्षक पद के लिए स्नातकोत्तर उपाधि एक अनिवार्य योग्यता है। डॉ. शर्मा स्नातक होते हुए उपाधीक्षक बने हुए हैं।

☞ डॉ. शिवादित्य ठाकुर, अनुसंधान पदाधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अनुसंधान ईकाई पटना वरीयता सूची में सबसे कनीय होते हुए अनुसंधान पदाधिकारी के पद को सुशोभित कर रहे है। अनुसंधान पदाधिकारी के लिए स्नातकोत्तर उपाधि अनिवार्य है। बिना एम.डी. योग्यता के अनुसंधान पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित है।

☞ डॉ. (श्रीमती) किरण शुक्ला बिना स्नातकोत्तर उपाधि आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित किये गये है। इस पद के लिए एम.डी. उपाधि अनिवार्य है। सारा नियम एवं अधिनियम ध्वस्त हो चुका है।

☞ डॉ. (प्रो.) विजय शंकर दुबे, अधीक्षक, राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल, पटना, माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, श्री मंगल पांडे के बहनोई लगते हैं।

☞ राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल, पटना में बहिरंग विभाग में सभी स्नातकधारी चिकित्सकों की ड्यूटी लगाई जाती है और स्नातकोत्तर शोध छात्र अपना रिसर्च के लिए ड्रग ट्रायल बहिरंग विभाग से करते हैं। स्नातक चिकित्सक पी.जी. छात्रों को कैसे गाइड कर सकते हैं, जबकि उन्हें अनुसंधान के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है।

★ राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल, पटना में स्नातकोत्तर उपाधि धारक :–

☞ डॉ. (प्रो.) विजय शंकर दुबे, एम.डी. (द्रव्यगुण), अधीक्षक, राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल, पटना

☞ डॉ. अरूण कुमार सिंह, एम.डी. (द्रव्यगुण), आवासीय चिकित्सा पदाधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल, पटना

☞ डॉ. राम बाबू पासवान, एम.डी. (द्रव्यगुण), आवासीय चिकित्सा पदाधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल, पटना

ऐसी भेदभाव पूर्ण स्थिति, नियम के प्रतिकूल पदस्थापन से किस प्रकार आयुर्वेद कॉलेज एवं अस्पताल की उन्नति संभव है। कुल मिलाकर पिछले 17 सालों में भाजपा के मंत्री, खासकर पूर्व मंत्री मंगल पांडे ने स्वास्थ्य विभाग का बेड़ा गर्क कर दिया।

सभी जनता से अपील

मैं राजकीय अयोध्या शिवकुमारी आयुर्वेद महाविद्यालय सह चिकित्सालय बेगूसराय में चल रहे अनैतिक अनाचार एवं भ्रष्टाचार से जुड़े मामले मे अतिचार ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि यहाँ के प्राचार्य डॉ0 उमाशंकर चतुर्वेदी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार, यौनशोषण एवं घृणित जातिवाद का नंगा नृत्य किया जा रहा है। प्राचार्य जो रंगा सियार है, अपने अवैध जरूरतों को पूरा करने और यहाँ के महिला कर्मचारियों को अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए अपने जैलाही चरित्र से गंदे किस्म का आदमी शंभू प्रसाद सिंह को रखे हुए है। मैं इसकी जाँच कर दोषी को सजा देने का अनुरोध कर रही हूँ।

प्राचार्य डॉ0 उमाशंकर चतुर्वेदी का इतिहास बहुत ही गंदा है। इसने अपने पटना आयुर्वेद कॉलेज के पदस्थापित काल में कॉलेज की ही डॉ0 उमा पाण्डेय को पटाया और उसको घर बुलाकर खुलकर यौनाचार करने लगा, इसको उसकी डॉक्टर पत्नी बर्दास्त नही कर पाई और उन्होने शरीर में आग लगा ली, ईलाज के दौरान डॉ0 उमाशंकर चतुर्वेदी ने ही पॉयजन की सूई देकर मौत के घाट उतार दिये।

डॉ0 उमा पाण्डेय भी अपने पति को छोड़कर अलग हो गई और यह पटना आयुर्वेद कॉलेज में प्रोफेसर है और दोनो खुल्लम खुल्ला यौनाचार में लीन रह रही है।

राजकीय अयोध्या शिवकुमारी महाविद्यालय सह चिकित्सालय बेगूसराय में प्राचार्य बनने के बाद अपने ही तरह के अय्याश शंभू प्रसाद सिंह को पटा लिया जो उसके लिए शराब एवं शबाब का व्यवस्था करता है। मालुम हो कि शंभू प्रसाद सिंह रोज शाम कॉलेज के अन्दर प्राचार्य के सहयोग से दारू पीता है और अय्याशी करता है। शंभू प्रसाद सिंह प्राचार्य के डेरा तक रोज दारू और लड़की को पहूँचाता है। इस कॉलेज में बहुत सी विधवा एवं निःसहाय महिला काम करती है जिसे शंभू प्रसाद सिंह पहले खुद यौन शोषण करता है और फिर प्राचार्य के डेरा पर पहूँचाता है। इसी मे एक मैं भी थी रूपम कुमारी मुझे लगभग 5 साल पहले खाना बनाने के नाम पर प्राचार्य के डेरा पर पहूँचाया गया और चाय में नशा मिलाकर डॉ0 उमाशंकर चतुर्वेदी मेरी इज्जत लूट लिया और लगभग तीन साल तक मुझे (रूपम कुमारी) को पत्नी की तरह रखने के बाद मुझे गर्भवती होने पर कॉलेज के नौकरी और डेरा दोनो से निकाल दिया इसके बाद मैं रूपम कुमारी ने प्राचार्य पर बलात्कार करने एवं पत्नी की तरह रखने का मुकदमा किया जो न्यायालय में चल रहा है, इस मामले में भारी रकम खर्च कर प्राचार्य मुकदमा रफा दफा करने का अथक प्रयास किया परन्तु प्राचार्य सफल नही हो पाया एवं कोर्ट में केश ऑडर पर है। अपने अय्याशी को जारी रखने के लिए प्राचार्य ने गंदा चरित्र के कर्मचारी शंभू प्रसाद सिंह को रिटायर होने के बाद भी अच्छे चरित्र प्रमाण पत्र एवं विभाग में मोटी रकम देकर पुनः संविदा शिक्षक पद पर बहाल कर लिया मालुम हो कि महाविद्यालय के कर्मचारी डोली सिन्हा एवं रूपम कुमारी ने शंभू प्रसाद सिंह पर गलत नियत से तंग करने का लिखित आरोप लगायी थी जिसे प्राचार्य ने जाँच का आरोप लगाकर खत्म कर दिया, हाल के दिनों में इसने वैष्णवी कम्पनी के 56 कर्मचारी को हटाकर फिर उसी कम्पनी से पैसा लेकर बहाल कर दिया, शंभू प्रसाद सिंह के नेतृत्व में ज्यादातर विधवा एवं लाचार महिला को ही रखा गया है, ताकि उनको डरा धमका कर उनकी मजबुरी का फायदा उठाकर उन सभी कर्मी का शोषन करवाते रहें जो कि रोस्टर एवं नियमाकुल नही है पुरूष के अपेक्षा महिला की संख्या ज्यादा रखना।

विश्वाराभाजन

रूपम कुमारी (पूर्व परिचारी)
रा0 अ0 शि0 आ0 महा0 सह चि0, बेगूसराय
ग्राम+पोस्ट : मोहनपुर, थाना : मुफस्सिल
जिला : बेगूसराय, बिहार, पिन नं0-851131

अब नई सरकार बनी है। तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री बनाये गए हैं। अब तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार से बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी है। केवल सच को नये स्वास्थ्य मंत्री से आशा है और केवल सच उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएँ देता है। केवल सच नये स्वास्थ्य मंत्री के पास भी स्वास्थ्य विभाग के भ्रष्टाचार की पोल खोलते रहेगा और आशा करेगा कि भ्रष्टाचार पर मंत्री महोदय द्वारा कार्रवाई भी होता रहे। ●

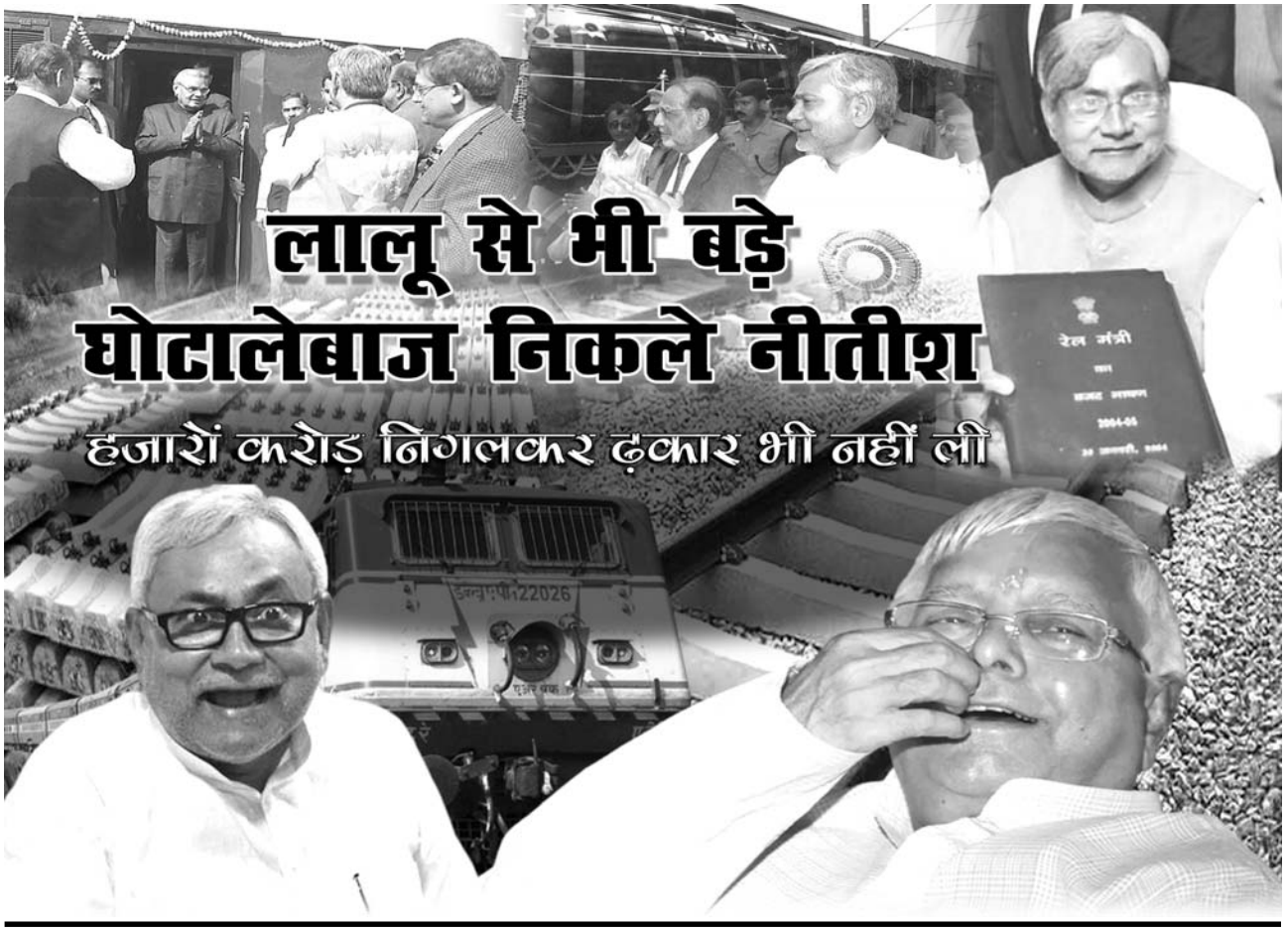

लालू से भी बड़े घोटालेबाज निकले नीतीश

हजारों करोड़ निगलकर ढ़कार भी नहीं ली

● शशि रंजन सिंह/राजीव शुक्ला

लालू यादव के रेल मंत्री काल की जाँच सी.बी.आई. कर रही है और इसमें कई दर्जन केस सी.बी.आई. द्वारा दर्ज की जा चुकी है। खुद पूर्व रेल मंत्री लालू यादव, उनकी पत्नी पूर्व मुख्य मंत्री रावड़ी देवी, बिहार के उप मुख्य मंत्री तेजस्वी यादव और लालू यादव के प्रिय पात्र पूर्व विधायक भोला यादव सहित कई आरोपियों पर सी.बी.आई. दर्जनों प्राथमिकी दर्ज कर चुकी है, लेकिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पूर्व रेल मंत्री नीतिश कुमार के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया जा सका है। जबकि महालेखाकार और सी.बी.आई. द्वारा हजारों करोड़ रूपये के घोटाले और वित्तीय अनियमितता प्रमाणित हो चुके हैं। 2004 से 2009 भारत के रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव थे। उन्होंने भी सी.बी.आई. को जल्द–से–जल्द जाँच पूरा कर दोषियों पर कार्रवाई का आदेश दिया था। सबसे बड़ी बात है कि हमाम में सभी राजनीतिक पार्टी नंगे हैं। हम यह बात यू हीं नहीं कह रहे हैं। स्लीपर घोटाले की कम्पनी गया के मेसर्स दया इंजिनियरिंग वर्कस् के

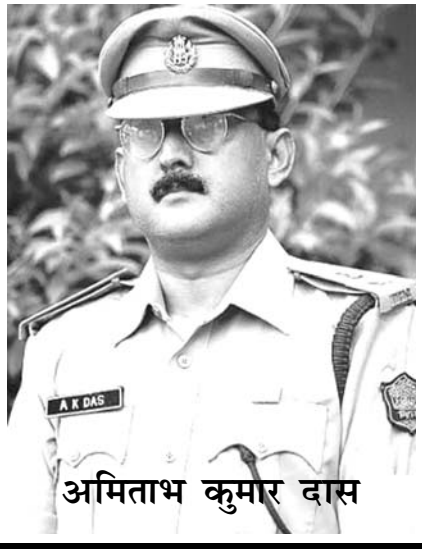

अमिताभ कुमार दास

मालिक दयानंद सहाय और धिरेन्द्र अग्रवाल राजद, भाजपा, काँग्रेस तीनों के बारी–बारी से सांसद रह चुके हैं। चूंकि दया इंजिनियरिंग वर्कस्, जिसके कारण हजारों रूपये का स्लीपर घोटाला हुआ, उनके दोनों मालिक धिरेन्द्र अग्रवाल और दयानंद सहाय ने बारी–बारी से सभी पार्टियों को लाभांवित किया। अब विडंबना देखिए कि रेलवे के छोटे–मोटे घोटाले में लालू यादव एवं उनके परिवार को सी.बी.आई. प्राथमिकी दर्ज कर तंग कर रही है, लेकिन राजनीतिक स्वार्थवश लालू यादव या उनके परिवार के कोई भी सदस्य नीतिश कुमार के रेल मंत्रित्व काल के घोटाले पर चुपी साधे हुए है।

हमाम में सभी पार्टियाँ नंगी है। इस संबंध में भाजपा नेता–सह–सांसद, राज्य सभा सुशील कुमार मोदी ने स्लीपर घोटाले की जानकारी नहीं होने की बात की है। रेलवे की लोक सभा की स्थाई समिति के अध्यक्ष–सह–भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सासंद

हमाम में सभी राजनीतिक पार्टी नंगे हैं।
2001–2004 के रेल मंत्रित्व काल में नीतीश कुमार द्वारा कई हजार करोड़ के घोटाले किये गए और फर्जी नियुक्ति की गई।

ब्रह्मानंद मंडल

नागमणी

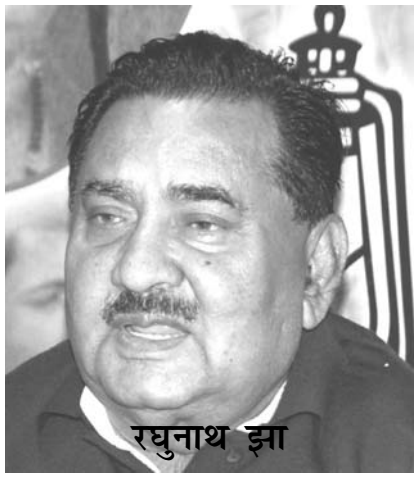
रघुनाथ झा

राधामोहन सिंह और भाजपा के दरभंगा के सासंद–सह–रेलवे की लोक सभा के स्थाई समिति के सदस्य गोपाल जी ठाकुर से बार–बार सम्पर्क करने और उनके सहायक को इस मामले की पूरी जानकारी दिये जाने के बावजूद भी कुछ भी बोलने से इंकार कर दिया। चूंकि यह घोटाला एन.डी.ए. के शासन काल में हुई थी और दया इंजिनियरिंग वर्कस् के मालिक धिरेन्द्र अग्रवाल भाजपा के भी सांसद रह चुके हैं, इसलिए भाजपा ने भी इस मुद्दे को पिछले 18 सालों से दबा कर रखा है।

तत्कालीन रेल पुलीस अधीक्षक, अमिताभ दास द्वारा मामले को संज्ञान में लाये जाने के कारण नीतिश कुमार द्वारा उन्हें जबरिया सेवा निवृत्ति दे दिया गया था। इस मामले को संज्ञान में लाने वाले समाजिक एवं आर.टी.आई. कार्यकर्त्ता मिथलेश सिंह की भी मृत्यु हो चुकी है। नये राजनीतिक परिवेश में बिहार के भाजपा नेता कुछ बोलने से इंकार कर रहे हैं, लेकिन केवल सच को मिली गुप्त स्त्रोत से जानकारी के अनुसार भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे मामले को अपने हैण्ड ओवर कर लिया है। जल्द ही सी.बी.आई. प्राथमिकी दर्ज कर दोषियों को गिरफ्तार कर सकती है, जिससे देश भर में बहुत बड़ी राजनीतिक उथल–पुथल होने की संभावना है। चूंकि यह मामला एन.डी.ए. शासन काल का है, इसलिए विपक्षी पार्टियाँ भी इसमें राजनीतिक रोटी सेक सकती है।

हाल के दिनों के राजनीतिक घटनाक्रम के कारण भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहेगी। भारतीय जनता पार्टी की रणनिती है कि नीतिश कुमार के ईमानदारी का मुखौटा जल्द–से–जल्द उतर सके। नीतिश कुमार और उनकी पार्टी

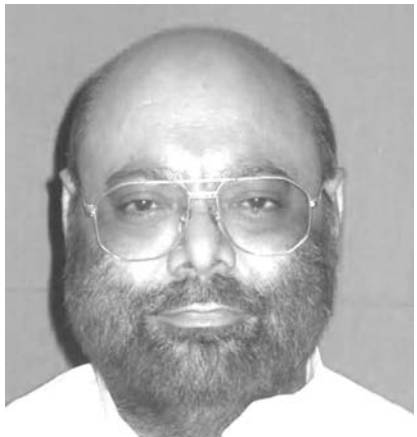
धीरेन्द्र अग्रवाल

78

प्रधान मंत्री
Prime Minister

New Delhi
April 23, 2003

Dear Shri Mandal,

I have received your letter of April 9, 2003 which has also been signed by Shri Raghunath Jha, MP, alleging irregularities and corrupt practices in the Ministry of Railways.

With regards,

Yours sincerely,

(A.B. Vajpayee)

Shri Brahmanand Mandal, MP
14-C, Ferozeshah Road
New Delhi – 110 001

*IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI

Date of decision: 7th July, 2014

%

W.P.(C) 1618/2014

\+

MITHLESH KUMAR SINGH ..... Petitioner
Through: Mr. Sudhir Nandrajog, Sr. Adv. with Mr. Avdhesh Kumar Singh and Mr. M.K. Singh, Advs.

Versus

UNION OF INDIA & ORS ..... Respondents
Through: Mr. R.V. Sinha and Mr. A.S. Singh, Advs. for R-1,3&4.
Mr. Sachin Datta with Ms. Ritika Vhurani, Advs. for UOI.
Mr. P.K. Sharma with Mr. Rakesh Kumar Sharma and Ms. Renu Malik, Advs. for R-6/CBI.

CORAM :-
HON'BLE THE CHIEF JUSTICE
HON'BLE MR. JUSTICE RAJIV SAHAI ENDLAW

RAJIV SAHAI ENDLAW, J.

1. This petition, filed by way of a Public Interest Litigation (PIL) seeks (i) a direction to the Ministry of Railways, Railway Board, Prime Minister Office, Lok Sabha Secretariat, the Director, CBI and the Planning Commission of India to provide the details of documents relating to purchase of jacks, appointment of candidates in the Railway Recruitment Board, Patna, financial irregularities in extension of railway line and scam in procurement of concrete sleepers in Railways during the tenure of respondent no.7 Mr. Nitish Kumar as Union

W.P.(C) 1618/2014 Page 1 of 4

Minister for Railways; and, (ii) a direction to the respondent no.6 Director, CBI to register the case against the respondent no.7 and his other associates.

2. The petitioner, on the same facts had earlier also filed W.P.(C) No.8919/2011 and which was dismissed vide order dated 21st December, 2011, accepting the version of the respondents that the matter had been referred to CBI for investigation and the CBI had not found any substance in the matter and had submitted report that no action was warranted in the case and which report was ultimately accepted. The petitioner thereafter sought information under the Right to Information Act, 2005 (RTI Act) and then sought review of the order of dismissal of the earlier writ petition on the ground that it was misrepresented before this Court that the matter had been referred to the CBI or that the CBI had not found any substance therein and which report was accepted. The said review petition came up before this Court on 7th December, 2012 when the counsel for the respondent Railways showed in confidence the records brought to the Court to the Bench then hearing the matter and on perusal thereof this Court recorded that the same disclosed that a CBI inquiry was indeed conducted and the report of the CBI was placed before the Standing Committee of the Railways. In view thereof the said review petition was dismissed, as aforesaid on 7th December, 2012.

W.P.(C) 1618/2014 Page 2 of 4

3. The petitioner again pursued his remedies under the RTI Act and on the basis thereof claims that there is no record of the matter having been placed before the Railway Board or having been enquired into / investigated by the CBI. Pleading so, this writ petition has been filed.

4. This Court (in the order dated 7th December, 2012 of dismissal of the review petition aforesaid) having observed that the records shown to it disclosed that a CBI inquiry was indeed conducted and that the report of the CBI was placed before the Standing Committee of the Railways, the contention today, of the CBI inquiry having not been conducted and the report thereof having not been placed before the Standing Committee of the Railways, cannot be accepted. The petitioner is thus not entitled to second or third round of litigation on the same aspect, as is being sought to be done.

5. We have otherwise also enquired from the senior counsel for the petitioner as to why the petitioner is targeting the respondent no.7 for the last nearly three years by filing one proceeding after another and what is the source of knowledge and information of the petitioner relating to affairs qua which commission of offences is alleged.

W.P.(C) 1618/2014 Page 3 of 4

6. No plausible answer has been forthcoming. We suspect the petition to be motivated and not in public interest and are not inclined to entertain the same on this ground also.

7. Even otherwise it has been held in ***Sakiri Vasu Vs. State of U.P.*** (2008) 2 SCC 409 that the High Courts, in exercise of powers under Article 226 of the Constitution of India, should not encourage rushing to the Court against non-registration of FIRs, the remedy whereagainst is to approach the Superintendent of Police under Section 154(3) Cr.P.C. or other police officers referred to in Section 36 Cr.P.C. and if despite that the grievance persists, to approach the Magistrate under Section 156(3) Cr.P.C. and if still dissatisfied, to file a criminal complaint under Section 200 Cr.P.C.

8. We have enquired from the senior counsel that why the petitioner in the last three years has not taken either of the aforesaid measures.

9. Again no response is forthcoming.

10. There is no merit in the petition which is dismissed. We refrain from imposing any costs.

RAJIV SAHAI ENDLAW, J.

CHIEF JUSTICE

JULY 07, 2014/pp

W.P.(C) 1618/2014 Page 4 of 4

c/o 3\ 11.7.14

WRIT/D-3

COPY OF ORDER/STAY/DASTI No. 19351-42/Q DHC/WRITS/D-3/2014

Dated 19-7-14

NDOH ______

From,
The Registrar General
Delhi High Court
New Delhi

To,
R1 to R6 & R8

CIVIL MISC. PETITION NO.- ____________

IN/AND

WRIT PETITION (C) NO.- 1618/14

Please see M.O.P. ...Petitioner/s

Vs.

...Respondent/s

Sir,

In continuation to this Court's letter No. ______ dated ______
I am directed to forward herewith for information and immediate compliance/necessary action a copy of order dated 7-7-14 passed by Hon'ble Division Bench of this Court in the above noted case along with a copy of memo of parties.

Please acknowledge receipt.

Yours faithfully,
Assistant Registrar
for Registrar General

Encl. As above

BR/11.7.2014

IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI

Copy of order

No. ____________/DHC/WRITS/D-3/2014
Dated ____________

From
The Registrar General
Delhi High Court
New Delhi

To

1. Union of India, through M/o Railways, Rail Bhawan, New Delhi
2. Planning Commission of India, Through its Secretary, Yojana Bhawan, Sansad Marg, New Delhi-1
3. Prime Minister Office, Through its Secretary, South Block, Raisina Hill, New Delhi
4. The Railway Board, Through its Chairman, Rail Bhawan, New Delhi
5. Lok Sabha Secretariat, Through its Secretary General, Parliament House, New Delhi
6. The Director CBI, CBI Policy Division, North Block, Room No. 27, New Delhi
7. Ministry of Home Affairs, Through its Secretary, North Block, Central Secretary, New Delhi

WRIT PETITION (C) NO. 1618/2014

Mithlesh Kumar Singh ....Petitioner/s
Vs.
UOI & others ....Respondent/s

Sir,

I am directed to forward herewith for information and immediate compliance/necessary action a copy of order dated 7.7.2014 passed by Hon'ble Division Bench of this Court in the above noted case alongwith a copy of memo of parties.

Please acknowledge receipt.

Yours faithfully,
Asstt. Registrar (Writs)
for Registrar General

लालू यादव और उनकी पार्टी के तरह मजबूत नहीं है, भाजपा यह बखूबी जानती है। नीतिश कुमार के जेल जाते ही नीतिश कुमार की पार्टी जमीनी स्तर से टूट–फूट जायेगी, जिसका सीधा फायदा भाजपा को होगा। विधानसभा के सीटों का अंक गणित देखे तो तेजस्वी यादव को मुख्य मंत्री बनने के लिए मात्र 4 विधायकों की जरूरत होगी, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल भी चाहेगा कि रेलवे के कई घोटालों में सी.बी. आई. द्वारा नीतिश कुमार पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाय। हाल के ही दिनों में नीतिश कुमार से अलग हुए उनके हर–दिल

मिथलेश कुमार सिंह

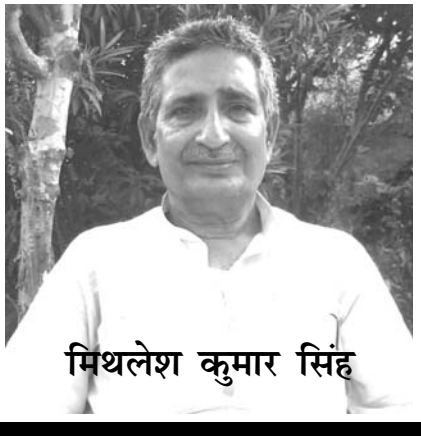

अजीज उनके प्रिय साथी पूर्व मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिन्हा भी इसी मौके के ताक में हैं और सी.बी.आई. को दस्तावेज उपलब्ध करवा रहे हैं। पूर्व प्रधान मंत्री स्व० अटल बिहारी वाजपई को भी इस मामले की पूरी जानकारी थी, लेकिन तब के राजनीतिक परिस्थिति के कारण वे भी किंकर्त्तव्यमूढ़ हो गये। जर्मन कम्पनियों एम.एफ.डी. और लुकास से जैक खरीदने का विरोध पूर्व प्रधान मंत्री चंद्रशेखर ने नीतिश कुमार को पत्र लिख कर किया था, लेकिन नीतिश कुमार ने किसी की नहीं सुनी।

भारतीय रेलवे को जैक (हाइड्रोलिक

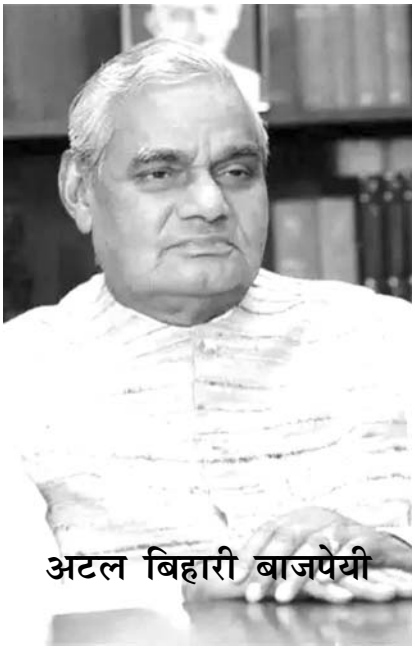
अटल बिहारी बाजपेयी

नीतीश कुमार, तत्कालिन रेल मंत्री

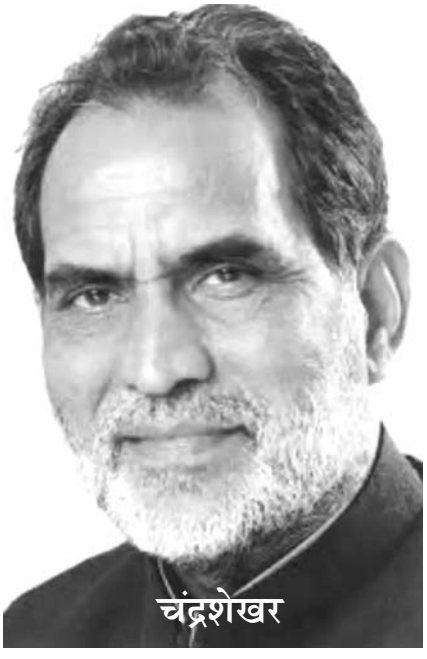
चंद्रशेखर

रोलिंग उपकरण) की खरीद करनी थी । यह उपकरण भारतीय कंपनी बेल्को द्वारा भी बनाया जाता था, जिसने भारतीय रेलवे को इन उपकरणों की आपूर्ति के लिए आवेदन किया था। लेकिन भारतीय रेलवे के अधिकारियों ने इस बोली में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली, बल्कि वे जर्मन कंपनियों एमएफडी और लुकास से इसे खरीदने की कोशिश कर रहे थे। भले ही बेल्को परीक्षण का खर्च उठाने के लिए तैयार था। हैरानी की बात यह है कि भारतीय रेल पूर्व प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद ही बेल्को के उपकरणों के परीक्षण के लिए तैयार हुई। जिसके बाद उपकरणों का दो बार परीक्षण किया गया और सभी आवश्यक तकनीकी मानकों पर उपयोग के लिए उपयुक्त पाया गया। रेलवे ने 49 करोड़ रुपये की लागत से ''फतुहा से इस्लामपुर तक खंडित लाइन की बहाली'' की एक परियोजना को मंजूरी दी, जिस पर अंततः 108 करोड़ रुपये खर्च हुए। उस समय स्थापित मानदंडों के अनुसार 50 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली किसी भी परियोजना को योजना आयोग से मंजूरी की आवश्यकता होती थी। ऐसा लगता है कि योजना आयोग की मंजूरी से बचने के लिए परियोजना की स्वीकृत लागत 50 करोड़ रुपये से कम थी, जो स्थापित मानदंडों और प्रक्रिया का खुला उल्लंघन था । आश्चर्यजनक रूप से एक नई परियोजना अर्थात बिहार शरीफ से बरबीघा तक नई लाइन का निर्माण भी सामग्री संशोधन के तहत उपरोक्त परियोजना में जोड़ा गया था । बिहार शरीफ से बरबीघा के बीच नई लाइन के निर्माण की परियोजना को हेड कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू लाइन के तहत स्वीकृत किया जाना चाहिए था ।

ऐसा लगता है कि यह योजना आयोग या किसी अन्य वैधानिक निकाय से नई मंजूरी प्राप्त करने से बचने के लिए किया गया था, जो अतिआवश्यक था। चूंकि बिहार शरीफ और बरबीघा के बीच नई लाइन के निर्माण की परियोजना को फतुहा–इस्लामपुर लाइन की बहाली की परियोजना के भौतिक संशोधन के तहत स्वीकृत किया गया था। इस इच्छित परियोजना के लिए कोई नया बजट स्वीकृत नहीं किया गया था और उपरोक्त नई लाइन के निर्माण पर किए गए सभी व्यय कोई बजटीय

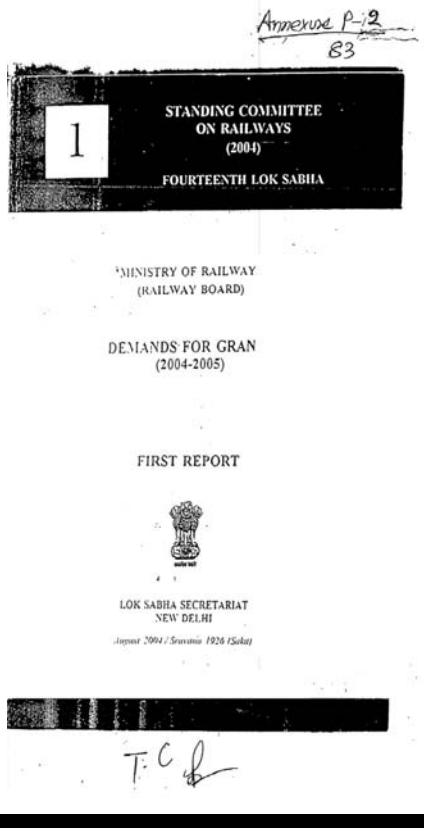
Annexure P-12
83

1

STANDING COMMITTEE ON RAILWAYS (2004)

FOURTEENTH LOK SABHA

MINISTRY OF RAILWAY (RAILWAY BOARD)

DEMANDS FOR GRAN (2004-2005)

FIRST REPORT

LOK SABHA SECRETARIAT NEW DELHI

August 2004 / Sravana 1926 (Saka)

T. C

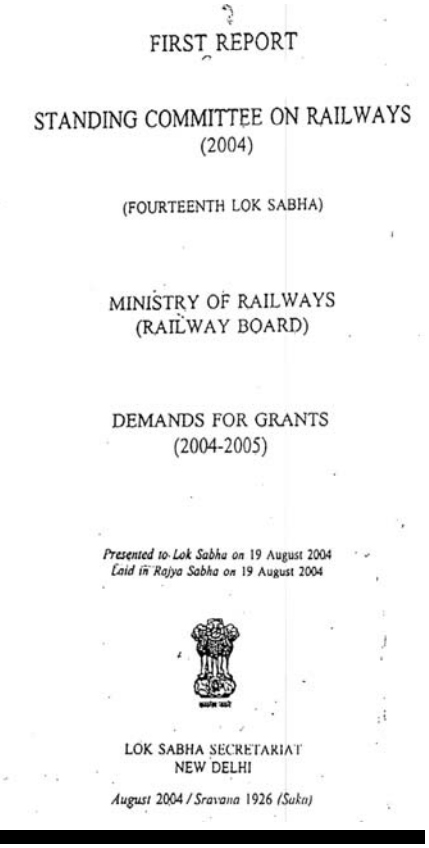
FIRST REPORT

STANDING COMMITTEE ON RAILWAYS (2004)

(FOURTEENTH LOK SABHA)

MINISTRY OF RAILWAYS (RAILWAY BOARD)

DEMANDS FOR GRANTS (2004-2005)

Presented to Lok Sabha on 19 August 2004
Laid in Rajya Sabha on 19 August 2004

LOK SABHA SECRETARIAT NEW DELHI

August 2004 / Sravana 1926 (Saka)

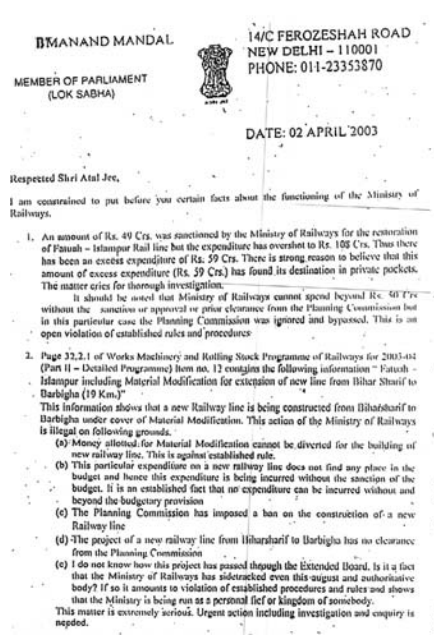

BMANAND MANDAL
MEMBER OF PARLIAMENT
(LOK SABHA)

14/C FEROZESHAH ROAD
NEW DELHI – 110001
PHONE: 011-23353870

DATE: 02 APRIL 2003

Respected Shri Atal Jee,

I am constrained to put before you certain facts about the functioning of the Ministry of Railways.

1. An amount of Rs. 49 Crs. was sanctioned by the Ministry of Railways for the restoration of Fatuah – Islampur Rail line but the expenditure has overshot to Rs. 108 Crs. Thus there has been an excess expenditure of Rs. 59 Crs. There is strong reason to believe that this amount of excess expenditure (Rs. 59 Crs.) has found its destination in private pockets. The matter cries for thorough investigation.
   It should be noted that Ministry of Railways cannot spend beyond Rs. 40 Crs without the sanction or approval or prior clearance from the Planning Commission but in this particular case the Planning Commission was ignored and bypassed. This is an open violation of established rules and procedures
2. Page 32.2.1 of Works Machinery and Rolling Stock Programme of Railways for 2003-04 (Part II – Detailed Programme) item no. 12 contains the following information " Fatuah – Islampur including Material Modification for execution of new line from Bihar Sharif to Barbigha (19 Km.)"
   This information shows that a new Railway line is being constructed from Biharsharif to Barbigha under cover of Material Modification. This action of the Ministry of Railways is illegal on following grounds.
   (a) Money allotted for Material Modification cannot be diverted for the building of new railway line. This is against established rule.
   (b) This particular expenditure on a new railway line does not find any place in the budget and hence this expenditure is being incurred without the sanction of the budget. It is an established fact that no expenditure can be incurred without and beyond the budgetary provision
   (c) The Planning Commission has imposed a ban on the construction of a new Railway line
   (d) The project of a new railway line from Biharsharif to Barbigha has no clearance from the Planning Commission
   (e) I do not know how this project has passed though the Extended Board. Is it a fact that the Ministry of Railways has sidetracked even this august and authoritative body? If so it amounts to violation of established procedures and rules and shows that the Ministry is being run as a personal fief or kingdom of somebody.

This matter is extremely serious. Urgent action including investigation and enquiry is needed.

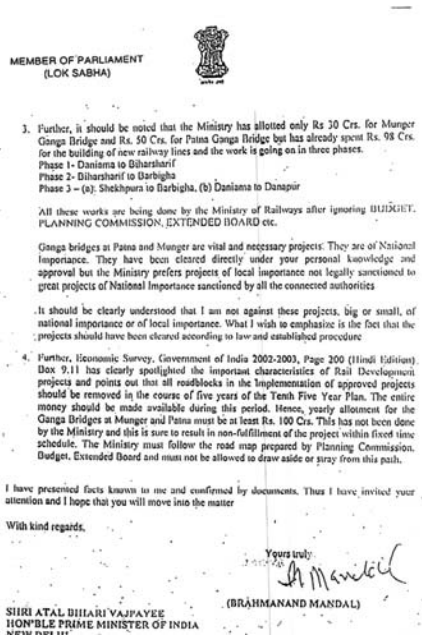

MEMBER OF PARLIAMENT
(LOK SABHA)

3. Further, it should be noted that the Ministry has allotted only Rs 30 Crs. for Munger Ganga Bridge and Rs. 50 Crs. for Patna Ganga Bridge but has already spent Rs. 98 Crs. for the building of new railway lines and the work is going on in three phases.
   Phase 1- Daniama to Biharsharif
   Phase 2- Biharsharif to Barbigha
   Phase 3 – (a). Shekhpura to Barbigha, (b) Daniama to Danapur

   All these works are being done by the Ministry of Railways after ignoring BUDGET, PLANNING COMMISSION, EXTENDED BOARD etc.

   Ganga bridges at Patna and Munger are vital and necessary projects. They are of National importance. They have been cleared directly under your personal knowledge and approval but the Ministry prefers projects of local importance not legally sanctioned to great projects of National Importance sanctioned by all the connected authorities

   It should be clearly understood that I am not against these projects, big or small, of national importance or of local importance. What I wish to emphasize is the fact that the projects should have been cleared according to law and established procedure

4. Further, Economic Survey, Government of India 2002-2003, Page 200 (Hindi Edition) Box 9.11 has clearly spotlighted the important characteristics of Rail Development projects and points out that all roadblocks in the implementation of approved projects should be removed in the course of five years of the Tenth Five Year Plan. The entire money should be made available during this period. Hence, yearly allotment for the Ganga Bridges at Munger and Patna must be at least Rs. 100 Crs. This has not been done by the Ministry and this is sure to result in non-fulfillment of the project within fixed time schedule. The Ministry must follow the road map prepared by Planning Commission, Budget, Extended Board and must not be allowed to draw aside or stray from this path.

I have presented facts known to me and confirmed by documents. Thus I have invited your attention and I hope that you will move into the matter

With kind regards,

Yours truly,

(BRAHMANAND MANDAL)

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE
HON'BLE PRIME MINISTER OF INDIA

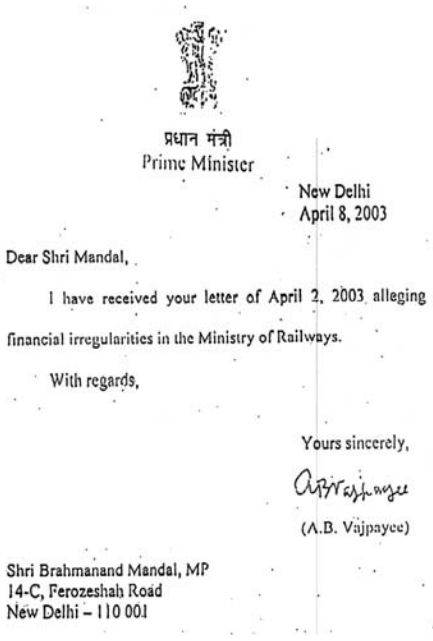

प्रधान मंत्री
Prime Minister

New Delhi
April 8, 2003

Dear Shri Mandal,

I have received your letter of April 2, 2003 alleging financial irregularities in the Ministry of Railways.

With regards,

Yours sincerely,

(A.B. Vajpayee)

Shri Brahmanand Mandal, MP
14-C, Ferozeshah Road
New Delhi – 110 001

प्रावधान के बिना थे । चूंकि नई लाइन का निर्माण योजना आयोग की मंजूरी के बिना शुरू किया गया था, जिसके बदले में बिहार शरीफ और बरबीघा के बीच नई लाइन के निर्माण पर रोक लगा दी थी ।

उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि उस समय रेल मंत्रालय को निजी संपत्ति के रूप में माना जाता था और स्थापित नियमों और प्रावध ानों का पालन किए बिना कुछ भी किया जा सकता था। 14वीं लोकसभा की स्थायी समिति ने भी कंक्रीट स्लीपरों की इन खरीद में गंभीर अनियमितताएं पाई थीं, उनके द्वारा यह भी आरोप लगाया था कि (पहली रिपोर्ट 17–08–2004 का पैरा 146) समिति ने नोट किया कि कंक्रीट स्लीपरों की खरीद एक बहुत ही संवेदनशील मामला बन गया है क्योंकि बहुत से बेईमान मौजूदा निर्माताओं ने अनुचित तरीकों से या प्रक्रिया के साथ छेड़छाड़ करके और साथ ही साथ नए प्रतियोगी को दौड़ से बाहर रखने के लिए एक कार्टेल लॉबी का गठन किया गया था। यहाँ एक बात उल्लेखनीय है कि समिति द्वारा कार्टेल शब्द का प्रयोग किया गया है।

भारतीय रेलवे को बड़ी संख्या में कंक्रीट स्लीपरों की खरीद करनी पड़ी थी। तदनुसार, भारतीय रेलवे द्वारा क्रमशः 160 लाख स्लीपरों और 90 लाख स्लीपरों की आपूर्ति के लिए निविदा संख्या सीएस 145/2000 और सीएस 152/2022 द्वारा दो निविदाएं जारी की गई।

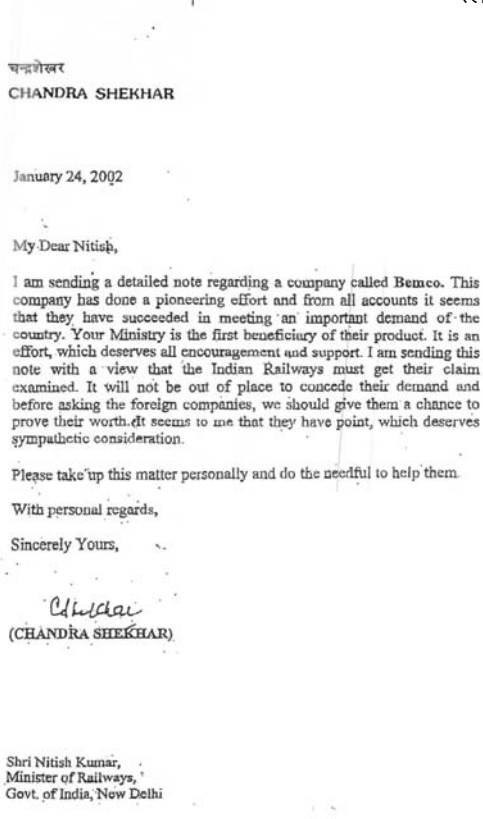

चन्द्रशेखर
CHANDRA SHEKHAR

January 24, 2002

My Dear Nitish,

I am sending a detailed note regarding a company called Bemco. This company has done a pioneering effort and from all accounts it seems that they have succeeded in meeting an important demand of the country. Your Ministry is the first beneficiary of their product. It is an effort, which deserves all encouragement and support. I am sending this note with a view that the Indian Railways must get their claim examined. It will not be out of place to concede their demand and before asking the foreign companies, we should give them a chance to prove their worth. It seems to me that they have point, which deserves sympathetic consideration.

Please take up this matter personally and do the needful to help them.

With personal regards,

Sincerely Yours,

(CHANDRA SHEKHAR)

Shri Nitish Kumar,
Minister of Railways,
Govt. of India, New Delhi

3, साउथ एवेन्यू लेन, नई दिल्ली-110 011 टेलीफोन 301-2587, 301-2163
3, South Avenue Lane, New Delhi - 110 011. Tele : 301-2587, 301-2163

निविदा संख्या सीएस 145/2000 :– भारतीय रेलवे ने खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से 160 लाख खरीद की आपूर्ति के लिए निविदा दी । टेंडर को 715 रुपये प्रति स्लीपर की दर से स्वीकार किया गया था, हालांकि सबसे कम बोली 591 रुपये प्रति स्लीपर की थी, जिसके परिणामस्वरूप 190 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

निविदा क्रमांक सीएस 152/2002 :– इसी प्रकार भारतीय रेलवे ने खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से 90 लाख स्लीपरों की आपूर्ति के लिए निविदा दी। 429 रुपये प्रति स्लीपर की न्यूनतम बोली के मुकाबले 565 रुपये प्रति स्लीपर की दर से निविदा स्वीकार की गई, जिसके परिणामस्वरूप 122–40 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

2004 से 2009 भारत के रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव थे। रेल मंत्री लालू प्रसाद ने सीबीआई से 200 करोड़ रुपये के स्लीपर खरीद घोटाले की जांच ''पूरी रफ्तार और ईमानदारी'' से करने को कहा ताकि दोषियों को बिना देर किए न्याय मिल सके। रेलवे में स्थायी समिति की रिपोर्ट के बाद घोटाले का पता चला है और सीबीआई के पास पहले से ही महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। ''उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी को जांच की गति तेज करनी चाहिए और दोषियों को जल्द से जल्द बुक करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि नीतीश जी या कोई हो (चाहे वह नीतीश जी हों या किसी अन्य व्यक्ति के साथ)

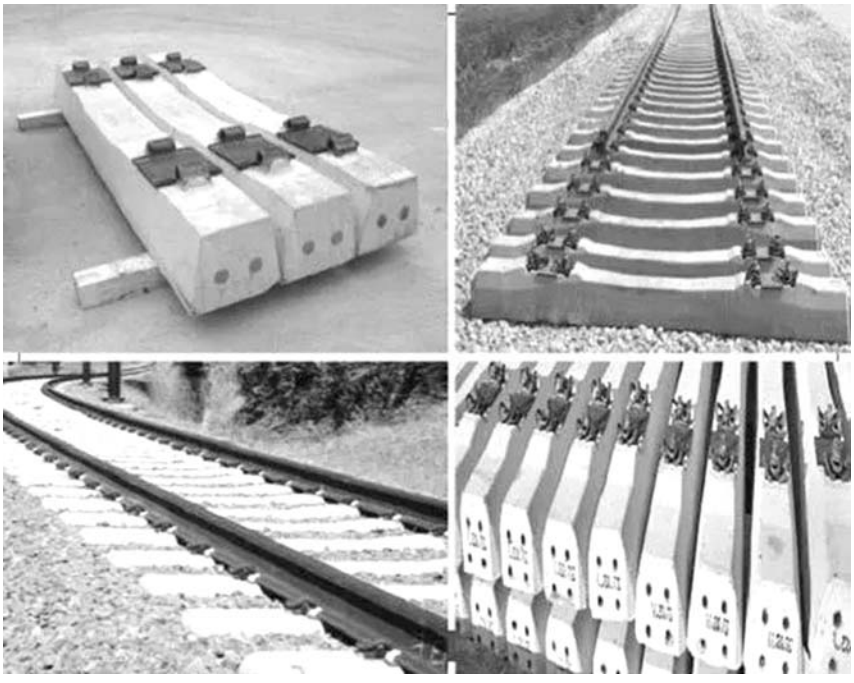

सीबीआई को किसी भी मामले में पूछताछ करनी चाहिए।'' लालू ने कहा था कि भारत के महालेखा परीक्षक ने भी अपनी रिपोर्ट में स्लीपरों की खरीद में अनियमितताओं को उजागर किया है । रेल मंत्री ने कहा कि केंद्र में एनडीए सरकार के दौरान जनता के पैसे की हेराफेरी से मामला है। ''केंद्रीय प्रमुख जांच एजेंसी होने के नाते सीबीआई ने स्लीपरों की खरीद में की गई अनियमितताओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों को जब्त कर लिया है। लालू ने कहा, मुझे विश्वास है कि सीबीआई सच्चाई को सामने लाने में सक्षम होगी और इसमें शामिल सभी लोगों को दंडित करने में न्यायपालिका की मदद करेगी।'' लालू ने खरीद में अनियमितताओं के संबंध में कुछ बड़े लोगों और ठगों के बीच साजिश की संभावना जताई थी।

करोड़ों रुपये के "स्लीपर घोटाले" पर केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मामले की जांच की या नहीं, इस पर सीबीआई, लोकसभा सचिवालय और रेल मंत्रालय की तीन अलग–अलग प्रतिक्रियाओं ने मामला गड़बड़ कर दिया है। एक याचिकाकर्ता ने मामले को ''फिर से खोलने'' के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया था। कथित घोटाला, जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय में 320 करोड़ रुपये की एक याचिका में रखा गया था, तब हुआ जब नीतीश कुमार मार्च 2001 और मई 2004 के बीच रेल मंत्री थे । याचिका मिथिलेश सिंह द्वारा अक्टूबर 2013 में दायर की गई थी और जुलाई 2014 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। जनवरी–फरवरी 2016 में एक अन्य कार्यकर्ता, गोपाल प्रसाद द्वारा एक आरटीआई प्रश्न का उत्तर देते हुए, लोकसभा सचिवालय ने सीबीआई के हवाले से कहा कि एजेंसी ने मामले की जांच नहीं की। हालांकि, इसी सवाल का जवाब देते हुए रेल मंत्रालय ने कहा कि सीबीआई ने जांच की लेकिन कोई आपराधिक मामला सामने नहीं आया। लोकसभा सचिवालय ने लिखा, ''सीबीआई ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि उन्होंने इस मामले में कोई खुली जांच नहीं की है। उपरोक्त सीबीआई सत्यापन नोट के संबंध में पहली जानकारी रेल मंत्रालय के पास है। सीबीआई, सचिवालय और रेलवे की इन तीन अलग–अलग प्रतिक्रियाओं ने दो याचिकाकर्ताओं को भ्रमित कर दिया है । दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी याचिका में मिथिलेश सिंह ने दावा किया था कि सीबीआई ने 2006 में रेलवे बोर्ड से कहा था कि वह मामले से जुड़ी किसी भी जानकारी का खुलासा नहीं करेगी क्योंकि इससे सूचना देने वालों की जान को खतरा होगा । यह मामला रेलवे पटरियों के बीच इस्तेमाल होने वाले कंक्रीट स्लीपरों की खरीद में कथित अनियमितताओं से संबंधित है । आरोपों के अनुसार, नीतिश कुमार ने रेल मंत्री के रूप में, स्वर्गीय दयानंद सहाय और धीरेंद्र अग्रवाल के मेसर्स दया इंजीनियरिंग वर्क्स, गया को 160 लाख कंक्रीट स्लीपर बनाने का ठेका दिया, जिसमें गाड़ी की लागत भी जोड़ी गई । इससे रेलवे को अतिरिक्त 1,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। ''कैरिज कॉस्ट'' स्लीपरों को उनके निर्माण के स्थान से उन साइटों तक ले जाने की लागत है जहां उनका उपयोग किया जाना है। याचिकाकर्ताओं को जो दिलचस्प लगा वह रेल मंत्रालय की प्रतिक्रिया है, जिसने कहा है कि मामले की जांच की गई थी, लेकिन ''अपराध'' स्थापित नहीं किया जा सका। गोपाल प्रसाद को मंत्रालय के जवाब में कहा गया था, यह सूचित किया जाता है कि वर्ष 2002 में कंक्रीट स्लीपरों की खरीद के लिए निविदाओं में कथित अनियमितताओं के संबंध में शिकायत की सीबीआई द्वारा जांच की गई है, जिसमें कोई ''आपराधिक अपराध'' स्थापित नहीं हुआ है। ''इन नवीनतम घटनाक्रमों के बाद कई सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्त्ता विभिन्न विभागों से आने वाले विरोधाभासी बयानों पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर करने के लिए तैयार हैं। पूर्व मंत्री ने कहा है कि विभिन्न विभागो मंत्रालयों से आ रहे बयान भ्रामक ह ै । उन्हो ने यह भी पूछा है कि क्या सीबीआई को मामले की जांच करने के लिए कहने के बाद सीबीआई को पीई (प्रारंभिक जांच) या आरसी (पंजीकृत मामला) दर्ज करना चाहिए। इस मामले की शुरुआत

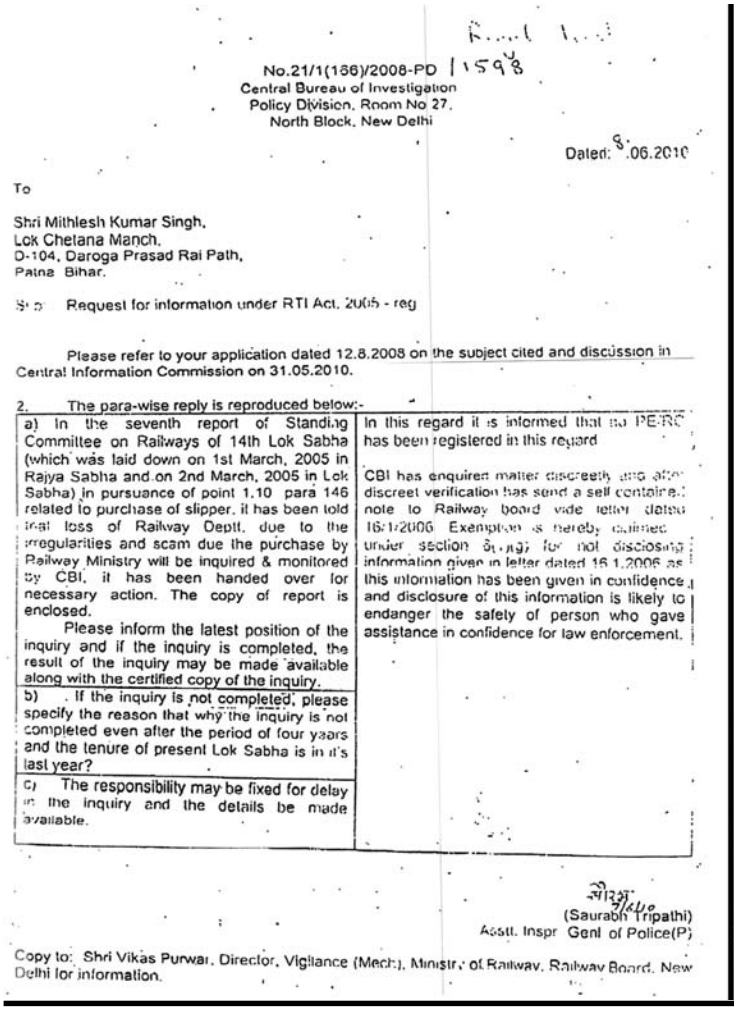

No.21/1(166)/2008-PD /1598
Central Bureau of Investigation
Policy Division, Room No 27,
North Block, New Delhi

Dated: 8.06.2010

To

Shri Mithlesh Kumar Singh,
Lok Chetana Manch,
D-104, Daroga Prasad Rai Path,
Patna Bihar.

Sub: Request for information under RTI Act, 2005 - reg

Please refer to your application dated 12.8.2008 on the subject cited and discussion in Central Information Commission on 31.05.2010.

2. The para-wise reply is reproduced below:-

a) In the seventh report of Standing Committee on Railways of 14th Lok Sabha (which was laid down on 1st March, 2005 in Rajya Sabha and on 2nd March, 2005 in Lok Sabha) in pursuance of point 1.10 para 146 related to purchase of slipper, it has been told that loss of Railway Deptt. due to the irregularities and scam due the purchase by Railway Ministry will be inquired & monitored by CBI, it has been handed over for necessary action. The copy of report is enclosed. Please inform the latest position of the inquiry and if the inquiry is completed, the result of the inquiry may be made available along with the certified copy of the inquiry.	In this regard it is informed that no PE/RC has been registered in this regard CBI has enquired matter discreetly and after discreet verification has send a self contained note to Railway board vide letter dated 16/12/2006 Exemption is hereby claimed under section 8(1)(g) for not disclosing information given in letter dated 16.1.2006 as this information has been given in confidence and disclosure of this information is likely to endanger the safety of person who gave assistance in confidence for law enforcement.
b) If the inquiry is not completed, please specify the reason that why the inquiry is not completed even after the period of four years and the tenure of present Lok Sabha is in it's last year?	
c) The responsibility may be fixed for delay in the inquiry and the details be made available.	

(Saurabh Tripathi)
Asstt. Inspr Genl of Police(P)

Copy to: Shri Vikas Purwar, Director, Vigilance (Mech.), Ministry of Railway, Railway Board, New Delhi for information.

NO. 21/1/(166)/2008-PD

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

POLICY DIVISION ROOM NO. 27 NORTH BLOCK, NEW DELHI-110011

Date 8.6.2010

To

SHRI MITHILESH KUMAR SINGH,
LOK CHETANA MANCH,
D-104, DAROGA PRASAD RAI,
PATH, PATNA, BIHAR

Sub: REQUEST FOR INFORMATION UNDER RTI ACT, 2005 REG.

Please refer to your application dated 12.8.2008 on the subject cited and discussion in Central Information Commission on 31.5.2010.

2. The para wise reply is reproduced below;

a. Seventh report of Railway's standing committee of 14th Lok Sabha (which was presented before Rajya Sabha on 1st march 2005 and before lok Sabha on 2nd March 2005)	In this regard, it is informed that no PE/RC has been registered in this regard. CBI has enquired matter discreetly and after discreet verification as send a

2004 में हुई थी, जब रेलवे की 14वीं संसदीय स्थायी समिति के तत्कालीन सांसदों जैसे बी. एन. मंडल और रघुनाथ झा सहित अन्य स्थायी समिति ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि इस कारण हुए नुकसान की जांच एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा की जानी चाहिए। इसके बाद, यूपीए सरकार ने मई 2005 में एक एक्शन टेकन रिपोर्ट संसद को सौंपी, जिसमें कहा गया था: ''... मामले को सीबीआई ने जांच के लिए उठाया है। स्थायी समिति की टिप्पणियों को देखने के अनुरोध के साथ स्थायी समिति के विचारों को संप्रेषित किया गया है।'' जब मिथिलेश सिंह मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय में ले गए थे, तो अदालत ने 2014 में कहा था कि सीबीआई ने ''वास्तव में'' जांच की थी और अदालत को ''रिकॉर्ड ... विश्वास में'' दिखाया था । इसमें कहा गया था कि सीबीआई की रिपोर्ट रेलवे पर संसदीय स्थायी समिति के समक्ष रखी गई थी । अदालत ने कहा था, ''प्रतिवादी रेलवे के वकील ने हमें विश्वास के साथ फिर से रिकॉर्ड दिखाया है और यह खुलासा करता है कि वास्तव में सीबीआई जांच की गई थी और सीबीआई की रिपोर्ट रेलवे की स्थायी समिति के समक्ष रखी गई थी।'' इस मुद्दे पर नीतीश कुमार का पक्ष लेने की बार–बार कोशिशें नाकाम साबित हुईं । मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) में उन्हें और उनके सचिवों को भेजे गए एक ईमेल का कोई जवाब नहीं मिला । सीबीआई ने भी भेजे गए सवाल का जवाब नहीं दिया ।

दिल्ली उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधी'ा न्यायामूर्ति राजीव सहाय एंड लॉ के कोर्ट में मिथलेश कुमार सिंह बनाम भारत सरकार ,वं अन्य के याचिका संख्या डब्ल्यू.पी.(सी) 1618/2014 निर्णय की तिथिः 7 जुलाई 2014, माननीय मुख्य न्यायाधीश माननीय श्रीमान जस्टिस राजीव सहाय एंड लॉ ने जनहित याचिका (पीआईएल) के माध्यम से दायर याचिका रेल मंत्रालय(रेलवे बोर्ड(प्रधान मंत्री कार्यालय(लोकसभा सचिवालय(निदेशक, सीबीआई और भारत के योजना आयोग को निर्देश देने की मांग करती है । श्री नीतीश कुमार के कार्यकाल के दौरान जैक की खरीद, रेलवे भर्ती बोर्ड, पटना में उम्मीदवारों की नियुक्ति, रेलवे लाइन के विस्तार में वित्तीय अनियमितता और रेलवे में कंक्रीट स्लीपरों की खरीद में घोटाले से संबंधित दस्तावेजों का विवरण प्रदान करें। केंद्रीय रेल मंत्री के रूप में और प्रतिवादी संख्या 6 निदेशक, सीबीआई को प्रतिवादी संख्या 7 और उसके अन्य सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश। याचिकाकर्ता ने पहले भी इन्हीं तथ्यों पर डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 8919/2011 दायर किया था और जिसे 21 दिसंबर 2011 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। यह स्वीकार करते हुए कि मामला सीबीआई को भेजा गया था। जांच की गई और सीबीआई को इस मामले में कोई सार नहीं मिला और उसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कि मामले में कोई कार्रवाई जरूरी नहीं थी और कौन सी रिपोर्ट अंततः स्वीकार कर ली गई थी ? इसके बाद याचिकाकर्ता ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (आरटीआई अधिनियम) के तहत सूचना मांगी और फिर इस आधार पर

नीतीश की पीएम मोदी से क्या तुलना करना, अब तो मंडल और कमंडल दोनों बीजेपी के साथ है। मेरे पास स्लीपर घोटाले से संबंधित कोई जानकारी नहीं है।

सुशील कुमार मोदी
राज्यसभा सांसद

नीतीश को बीजेपी ने बड़ा नेता बनाया है, लेकिन अब एक बार फिर वह भ्रष्टाचार के गोद में चले गए हैं।

रविशंकर प्रसाद
सांसद
सह पूर्व कानून मंत्री

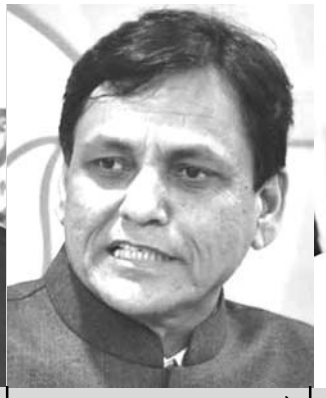

'गुंडाराज' आ गया है। जगह-जगह से दुष्कर्म, लूट, अपराध की खबरें आने लगी हैं।

नित्यानंद राय
गृह राज्य मंत्री,
भारत सरकार

नीतीश कुमार ने नीति, नीयत और नैतिकता को फ्रिज में रख दिया है।

गिरिराज सिंह
केन्द्रीय मंत्री,
भारत सरकार

पिछली रिट याचिका को खारिज करने के आदेश की समीक्षा की मांग की कि इस अदालत के समक्ष रिट याचिका को गलत तरीके से पेश किया गया था कि मामला सीबीआई को भेजा गया था। सीबीआई को उसमें कोई सार नहीं मिला था और किस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया था ? उक्त समीक्षा याचिका इस न्यायालय के समक्ष 7 दिसम्बर 2012 को आई जब प्रतिवादी रेलवे के वकील ने न्यायालय में लाए गए अभिलेखों को विश्वास के साथ पीठ को दिखाया और फिर मामले की सुनवाई की और उसके अवलोकन पर इस न्यायालय ने दर्ज किया कि उसी ने खुलासा किया कि वास्तव में सीबीआई जांच की गई और सीबीआई की रिपोर्ट रेलवे की स्थायी समिति के समक्ष रखी गई। इसके मद्देनजर उक्त समीक्षा याचिका को 7 दिसंबर 2012 को पूर्वोक्तर रूप में खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने फिर से आरटीआई अधिनियम के तहत अपने सूचना का पीछा किया और उसके आधार पर दावा किया कि मामले को रेलवे बोर्ड के समक्ष रखा गया है या सीबीआई द्वारा जांच की गई है इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। यह निवेदन करते हुए यह रिट याचिका दायर की गई है। इस न्यायालय ने (पूर्वोक्तर समीक्षा याचिका को खारिज करने के आदेश दिनांक 7 दिसंबर 2012 के आदेश में) यह देखते हुए कि उसे दिखाए गए रिकॉर्ड से पता चलता है कि वास्तव में सीबीआई जांच की गई थी और सीबीआई की रिपोर्ट को स्थायी समिति के समक्ष रखा गया था। रेलवे की आज की सीबीआई जांच नहीं होने और उसकी रिपोर्ट को रेलवे की स्थायी समिति के समक्ष नहीं रखे जाने के तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार याचिकाकर्ता उसी पहलू पर दूसरे या तीसरे दौर की मुकदमेबाजी का हकदार नहीं है, जैसा करने की मांग की जा रही है। हमने अन्य सभी याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील से पूछताछ की है कि याचिकाकर्ता एक के बाद एक कार्यवाही दर्ज करके पिछले लगभग तीन वर्षों से प्रतिवादी संख्या 7 को क्यों निशाना बना रहा है और याचिकाकर्ता के ज्ञान और जानकारी का स्रोत क्या है? उन मामलों से संबंधित जो अपराधों के कमीशन का आरोप लगाया गया है। कोई प्रशंसनीय उत्तर सामने नहीं आया है। हमें संदेह है कि याचिका प्रेरित है और जनहित में नहीं है और इस आधार पर भी इस पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट के इस निर्णय से कुछ भी स्पष्ट नहीं हो सका है और अनिर्णय की स्थिति बनी रह गई। इस मामले में याचिकाकर्त्ता द्वारा उच्चतम न्यायालय में एस. एल.पी. दायर करना था, जो अज्ञात कारणवश नहीं किया जा सका और पिछले कोरोना काल में याचिकाकर्त्ता मिथलेश कुमार सिंह की मृत्यु भी हो गई। मिथलेश कुमार सिंह के मोबाईल पर सम्पर्क करने पर उनके परिवार के सदस्य द्वारा बताया गया कि उनकी मृत्यु लगभग डेढ़ साल पहले हो चुकी है। दिल्ली हाई कोर्ट के उक्त आदेश में कई प्रकार की प्रश्नवाचक वाक्य हैं, जिसका निपटारा उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा होना आवश्यक है। नये राजनीतिक परिवेश में कई राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्त्ता इस मामले को उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। हजारों करोड़ :रूपये के इस घोटाले में राजकीय राजकोष की लूट हुई है। साथ ही बड़ी वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है, लेकिन राजनीतिक पार्टी अपने निजि स्वार्थवश इस मामले को 18 सालों से दबाये हुए हैं। महालेखाकार की रिपोर्ट, रेलवे के लोकसभा की स्थाई समिति की रिपोर्ट और सीबीआई की रिपोर्ट आने के बावजूद भारत के गरीब जनता की पैसों की वसूली न होना भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के न खाउँगा न खाने दूँगा के सिद्धांत को झुठला रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नैशनल हेराल्ड केस में सोनिया गाँधी और राहूल गाँधी को जेल भेजने को तैयार है, वहीं दूसरी तरफ ,एनडीए शासन काल में हुए, घोटाले पर चुपी साधे हुए हैं। भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कहते हैं कि भ्रष्टाचार करने वाले किसी को नहीं छोड़ा जायेगा, तो फिर नीतश कुमार के मामले में यह नारा क्यों कमजोर पड़ जाता है? केवल सच इस मामले में अगले अंक में विस्तारपूर्वक परत–दर–परत इसकी जानकारी देगा। जरूःरत पड़ने पर न्याय के लिए केवल सच अपने सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटायेगा। ●

शिक्षा के क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ रहा है जहानाबाद

10वीं बोर्ड से लेकर यूपीएससी तक जिले के छात्र फहरा रहे झंडे

● नवीन कुमार रौशन

कभी पूरे देश में नक्सली गतिविधियों के लिए चर्चित बिहार का जहानाबाद जिला अब पूर्णत: बदल चुका है। कभी समय था कि यहाँ के युवा नक्सली गतिविधियों के लिए बदनाम थे।उस बदनामी की दाग को जिले के छात्रों ने अपनी कड़ी मेहनत और कठोर परिश्रम से धो डाला है। जहानाबाद को इसके भूत से निकालने में यहाँ के शिक्षाविदों ने भी अहम भूमिका निभाई है। डीएवी के पूर्व प्राचार्य डॉ वीएस ओझा, बाल विद्या निकेतन सह पटेल ग्रुप ऑफ कॉलेजेज के निदेशक डॉ अनिल कुमार,मानस विद्यालय के नवल किशोर शर्मा, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल के डॉ निर्मला शर्मा,प्रतिभा प्लवन मेमोरियल शैक्षणिक ग्रुप के डॉ एसके सुनील व राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित डॉ इंदु कश्यप,मानस इंटरनेशनल शैक्षणिक ग्रुप के प्रो अरुण कुमार,रामकृष्ण परमहंस विद्यालय के प्रो चन्द्रभूषण शर्मा उर्फ भोला बाबू, प्रतिभा प्लवन शैक्षणिक ग्रुप के अभिराम शर्मा,एमपीसी स्कूल के प्रमोद कुमार,बाल विद्या निकेतन के अक्षय कुमार, सन्त कोलम्बस पब्लिक स्कूल के राकेश कुमार जैसे लोगों ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से पूरे जिलों को शैक्षणिक हब के रूप में विकसित कर डाला। जहानाबाद जैसे छोटे से जिले का,यह बदलाव का ही प्रमाण है कि ऐसे तो यहाँ सैकड़ो विद्यालय स्थापित है जो जिले में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अलख जगा रहें है,लेकिन यहाँ के एक दर्जन से भी अधिक स्थापित सीबीएसई विद्यालयों से प्रत्येक वर्ष निकलने वाले बच्चे पूरे राज्य ही नही देश मे अपने प्रतिभा का लोहा मनवा रहें है। हाल हीं में ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल से पढ़ने वाली दिव्या शर्मा ने बीपीएससी की परीक्षा में जहानाबाद का झंडा गाड़ा है, वहीं बाल विद्या निकेतन से पढ़ने वाले राजेश रंजन ने तो इस जिले का परचम पिछले वर्ष यूपीएससी की परीक्षाओं में लहराया है। यही नही मानस विद्यालय से पढ़ने वाले किसान पुत्र सनोज राज ने तो एसएसबी के साथ साथ सोनी टीवी द्वारा प्रायोजित तथा मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन द्वारा संचालित कौन बनेगा करोड़पति के 11 वीं सीजन में 25 करोड़ की राशि जीत कर जिले की प्रतिभा का लोहा मनवाया तथा इस सीजन के पहले विजेता होने का गौरव प्राप्त किया है। उपलब्धियों की श्रृंखला में ऐसे कई नाम है जिसने जहानाबाद की छवि राज्य में हीं नही देश मे बदला है।

प्रतिभाओं की ऐसी सृंखला का निर्माण यहाँ के विद्यालयों में आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण हीं सम्भव हो सका है। हमेशा अपने को सबसे बेहतर साबित करने और एक दूसरे को पीछे छोड़ने में लगे यहाँ के शिक्षाविदों ने हमेशा अपने संस्थानों में कड़ी अनुशासन और बेहतर शैक्षणिक महौल स्थापित किया है। तभी तो किसी के बच्चे एकेडमिक परीक्षा परिणामों में बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर अपने संस्थान को उत्कृष्ट होने के गौरव से गौरान्वित करवाता है तो कभी यहाँ से निकले छात्र विभिन्न तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतरीन रिजल्ट देकर अपने विद्यालय को बेहतर होने का फक्र करवाता है। इस बार भी एकेडमिक परीक्षाओं के परिणामों में कुछ ऐसा हीं हुआ है। किसी विद्यालय के बच्चे सीबीएसई के 10 की परीक्षा परिणामों में सबसे अधिक 10 सीजीपी लाकर अपने विद्यालय का परचम लहराया है तो किसी विद्यालय के बच्चे सीबीएसई 12 वीं में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर अपने विद्यालय का परचम लहराया है। दूसरी तरफ जेईई मेन की प्रतियोगी परीक्षा में जिले के दर्जनों छात्रों ने अपने-अपने विद्यालय को गौरवान्वित किया है।

10 वी और 12 वी सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा परिणामों की बात करें तो इस वर्ष डीएवी के अंशुल प्रकाश ने 10 वी सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में 98.6 प्रतिशत अंक लाकर जिले में टॉप किया है। वही प्रतिभा पल्लवन की मोनी, डीएवी की ही अनिशा, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल की आशका तथा मानस इंटरनेशनल के हिमांशु जिले में सेकंड टॉपर होने का गौरव प्राप्त किया है। रामकृष्ण परमहंस विद्यालय के अमित राज 96 प्रतिशत अंक प्राप्त कर विद्यालय टॉपर बना वहीं आदित्य नारायण 94.8 प्रतिशत आदित्य कुमार 94 प्रतिशत, सुप्रिया प्रकाश 93 प्रतिशत,रानी कुमारी 92.2 प्रतिशत,गौरव कुमार 91.4 प्रतिशत, प्रकाश कुमार 91.6 प्रतिशत अंक प्राप्त कर अपने विद्यालय के शैक्षणिक गुणवत्ता का परिचय दिया है। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक प्रोफेसर चन्द्रभूषण शर्मा ने छात्रों को बधाई देते हुए उनके उज्वल भविष्य की कामना की है। साथ हीं कहा

जेईई मेन में भी जिले का लहरा रहा है परचम

जहानाबाद जिले के छात्रों ने एक बार फिर से राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली जेईई मेन की परीक्षा में आशातीत प्रदर्शन करते हुए जिले का परचम लहरा दिया है। अपनी कड़ी मेहनत और लगन के बदौलत अपने परिवार, समाज,जिला और विद्यालय की प्रतिष्ठा राज्य और देश मे स्थापित की है। विगत दिनों जेईई मेन की परीक्षा का परिणाम जारी किया है। जिसमे पी.पी.विद्यालय के 11 तथा मानस इटरनेशनल विद्यालय दक्षिणी के कुल दो छात्रों ने सफलता हासिल की है। मानस इंटरनेशनल दक्षिणी के आदित्य रंजन तथा कन्हैया कुमार के सफलता पर विद्यालय के निदेशक निशांत रंजन तथा चेयरमैन प्रो अरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि इस जिले की पृष्ठभूमि कृषि प्रधान है। जहाँ बच्चे अपने अभिभावकों को कठोर परिश्र्म करते देख कड़ी मेहनत व परिश्र्म करना सीखते है।

विद्यालय उन्हें अनुशासन मे रहना था विद्यालय के शिक्षक उनके परिश्र्म को सकारात्मक दिशा देने का काम करते है। प्रो सिन्हा ने विद्यालय के छात्रों के इस सफलता पर छात्रों व शिक्षकों को भी बधाई दी है। वहीं पी.पी.स्कूल के छात्रों के सफलता पर पी.पी. शैक्षणिक समूह के चेयरमैन डॉ. अभिराम सिंह ने कहा कि नि:संदेह इसमें छात्रों ने कठिन परिश्रम से यह सफलता हसिल की है। मेरी कामना है कि आप देश के अन्य प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल कर अपने माता-पिता का नाम रौशन करें। मौके पर पी.पी. पब्लिक स्कूल के एमडी अक्षय आनन्द ने कहा कि एक साथ इस विद्यालय के 11 छात्रों का जेईई मेन जैसे राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में सफलता हासिल करना वास्तव में विद्यालय और जिले के लिए भी गौरव की बात है। उन्होंने बताया कि साक्षी प्रकाश ने 98.10 का स्कोर प्राप्त किया। वहीं प्रिय रंजन कुमार ने 97 स्कोर, प्रभात कुमार ने 94, सोनु कुमार ने 93, शशांक राज ने 93, अभिषेक कुमार ने 93.72, सौरभ कुमार ने 92, ज्ञान रंजन ने 90.6, रवि कुमार 90.35, श्रेया राज 90 व दीपक कुमार ने 90 का स्कोर प्राप्त कर यह दिखा दिया है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। बस इन्हें उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता है। ये सभी बच्चे प्राथमिक वर्ग से लेकर 12वीं बोर्ड तक की शिक्षा इसी विद्यालय से प्राप्त की है। सभी बच्चों ने 12वीं में भी 90 फीसदी से अधिक अंक प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था। श्री आनन्द ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

कि इस विद्यालय के बच्चे वर्ष प्रतिवर्ष अपने ही विद्यालय के द्वारा स्थापित कीर्तिमानों को तोड़ रहें हैं। यह विद्यालय के शिक्षकों की कुशल मार्गदर्शन और छात्रों की कड़ी मेहनत से हीं सम्भव हो पा रहा है। शहर के निजामदीपुर स्थित ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल के आशका कुमारी ने 98.4 अंक प्राप्त कर जिले के सेकेंड टॉपर होने का गौरव प्राप्त किया है। ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल के निदेशक निर्मला शर्मा व प्रिंसिपल श्रीमती रंजना ने संयुक्त रूप से मीडिया से बात करते हुए बताया कि विद्यालय के छात्र बार-बार विद्यालय को गौरवान्वित कर रहें हैं। श्रीमती शर्मा ने बताया कि ब्रिलियंट शैक्षणिक ग्रुप केवल एक बच्चे को लेकर नही चलता बल्कि सभी बच्चों पर समान दृष्टिकोण रखता है,परतु जो बच्चे शिक्षकों के कुशल मार्गदर्शन को शिरोधार्य कर कड़ी मेहनत करते हैं वे हीं समाज मे अपने प्रतिभा का लोहा मनवाते हैं। उन्होंने बताया कि विद्यालय का शतप्रतिशत रिजल्ट इसका प्रमाण है। वहीं शहर मुख्यालय के प्रतिभा नगर में स्थित प्रतिभा पल्लवन पब्लिक स्कूल का भी रिजल्ट काफी बेहतर रहा। इस विद्यालय के मोनी कुमारी ने 98.2 प्रतिशत अंक प्राप्त कर अपने विद्यालय में प्रथम रहीं, वहीं आदर्श आनन्द ने 97 प्रतिशत अंक प्राप्त कर विद्यालय में द्वितीत तथा 96 प्रतिशत अंक प्राप्त कर रिया शर्मा ने विद्यालय में तृतीय स्थान प्राप्त किया। मोनी कुमारी को जिले के दूसरे टॉपर होने का भी गौरव प्राप्त हुआ है। इस बात की जानकारी पीपी शैक्षणिक ग्रुप के चेयरमैन डॉ अभिराम शर्मा ने मीडिया को देते हुए कहा कि इस विद्यालय के बच्चों की सफलता ने एक बार फिर से विद्यालय की शैक्षिक गुणवत्ता पर मुहर लगा दी है।इस विद्यालय के चार दर्जन से ज्यादा बच्चों ने 90 प्रतिशत से ज्यादा अंक प्राप्त किया है। डॉ शर्मा ने बताया कि इस विद्यालय के दर्जन भर छात्रों ने जेईई मेन्स के एग्जाम में भी विद्यालय का परचम लहराया है।

अगर सीबीएसई 12 की भी बात करें तो जिले के सीबीएसई विद्यालय के बच्चों ने इसमें भी 97-98 प्रतिशत तक अंक प्राप्त कर अपने प्रतिभा का लोहा मनवाया है। जिले के दक्षिणी स्थित मानस इंटरनेशनल विद्यालय के हर्ष शर्मा 98 प्रतिशत अंक लाकर जिले का टॉपर होने का गौरव प्राप्त किया। मानस इंटरनेशनल शैक्षणिक ग्रुप के निदेशक प्रो अरुण कुमार सिन्हा ने बच्चों को बधाई देते हुए कहा कि मेहनत कभी बेकार नही जाती,वह रंग लाती हीं है। यह बच्चों का मेहनत हीं है कि किसी किसी विषयों में तो 99 से 100 प्रतिशत तक अंक प्राप्त किये हैं।श्री सिन्हा ने बताया कि गणित और भौतिकी जैसे विषयों में हमारे विद्यालय के बच्चे 99 प्रतिशत तक अंक प्राप्त किये हैं वहीं फिजिकल एडुकेशन और जीव बिज्ञान जैसे विषयों में शतप्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं। विद्यालय के प्रबंधक निशांत रंजन और प्रिंसिपल मृत्युंजय कुमार ने इस अवसर पर कहा की विद्यालय के छात्र हर्ष शर्मा ने 98 प्रतिशत तथा आदित्य रंजन 97.2 प्रतिशत,आदर्श चौधरी 96 प्रतिशत तथा प्रियंका कुमारी 93 प्रतिशत

तक अंक प्राप्त कर साबित कर दिया है कि ग्रामीण इलाके में भी प्रतिभा की कमी नही है जरूरत है उसे मार्गदर्शन और अवसर प्रदान करने की। उस कार्य को मानस विद्यालय बखूबी निर्वहन कर रहा है। शहर के बभना में स्थापित मानस विद्यालय के छात्रों ने भी 97.8 प्रतिशत तक अंक प्राप्त कर अपने विद्यालय की गुणवत्ता और अपने प्रतिभा का कीर्तिमान स्थापित किया। मयंक राज ने 97.8 प्रतिशत,आशुतोष शर्मा 97.8 प्रतिशत,नीलम कुमारी 96.17 प्रतिशत, इश्तियाक 96.17 प्रतिशत,आलोक 95.5 प्रतिशत तक अंक प्राप्त किया है।उक्त बातों की जानकारी विद्यालय के निदेशक अभिषेक आनन्द ने मीडिया को दी है। उन्होंने बताया कि विद्यालय के छात्र आशुतोष सामाजिक विज्ञान मे विज्ञान में शनि कुमार, अभिषेक आनन्द संस्कृत में तथा गणित में शत-प्रतिशत अंक प्राप्त किया है। वही वेंकटेश नगर में स्थित

प्रतिभा पल्लवन मेमोरियल विद्यालय के बच्चों ने भी शतप्रतिशत परीक्षा परिणाम प्राप्त कर विद्यालय का परचम लहराया है। विद्यालय के अभिषेक शर्मा 94.4 प्रतिशत,अभिजीत शर्मा 95 प्रतिशत,प्रिंस कुमार 94.6 प्रतिशत,शालू कुमारी 92.8 प्रतिशत विनीत कुमार 92.8 प्रतिशत अंक प्राप्त कर अपनी प्रतिभा तथा विद्यालय की गुणवत्ता का प्रमाण प्रस्तुत किया है। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक इंदु कश्यप ने सफल छात्रों को मिठाई खिलाकर उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।●

जिले ने मनाया 36वां स्थापना दिवस

पूरे जिले में रही कार्यक्रमों की धूम

● **नवीन कुमार रौशन**

जहानाबाद 1 अगस्त को अपना 36 वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर पूरी सप्ताह पूरे जिले में निजी से लेकर सरकारी संस्थानों में कार्यक्रमों की धूम रही। कहीं बृक्षारोपण किये गए तो कहीं प्रभातफेरियां निकाली गई। कहीं निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की गई तो कहीं खेल।

जिले का मुख्य कार्यक्रम जिला मुख्यालय स्थित नगर भवन में सम्पन्न हुआ। जिसका विधिवत उद्घाटन द्वीप प्रज्वलित कर बिहार सरकार के अनसूचित जाति व जनजाति कल्याण तथा लघु जल संसाधन सह जिले के प्रभारी मंत्री सन्तोष कुमार सुमन जहानाबाद के राजद विधायक कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव घोषी के विधायक रामबली यादव, जिला परिषद अध्यक्ष रानी कुमारी, जिलाधिकारी रिची पाण्डे, पुलिस अधीक्षक दीपक रंजन, उपविकास आयुक्त परितोष कुमार तथा जिले के प्रशासनिक पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने पदाधिकारियों के साथ मिलकर ग्रैंड केक भी काटा। सृजन दिवस के इस मुख्य कार्यक्रम को स्थानीय तथा विद्यालय के कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा सृजन दिवस को जीवंत व यादगार बना दिया।

प्रभारी मंत्री ने इस अवसर पर लोगों को सम्बोधित करते हुए, जिलावासियों को,जिला सृजन दिवस की शुभकामनाएं दी तथा कहा कि अपने स्थापना काल से इस जिले ने कई उतार-चढ़ाव देखें हैं वावजूद प्रगति के पथ पर अग्रसर रहा है। आज जिले में शिक्षा, रोजगार सहित अन्य सभी क्षेत्रों में विकास देखा जा सकता है। सभी गांव तक पथ का निर्माण हुआ, जिले के बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे हैं और पदक प्राप्त कर जिले का नाम रौशन कर रहे हैं। महिलाओं को जीविका की सहायता से अपने जीवन स्तर को सुधारने का अवसर प्राप्त हो रहा है। उन्होंने जिलावासियों से एक अच्छा नागरिक बनकर आगे बढ़ने का अपील किया साथ ही जिले में चल रहे, जल-जीवन-हरियाली अभियान को सफल बनाने का आवाहन भी किया। जिला सृजन दिवस के अवसर पर जहानाबाद के विधायक सुदय यादव, घोषी के विधायक रामबली यादव जिला परिषद अध्यक्षा रानी कुमारी सहित अन्य जन-प्रतिनिधिगणों द्वारा भी जिलेवासियों को शुभकामनायें दिया गया तथा इसी प्रकार आगे

36 वर्षों बाद भी अपने बदहाली पर आँसू बहा रहा है जहानाबाद

किसी भी राज्य या जिले को उसके पुराने भौगोलिक परिदृश्य से काट कर एक नई भौगोलिक संरचना व पहचान दी जाती है कि उसका सामाजिक, शैक्षणिक आर्थिक, व ढाँचागत विकास तेजी से हो सके। लेकिन 36 वर्षों का प्रौढ़ जिला होने के बाद भी, अगर हम दूसरे जिलों से इसकी तुलना करें तो जहानाबाद का विकास जितनी तेजी से और जितना होना चाहिए था, वह अभी भी नही हो सका है। 1986 में जहानाबाद मगध प्रमंडल की मुख्यालय गया जिला से कट कर एक अलग व स्वतंत्र जिले के रूप में स्थापित हुआ। प्रारम्भ से ही मगध के इस जिले की राजनैतिक पृष्ठभूमि उर्वरा रही है। यहाँ के राजनीतिज्ञ प्रारम्भ से ही देश व समाज को दशा व दिशा देने का काम करते रहें है। रामाश्रय प्रसाद सिंह, किंग महेंद्र, रामाश्रय प्रसाद यादव जैसे राजनीति के राजनैतिक पुरोधाओं का सम्बंध इस जिले से रहा है। बाद में डॉ अरुण कुमार, डॉ सुरेंद्र प्रसाद यादव, डॉ जगदीश शर्मा, जीतन राम मांझी, कृष्णनन्दन वर्मा जैसे राजनीतिज्ञों ने भी इस जिले का नेतृत्व किया है। जीतन राम मांझी तो इस जिले के विधायक के रूप में बिहार के मुख्यमंत्री भी रहें हैं। वावजूद यह जिला अपने बदहाली और यहाँ के युवा अपनी बेरोजगरी पर आँसू बहाने को मजबूर है। अगर यहाँ के शिक्षाविदों की पहल और प्रयास से प्रारम्भिक एकेडमिक शैक्षणिक ढाँचागत विकास की बात छोड़ दें तो न ही यहाँ से सम्बन्ध रखने वाले किसी मंत्री या सांसदों ने बिजली, पानी, सड़क और जल जमाव जैसे जिले की बुनियादी समस्याओं को हीं हल कर सके हैं और न हीं मुख्यमंत्री रहते हुए जीतनराम मांझी ने जिले में कोई बड़ा सा उद्योग या तकनीकी संस्थान हीं स्थापित करा सके। जिससे जिले के लोगों की वेरोजगारी दूर हो और जिले की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो सके। ऐसा नही है कि इन राजनीतिज्ञों का ध्यान जिले के लोगों ने अपनी बुनियादी जरूरतों और सार्वजनिक विकास की ओर नही दिलाया है। जहानाबाद डेवेलपमेंट कमिटी ने जिले की बुनियादी समस्याओं पर स्थानीय जनप्रतिनिधि से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक ध्यान आकृष्ट करवाने का प्रयास किया है। लेकिन दुर्भाग्य है इस जिले का कि अपने को राजनीति के पुरोधा साबित करने का प्रयास करते रहने वाले ये राजनेता अपने आप को विकास पुरुष के रूप में स्थापित करने में असफल रहें हैं। शहर के बीचोबीच राजाबाजार रेलवे अंडर पास पर जब चिलचिलाती जेठ की दुपहरी में बिलबिलाते छोटे छोटे स्कूली बच्चे जाम में फँसे दिखते हैं तो विकास की सारी पोल खुल कर रह जाती हैं। उस समय इन नेताओं द्वारा जिले में गिनाये जाने वाले विकास की उपलब्धियां धरी की धरी रह जाती है जब जाम में फंसे किसी बीमार को अस्पताल ले जाते हुए एम्बुलेंस की सायरन और उसमें परिजनों का बिलाप जाम को चिर कर भरसक आगे बढ़ने का प्रयास करते देखा जाता है। लेकिन एसी में रहने वाले उन नेताओं का इस से क्या..? यह जिले का दुर्भाग्य कहा जाए या इन राजनीतिज्ञों का, कि प्राकृतिक सुषमाओं से आच्छादित 'वाणावर' जैसे ऐतिहासिक घरोहर को राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन स्थल के रूप में पहचान दिला पाने में भी असफल रहें हैं। ऐसा नही है कि जिले की यह स्थापना दिवस पहली बार मनाई जा रही है। सृजन दिवस मनाने की यह परंपरा अनेक वर्षों से चली आ रही है। जिसमें जिले के उपरोक्त सभी राजनीतिक नेता कभी सांसद के रुप में तो कोई सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में सृजन दिवस के कार्यक्रमों में शामिल हो कर जिले वासियों को जिले की सृजन की बधाइयाँ देते रहें हैं। बस नही दिया तो जिले को समुचित विकास जिसकी तुलना इसके साथ या इसके समकक्ष बनें जिले से करने पर हम जिले वासियों को अपने नेताओं पर गर्व महसूस करा सके। ऐसे में जरूरत है हमारे जिले के नेताओं को हमारे जिले की स्थापना काल से महज 10 -12 वर्ष पूर्व में स्थापित औरंगाबाद और नवादा जिले में हुए विकास से सिख लेने की। तुलना करें तो इन जिलों की सर्वांगीण विकास के समक्ष हमारे जिले का विकास नगण्य है। औरंगाबाद का औद्योगीकरण व उच्च शिक्षा के लिए स्थापित संस्थायें जहानाबाद ही नही बल्कि पूरे मगध को मुँह चिढ़ा रही हैं।

बढ़ते रहने की कामना की गई। जिला सृजन दिवस पर जिले के शिक्षा, जीविका, कृषि, आईसीडीएस, स्वास्थ्य, डीआरडीए, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मद्य निषेध, पीएचईडी आदि विभागों द्वारा सरकार के कल्याणकारी योजनाओं से सम्बंधित स्टॉल लगा जिले में सरकार की चल रही कल्याणकारी योजनाओं से जिलेवासियों को अवगत कराया गया।स्वच्छ जहानाबाद, समृद्ध जहानाबाद के नारे के साथ स्वच्छता अभियान को जनमानस में संचारित करने के उद्देश्य से गुब्बारा उड़ाये गए। जिलाधिकारी रिची पांडे ने शहर के सड़कों पर उतर कर झाड़ू लगा जिले वासियों को स्वच्छता के प्रति एक सन्देश देने का प्रयास किया। इस अवसर पर जिले के योग्य लाभुकों के बीच भूमि संबंधित पर्चा वितरण, खेल के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित भी किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर भारोत्तोलन में स्वर्ण जीतने वाले श्री भोला सिंह एवं रग्बी

प्रतियोगिता में स्वर्ण जीतने वाली सुश्री सलोनी कुमारी को सम्मानित किया गया। राज्य स्तर पर जहानाबाद जिले का प्रतिनिधित्व कर एथलेटिक्स, हैंडबॉल, भारोत्तोलन और बैडमिंटन में जीतने वाले खिलाड़ियों को भी प्रशस्ति पत्र दी गई।शिक्षा के क्षेत्र में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक एवं इंटर परीक्षा में सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को भी पुरस्कृत किया। रंगोली प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आने वाले विद्यालय एवं आंगनबाड़ी सेविका व सहायिकाओं की टीम को भी पुरस्कृत किया गया। कोविड-19 टीकाकरण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ए०एन०एम०तथा सहायिका व परिवार नियोजन में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, काको को भी पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर उद्योग विभाग द्वारा महिला उद्यमी योजना के अंतर्गत नये उद्योग स्थापित करने के लिए 29 महिला उद्यमियों को चार-चार लाख रुपये सहित कुल 11,600,000/- रुपए का ऋण दिया गया

है।

जिला सृजन दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी रिची पाण्डेय ने जिलेवासियों को शुभकामना देते हुए कहा कि हम सभी पर्यावरण का अभिन्न अंग हैं। हमारे कृत्यों से पर्यावरण प्रभावित होते हैं और हम पर्यावरण के प्रभावित होने से। इस लिए शुद्ध और स्वस्थ्य वातावरण में जीवन निर्वहन के लिए पर्यावरण का संरक्षण आवश्यक है।और पर्यावरण का संरक्षण जल-जीवन-हरियाली अभियान जैसे महत्वकांक्षी योजनाओं से हीं सम्भव हो सकता है। जिलापदधिकारी ने कहा कि समाज मे गिर रहे नैतिक मूल्यों के कारण समाज का सामाजिक पतन हो रहा है। सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन हेतु सरकार व प्रसासन द्वारा समाज सुधार अभियान चलाया जा रहा है। इसका सफल क्रियान्वयन जिलेवासियों के सहयोग के बिना अधूरी है। अत: हर जिलावासियों से मैं जिले के स्थापना दिवस के अवसर पर आह्वान करना चाहूंगा कि समाज निर्माण और पर्यावरण संरक्षण में अपनी दायित्वों को समझें और अपने जिले के विकास में महती भूमिका निभायें। यह जिले के स्वर्णिम भविष्य के निर्माण के लिए समय की माँग भी है और जरूरत भी है। जिलाधिकारी रिची पाण्डे ने इस अवसर पर सांस्कृतिक कर्यक्रम में प्रथम द्वितीय व तृतीय स्थान पाने वाले कलाकारों व संस्थानों को पुरस्कृत भी किया। कस्तूरबा गाँधी विद्यालय टेहटा को प्रथम,एन.बी.किड्स स्कूल जहानाबाद को द्वितीत तथा श्वेता एण्ड ग्रुप जहानाबाद को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। ●

अभी कलम उठाइये

आपके सामने हो रहे भ्रष्टाचार एवं अपराध की खबर की समीक्षा करें और सरकार सहित पुलिस-प्रशासन तक उसको पहुंचाने के लिए केवल सच पत्रिका के साथ जुड़े। खबर की जानकारी इस नम्बर पर दें

सम्पर्क करें:- 9431073769/9955077308

ई-मेल:- editor.kstimes@rediffmail.com पर भेजें।

प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल के अंकित 12वीं और शुभम 10वीं में रह अनुमंडल टॉपर

● श्रीकान्त कुमार श्रीवास्तव

मसौढ़ी बरनी रोड स्थित प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल के छात्र-छात्राओं ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का परचम लहराकर C.B.S.E. 12वीं एव 10वीं की परीक्षा में अपनी श्रेष्ठता को बनाए रखा है। पी.पी. शैक्षणिक समूह के चेयरमैन डा. अभिराम सिंह ने बताया कि विद्यालय के शिक्षकों के मेहनत एवं विद्यार्थियों के संघर्ष का यह नतीजा है कि इस विद्यालय का रिजल्ट शत-प्रतिशत रहा। विद्यालय के प्रतिभाशाली छात्र अंकित कुमार ने 96.20% अंक लाकर इस विद्यालय का ही नहीं अपितु मसौढ़ी का सर फक्र से ऊँचा कर दिया है। 12वीं में अंकित कुमार के साथ ही 93. 2% अंक के साथ डब्लू कुमार द्वितीय तथा नेहा भारती एवं अनामिका कुमारी ने 93% के साथ संयुक्त रूप से तृतीय स्थान पर रहें। दूसरी ओर 10वीं में शुभम कुमार ने अपने ही विद्यालय के पूर्व के रिकार्ड को तोड़ते हुए 98.2% अंक प्राप्त करके मसौढ़ी अनुमण्डल में सर्वोच्च स्थान पर रहे। अतुल कुमार एवं मोहित राज 97.8% अंक के साथ द्वितीय तथा नेहा भारती 96.6% अंक के साथ तृतीय स्थान पर रहे। इस मौके पर उपस्थित पी.पी. पब्लिक स्कूल के अकैडमिक डायरेक्टर सुप्रतिम चौधरी ने हर्ष व्यति करते हुए कहा है कि विगत कई वर्षो से इस विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने जिले में अपने प्रदर्शन से अलग पहचान बनाई है। यह विद्यालय परिवार एवं विद्यार्थियों के कर्मठता का परिणाम है कि 36 से ज्यादा बच्चों ने 90% से ज्यादा अंक प्राप्त किया। वहीं 40 से अधिक छात्र-छात्राओं ने 80% से अधिक अंक प्राप्त किया है। श्री चौधरी ने शिक्षकों एवं छात्र-छात्राओं को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविय की कामना करते हुए कहा कि विद्यालय परिवार अपने विद्यार्थियों के सुनहरे भविष्य को लेकर दृढ़ संकल्पित है। पी.पी. पब्लिक स्कूल के टॉपर्स को मंत्री गिरिराज सिंह ने किया सम्मानित। पटना के होटल मौर्या में सोमवार को आयोजित ग्राम संसद बिहार चैप्टर-2 कार्यक्रम में स्थानीय बरनी स्थित प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल के मेधावी छात्रों को CBSE की 10 वीं एवं 12 वीं परीक्षा में बेहतर अंक लाने के लिए मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा सम्मानित किए जाने से पूरे इलाके में खुशी की लहर है। पी.पी. शैक्षाकि समूह के एम. डी. अक्षय आनंद ने बताया कि इस बार CBSE की परीक्षा में उनके विद्यालय के छात्र शुभम कुमार ने 10 वीं में 98.2% एवं 12वीं में अंकित कुमार ने 96.2% अंक प्राप्त करके अनुमंडल मसौढ़ी में टॉपर रहे हैं। इसी को लेकर विद्यालय के इन बच्चों को केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह व सूबे के मंत्री सम्राट चौधारी के द्वारा सम्मानित किया गया है। ●

लिपिक को पटना डीएम ने किया निलंबित

● श्रीकान्त कुमार श्रीवास्तव

पालीगंज अनुमंडल कार्यालय के लिपिक सह नाजीर को पटना जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने बीते शनिवार को निलंबित कर दिया। अनुमंडल कार्यालय और भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता को लंबित वाद का निपटारा करने का निर्देश दिया। पालीगंज में नव निर्मित अनुमंडलीय अस्पताल को कार्यशील नहीं किए जाने पर अस्पताल अधीक्षक को फटकार लगाया। जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह शनिवार को अनुमंडल कार्यालय के निरीक्षण के दौरान बिना सूचना के गायब लिपिक सह नाजीर जितेन्द्र सिंह को निलंबित कर दिया। निरीक्षण के दौरान 1.71 करोड़ से अधिक राशि का उपयोग नहीं होने पर सरकारी खजाने में वापस करना चाहिए था। वित्तीय अनुशासन का पालन नहीं करने पर नाजिर जितेन्द्र सिंह के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए प्रपत्र क गठित करने और जिला लेखा पदाधिकारी को पूरे मामले की जांच करने का निर्देश दिया। अनुमंडल में लोक शिकायत, भूमि विवाद, दाखिल-खारिज सहित अन्य मामले की जानकारी ली। बताया गया कि लोक शिकायत के 192 मामले लंबित हैं जिसे समय पर निपटारा का निर्देश दिया। भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता स्तर पर भूमि विववा के 42, दाखिल-खारिज के 12 और लगान से संबंधित 11 मामले लंबित पाया गया। पालीगंज में 15.3 करोड़ की लागत से अनुमंडलीय अस्पताल का भवन निर्माण कराया गया है। अस्पताल के नए भवन का उद्घाटन 10 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। अब तक नए भवन का उपयोग नहीं किए जाने पर जिलाधिकारी डॉ. चन्द्रशेखर सिंह ने बीते शनिवर को उपाधीक्षक डॉ. आभा रानी से 24 घंटे में स्पष्टीकरण का जवाब मांगा है। डी.एम. ने 30 अगस्त तक नए भवन में चिकित्सा सेवा शुरू करने का निर्देश दिया है। डी.एम. ने लापरवाही और अनुशासनहीनता के खिलाफ कार्रवाई के लिए अनुशंसा करने की चेतावनी दी है। डी.एम. के आदेश पर तत्काल प्रभाव से उपाधीक्षक का वेतन भुगतान रोक दिया गया है। डी.एम. ने 30 अगस्त तक अस्पताल के साथ ए. एन.एम. प्रशिक्षण संस्थान को चालू कराने का निर्देश दिया। बाद में अनुमंडलीय न्यायालय और उप-कारा का निरीक्षण किया। डी.एम. ने कहा कि सितंबर तक दानापुर मंडल कारा पालीगज में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ●

सड़क पर लूटपाट करने वाले गिरफ्तार

● श्रीकान्त कुमार श्रीवास्तव

मसौढ़ी व धनरूआ में 35 दिन के अंदर सड़क लूट की तीन अलग-अलग घटनाएं करने वाले गिरोह के आठ अपराधियों को ए. एस.पी. वैभव शर्मा के नेतृत्व में गठित टीम ने दबोच लिया। इनके अलावा लूट का माल खरीदने वाले एक और आरोपित को दबोचा गया है। आरोपितों के पास से कट्टा व कारतूस और आठ दो पहिया वाहन, 11 मोबाइल व 66 सौ नकदी भी बरामद की। इसकी जानकारी शनिवार को सिटी एस.पी. पूर्वी प्रमोद कुमार यादव ने दी। उन्होंने बताया कि 3 अगस्त की रात धनरूआ के मोरियावां के पास दो युवकों से स्कूटी, सोने की चेन, मोबाइल व पर्स लूट की घटनाएं हुई थी। 28 जुलाई को धनरूआ के भखरी के पास दंपती से आभूषण और नकदी लूटी गई थी। वहीं 15 जुलाई की रात मसौढ़ी के सरवां रेलवे गुमटी के पास बाइक सवार युवक व उसके महिला रिश्तेदार से भी गहने लूटे गए थे। सिटी एस.पी. ने बताया कि मोरियावां के पास हुई लूट की घटना की सूचना पर पुलिस ने बदमासों का पीछा किया तो पभेड़ा स्थित पुलिया के पास वे लूटी गई स्कूटी व बाइक छोड़कर फरार हो गए थे। एस.एस.पी. व सिटी एस.पी. के निर्देशन में गठित टीम ने गुप्त सूचना पर धनरूआ थाना के रेड़गिहा के सोनू कुमार को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के आधार पर गौरीचक थाना के बेलदारीचक में ज्वेलरी दुकान के मालिक व मसौढ़ी के कैलूचक निवासी चंदन कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया। वह लूटे गए आभूषा खरीदता था। गिरफ्तार अन्य आरोपितों में मसौढ़ी के कैलूचक के सुनील कुमार उर्फ भिंडा और सोनू कुमार धनरूआ थाना के रेड़िबिगहा के मंटूश कुमार, पभेड़ी मोड़ के अविनेश कुमार, मंझौली के अजीत कुमार, गौरीचक के साहेबनगर के रविकांत, पटना चिरैयाटांड के विकास कुमार शामिल हैं। हालांकि गिरोज के एक सदस्य रेड़बिगहा का साहिल कुमार फिलहाल फरार बताया जा रहा है। सिटी एस.पी. ने बताया कि यह नया गिरोह है जो राहगीरों के साथ डकैती व लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देता है। गिरफ्तार करने वाली टीम में मसौढ़ी थानाध्यक्ष दीनानाथ सिंह, दारोगा विकास कुमार और पुनपुन थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार शामिल थे। राहगीरों से लूटपाट करने वाले गिरोह का सरगना सोनू कुमार और अमित कुमार बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार आरोपितों से एस.एस.पी. डा. मानवजीत सिंह ढिल्लो ने धनरूआ व मसौढी थाने में पूछताछ की। एस.एस.पी. के साथ सिटी एस.पी. पूर्वी प्रमोद कुमार यादव भी थे। ●

अभी कलम उठाइये

आपके सामने हो रहे भ्रष्टाचार एवं अपराध की खबर की समीक्षा करें और सरकार सहित पुलिस-प्रशासन तक उसको पहुंचाने के लिए केवल सच पत्रिका के साथ जुड़े। खबर की जानकारी इस नम्बर पर दें

सम्पर्क करें:- 9431073769/8340360961

ई-मेल:- editor.kstimes@rediffmail.com पर भेजें।